RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107
समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053
विशेष संपादक
मुकेश कुमार सिंह
सहायक संपादक
कोमल सुल्तानिया
राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337
संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433
राजनीतिक ब्यूरो
अमरेंद्र शर्मा 9899360011
प्रभाकर कुमार राय
प्रबंधक
अविनाश कुमार 8287266244
विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह 9546224277
क्राइम ब्यूरो
एसएन श्याम
मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार
जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334114515
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति, रंजीत कुमार
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 8, अंक : 10, जून 2021, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

10 और अब गायकी में धमाकेदार इंट्री कर रही हैं भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी...

बच्चों के इलाज के अनुसार ... 05

पठनीयता के संकट के बीच ... 07

अनाथ बच्चों को पालने ... 22

अंधविश्वास और वैज्ञानिक ... 18

जमीनी हकीकत के अनुरूप उठायें कदम

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

शीर्ष अदालत ने देश में वैक्सीन नीति से जुड़ी विसंगतियों और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से सख्त लहजे में सवाल पूछे और तल्ख टिप्पणियां कीं। ये सवाल वैक्सीन की खरीद, वैक्सीन की उपलब्धता और इसके लिये पंजीकरण से जुड़ी दिक्कतों से भी जुड़े थे। दरअसल, अदालत कोरोना मरीजों की दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीन से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है। तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एस. रवींद्र भट्ट और एल. नागेश्वर राव शामिल थे। बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत ने कड़े सवाल किये। बेंच ने कहा कि केंद्र सस्ते दाम में वैक्सीन खरीद रही है और राज्यों व निजी चिकित्सालयों के लिए कंपनियां कीमत तय कर रही हैं। ऐसा क्यों है? वैक्सीन खरीदने के लिये राज्य ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, क्या यह केंद्र की पॉलिसी का हिस्सा है? बेंच ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया की दुहाई देती है, जबकि देश में गरीबी व निरक्षरता के चलते श्रमिक वर्ग कैसे कोविन एप पर पंजीकरण करा सकेगा? अदालत का मानना था कि देश में टीके की कीमत में एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सही-गलत का निर्धारण सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। जनसरोकारों से जुड़े विषयों में अदालत को हस्तक्षेप करने के पूरे अधिकार हैं। सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहने पर कि यह नीतिगत मामला है और कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित हैं, कोर्ट ने दो टूक कहा कि हम आपसे नीति बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। लोगों को सरकार की नीति से परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने माना कि महामारी का संकट बड़ा है और हाल ही में विदेश मंत्री अमेरिका आवश्यक चीजों के लिये गये थे, लेकिन सरकार को अपनी कमियां भी स्वीकारनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि यह सुनवाई सरकार को असहज करने के लिए नहीं है, कमजोरी स्वीकारना मजबूती की निशानी भी होती है। दरअसल, शीर्ष अदालत की बेंच केंद्र सरकार से टीका नीति की वास्तविक स्थिति जानना चाहती है। न्याय मित्र जयदीप गुप्ता ने टीका नीति की विसंगतियों की ओर अदालत का ध्यान खींचते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को टीका खरीद का करार करने को कहा है लेकिन एक तो विदेशी टीका निमार्ता कंपनियां राज्यों से करार नहीं करना चाहतीं, वहीं हर राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह महंगी वैक्सीन जुटाने में सक्षम हो। हालांकि, टीके के दामों के बाबत पूछे जाने पर सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि यदि हम टीकों के दामों से जुड़ी जांच की ओर बढ़ेंगे तो इससे टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित होगा। कोर्ट का मानना था कि देश की संघीय व्यवस्था के तहत बेहतर होता कि केंद्र वैक्सीन खरीद कर राज्यों को देता। लेकिन केंद्र राज्यों को अनिश्चय की स्थिति में नहीं छोड़ सकता। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि उसे ज्यादा टीके खरीदने के कारण कम कीमत पर टीका मिला है। अदालत द्वारा तीसरी लहर की चुनौती में ग्रामीण क्षेत्रों व बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका को लेकर पूछे गये सवाल पर केंद्र की ओर जवाब दिया गया कि सरकार ने गंभीर विचार-विमर्श के बाद टीकाकरण नीति का निर्धारण किया है। यदि इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो सरकार सही दिशा में बदलाव को तत्पर रहेगी। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि देश में टीका उत्पादन की क्षमता के अनुरूप क्या साल के अंत तक टीकाकरण के लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे? इस पर केंद्र के प्रतिनिधि का कहना था कि टीकों की उपलब्धता के आधार पर ही लक्ष्य तय किये गये हैं। निस्संदेह शीर्ष अदालत ने देश के जनमानस को उद्वेलित कर रहे सवालों का ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण चाहा है ताकि जनता में किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति न बने। निस्संदेह जनमानस की आशंकाओं का निराकरण जरूरी है।

कोरोना के आगे विश्वास रखें सब अच्छा होगा

आतिश कुमार झा

वर्तमान समय बड़े मुश्किलों का है। इस तरह की आपदा के बारे मे संभवतः हम मे से किसी ने कल्पना भी नही की थी। फिल्मों व उपन्यासों की बात छोड़ दिया जाए तो यह चीन जनित मानव आपदा कोरोना हमारे देश ही नही मानव जाति की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आई है जिसके समक्ष वर्तमान मे हम असहाय है। विज्ञान के नए आविष्कारों पर चढ़ कर मंगल और चंद्रमा तक यात्रा करने की क्षमता रखते हुए भी हम एक अति सूक्ष्म अदृश्य विषाणु के प्रकोप के आगे स्वयं को किंकर्तव्यविमूढ़ वाली स्थिति में मान नतमस्तक हो चुके हैं। कोरोना वाईरस ने जहां राष्ट्र व समाज को आर्थिक क्षति पहुंचाई उससे कहीं अधिक सामाजिक सांस्कृतिक व पारिवारिक क्षति किया है। इस बीमारी ने मानवीय संवेदनाओं व संबंधों को तार-तार कर दिया। ऐसा नहीं कि मानवीय संवेदनाएं हमसे हमारे अंतस से समाप्त हो गई वरन स्वयं के प्राणरक्षा के भय ने इन संवेदनाओं की भ्रूणहत्या कर दी। संबंधों के तराजू पर स्वयं के प्राणों के आगे दूसरे पलड़े पर संवेदना का कोई वजन कोई मूल्य चाह कर भी नहीं रहने दिया।

जब वर्ष भर पहले कोरोना की पहली लहर आई थी तब यह मानवीय संवेदनाएं बेबसी में खुद को कसमसाते हुए इस आशा और उम्मीद से जी रही थी कि यह बुरा वक्त है चला जाएगा देश की जनता सरकार के प्रत्येक कदम में सहयोग की भावना के साथ कभी ताली बजाने से लेकर शंख घड़ियाल बजाती रही, कभी कोरोना से जूझ रहे फ्रण्टलाईन वारियर्स डाक्टर्स, पैरामेडिकल्स, पुलिस वालो का हौसला बढ़ाने के लिये दीपक जला कर उनका हौसला बढ़ाती रही। मनोवैज्ञानिक व सामरिक दृष्टि से देखें तो इसका लाभ भी हमें मिला। एक डेढ़ माह के कंप्लीट लॉकडाउन ने हमारे देश को कोरोना से लड़ने की प्राथमिक तैयारी का मौका दिया। मास्क से लेकर सैनिटाइजर, वेंटीलेटर जैसी जरूरी चीजों को तैयार कर हम कोरोना से लड़ने मैदान में आ गए तो सरकार ने आम गरीब जनता के राशन पानी तक की व्यवस्था की। पुलिस का संवेदनशील व सहयोगात्मक व्यवहार आम जन ने पहली बार महसूस किया। कोरोना वाईरस से इस पहली लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ उतरने का लाभ यह रहा कि हम कोरोना के पहले युद्ध में विजयी हुए। हमारे लड़ने के ढंग से लेकर मनोवैज्ञानिक सामरिकी तक की तारीफ पूरी दुनिया ने किया। इस मुश्किल वक्त मे एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला कर जहां हमने एक दूसरे के बिखरे बिछड़े साथियों को ढूंढ़ना शुरू किया जहां हमने जमीन पर

करोना को हराया वही अपने अंशदान से पीएम केयर्स फंड को समृद्ध किया। कोरोना के आपदा काल में शारीरिक और भौतिक दूरियां काफी होने के बावजूद हमने एक दूसरे के बिखरे बिछुड़े साथियों को ढूंढ़ ढूंढ कर एक माला में पिरोने का काम बड़े करीने से किया। स्कूली जमाने के दोस्तों से लेकर विश्वविद्यालय और संघर्ष के दिनों के बिखरे हुये साथी एक एक कर प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और फेसबुक व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर कई कई ग्रुप बन गए। इन सोशल मीडिया ग्रुप ने केवल आभासी स्तर पर नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर भी आपस में एक समझदारी व साझेदारी कायम किया। आपसी संबंध भौतिक रूप से दूर रहने के बावजूद मन से जुड़ते गये, जिंदगी फिर वैसे ही चलने लगी जैसे कोरोना के पहले चलती थी। सरकार लगायत वैश्विक संगठन हमें बार-बार चेतावनी देते रहे पर हम फिर अपने रंग में रंग गए ह्यहम न मरब मरिहै संसाराह्ल के तर्ज पर ।

भूल तो यही हो गई जो हमने काशी के गूढ़वादी फक्कड़ अलमस्त कबीर के ह्यहम न मरब मरिहै संसाराह्ल का अर्थ न समझ खुद को ही स्वयं संप्रभु मान बैठे। हमने यह नहीं सोचा, एक क्षण के लिए भी नहीं कि हम अपने अंदर के ह्यअहंह्ल का प्रतीक है और यदि हमने अपने ह्यहमह्ल अर्थात ह्यअहंकारह्ल को नहीं मारा तो हम अपने ह्यजियावनहाराह्ल अर्थात परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। यह परमात्मा ही कल्याणकारी हमारा सुख है हमारी शांति है हमारी संतुष्टि है। परंतु हमने करोना के बाद अपने अहंकार को बस में नहीं किया , दिशानिर्देश नही माने, संकल्पबद्ध नही किये। मास्क सावधानी भीड़ सब को अनदेखा कर दिया हमने तो हमारे अहंकार को मारने प्रकृत को आना ही था। परिणाम सामने है आज करोना कि दूसरी लहर के आगे हम असहाय हैं। जिस भारत की पूरे विश्व में कोरोनावायरस के लिए प्रशंसा हो रही थी आज वही अपनी गलतियों से संपूर्ण विश्व का दयापात्र बना हुआ है। गलती कहां हुई? यह आत्मआलोचना व आत्मनिरीक्षण का विषय है पर कड़ुआ सच यह है कि हम में से कोई भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।चाहे वह प्रधानमंत्री हो या प्रधान सचिव ग्राम प्रधान हो या गांव के पटवारी। वास्तविकता यह है कि हम सब ने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी लापरवाही प्रदर्शित किया है।आज बंगाल तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम के विधानसभा चुनाव के लिए न्यायपालिका हाई कोर्ट मद्रास चुनाव आयोग को हत्या जैसे अपराध का दोषी बताती है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट पंचायत चुनाव पर उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रैल के आखिरी तारीख तक अनिवार्य रूप से चुनाव कराने का आदेश देकर स्वयं को साफ पाक कैसे कह सकती है?

वही देश के सर्वोच्च जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सहित बड़े-बड़े राजनेताओं द्वारा की जाने वाली चुनाव रैलियों में ह्यदो गज की दूरी मास्क है जरूरीह्ल का सिद्धांत चुनावी प्रचार पार्टियों मे चुनावी पम्फलेट की तरह उड़ता नजर आया। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार कोरोना की सुनामी को झेलने के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पाँच सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने के निदेर्शों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले आए और हमारा सर्वोच्च न्यायालय दूसरे प्रदेशों में हो रही घोर लापरवाही प्राणवायु और अस्पतालों में पेड़ों और श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए तीन-तीन दिनों से

लाइन में लगे लोगों के सहूलियत के लिए कड़ी टिप्पणी जारी करने के बावजूद उच्च न्यायालय के निर्देश को स्थगित कर दें तो आमजन अपने अपनों की सेवा चिकित्सा और प्राण रक्षा के लिए कहां जाएं ? जनता की दृष्टि मे इस कागजी कवायद ने न्यायपालिका पर भी मूकप्रश्न उठाया है। बार-बार चिकित्सा सेवा और सुविधाओं के विस्तारीकरण की आवश्यकता और आवश्यक धनराशि होने के बावजूद हमारे सर्वशक्तिमान सत्तानियंता व अधिकारीगण पूरे साल में 1000 वेंटिलेटर और हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा पाए तो दूसरों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश देने वाले न्यायालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अनुपालन हुआ यह किसी से छिपा नहीं है फिर आम जनता तो नियम कानून ना मानने को अपना जन्मसिद्ध मूल अधिकार ही मानती है उसके लिए ह्य2 गज की दूरी मास्क है जरूरीह्ल सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें ही बेमानी थी। कुल मिला जुला कर अगर हम पूरे कोरोना सुनामी के दूसरे लहर के लिए किसी पर उंगली उठाने की स्थिति में है तो वह शीश महल में पत्थर फेंक कर उसके किरिचों मे खुद का बिगड़ता चेहरा देखने वाली बात होगी।

परन्तु कोरोना का जो सर्वाधिक दुखद पहलू है आपसी संवेदनाओं और संबंधों की तिलांजलि। कोरोनावायरस आज के समय में अश्पृश्य जैसे हो गए जहां पुत्र पिता की, व्यक्ति अपने निकटतम परिजनों की अंत्येष्टि भी नहीं कर पाया। छोटी-छोटी घटनाओं पर एक दूसरे से कंधा मिलाने वाले लोग आज मृत्यु जैसे संस्कारों पर भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। आपदा मे अवसर के नाम पर मानव गिद्धों ने दो रुपए की दवायें बीस रुपए और 899/- का रेमडेसिवर ७५ हजार एक लाख मे बेंचने से बाज नही आये। अस्पतालों ने कोरोना के नाम पर बिना किसी सुविधा के १५००/- वाले बेड पर डेढ़ लाख रुपए तक वसूला तो लाशों को कंधा देने के नाम पर दस कदम तक लाश पहुंचाने के आठ से सोलह हजार , एंबुलेंस के किराये दो दो लाख रुपए तक वसूले गये। नकली दवा इंजेक्सन डाक्टर ड्राईवर एंबुलेंस की तो बात ही छोड़ दिजिये। किस मानसिक आर्थिक आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ रहा है हमारा भारतीय समाज? कैसे बचा जाय इन मानव गिद्धों से यह प्रश्न तो सदैव खड़ा रहेगा।

हम निराशाजनक और नकारात्मक पहलू को छोड़ दें तो हर व्यक्ति मन से एक दूसरे के पीड़ा में शरीक हैं यदि वह भौतिक रूप से अपनों के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो यह उसकी मर्जी या मनोदशा नहीं है वरन आज की दुर्गम परिस्थितियां हैं। मैं फेसबुक व्हाट्सएप और अखबारों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम देखता हूं कि इस आपदा काल में अपनी आवास से ही मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दें तो सोचता हूं यह विनम्र निवेदन है या सूचना की औपचारिकता?कभी हमने ऐसे परिवेश और परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी पर जो सच हमारे सामने हैं हम उसे अस्वीकार नही कर सकते । आज हमें उसमें ही स्वयं को समायोजित करने के अतिरिक्त कोई पर्याय भी नहीं है । आवश्यकता परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से लेने की है। माल्थस ने कहा था प्रकृति अपने आवश्यकतानुसार जनसंख्या को नियंत्रित करती है संभवत यह प्रकृति का ही स्व नियंत्रण हो, पर प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया भी है उसका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कभी-कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर उस पर चहचहाती चिड़ियों की आवाज सुनिए और पेड़ के पत्तों से बहते हुए सनसनाहट को महसूस करिए तब आपको पता चलेगा की प्रकृति ने हमें कितनी प्यारी चीजें दी है। कभी किसी तालाब के किनारे चुपचाप बैठ उसमें भागती उछलती मछलियों को देखिए और उन पर ध्यान लगाए बगूले की एकाग्रता को महसूस कीजिए तब पता चलेगा कि संसार में कोरोनावायरस केअतिरिक्त भी बहुत कुछ है जोअच्छा है बस उसे देखने की जरूरत है। जीवन की आपाधापी में हमने उसके लिए दो पल का वक्त ही नहीं निकाला । कुछ नहीं तो घर के बाहर एक छोटे खुले डिब्बे में चिड़ियों के लिए पानी रखकर गमले में खुद के लगाए पौधे को ध्यान से देखिए तब लगेगा कि जीवन बहुत खुशनुमा है और कोरोनावायरस कुछ भी नही बल्कि इससे हट के जिन्दगी बहुत कुछ है जिसे जीना है महसूस करना है आनंद लेना है।

बच्चों के इलाज के अनुसार करना होगा चिकित्सा क्षेत्र को तैयार !

कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर ने भारत में शहर से लेकर गांव तक जमकर तांडव मचाया है। इस लहर ने भारत में उपलब्ध चिकित्सा क्षेत्र को ध्वस्त करके रख दिया है। हाल के दिनों की कठिन परिस्थितियों ने देश में चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। हमारे देश के नीतिनिमार्ताओं को आज के इस हालात से सबक लेकर भविष्य के लिए चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में असमय काल का ग्रास बने लोगों की जलती चिताओं ने अधिकांश देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है, वो भविष्य में अब इस तरह की आपाधापी वाली भयावह स्थिति को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। देश-विदेश के कोरोना विशेषज्ञ भी भारत में भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचाव के लिए हालात का लगातार गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन देश में जिस तरह से वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर में वायरस ने बुजुर्गों को अपना ज्यादा शिकार बनाया था, वहीं वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी ताकतवर लहर जो देश में अभी चल रही है वह युवाओं को अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रही है, वायरस के इस व्यवहार को देखकर कोरोना विशेषज्ञ इस की तीसरी लहर आने का आशंका व्यक्त करते हुए उसमें बच्चों को इसका अधिक शिकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं। वह सरकार व सिस्टम को इस तरह के हालात उत्पन्न होने पर उसे निपटने के लिए तैयारी करने के लिए लगातार चेता रहे है।

वैसे भी कुछ दिन पहले मई माह में ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ह्लके. विजय राघवनह्व ने कहा था कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैला हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि तीसरी लहर कब और किस स्तर की होगी, लेकिन हमें बीमारी की नई लहरों के लिए तैयारी करनी चाहिए।

भारत में कोरोना के मामलों को नजदीक से देख रहे विशेषज्ञों में से अधिकतर का मानना है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर इसी वर्ष 2021 के सितंबर के बाद शायद आ सकती है। इसके लिये कोरोना वायरस में होते तेजी से म्यूटेशन जिम्मेदार हैं, म्यूटेशन का अर्थ वायरस में होने वाला बदलाव होता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुनिया में इस घातक कोरोना महामारी की शुरूआत से अभी तक इस जानलेवा वायरस

के कई म्यूटेशन सामने आए हैं। इनमें से कुछ म्यूटेशन तो लोगों के जीवन के लिए बेहद घातक साबित हुए हैं, जैसे की आजकल ह्लबी.1.617ह्व स्ट्रैन ने अपना कहर बरपा रखा है। कोरोना वायरस के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता को देखते हुए ही विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर हमारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों पर होगा। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की हमारे देश में आबादी 32 करोड़ के लगभग है। वैसे भी हमारे देश में अभी 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कोई भी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण का देश में हमारे बच्चे सबसे आसान शिकार बन सकते हैं।

हालांकि संतोष देने वाली बात यह है कि सोमवार को बच्चों पर तीसरी लहर के संभावित प्रभाव पर एक सवाल का जवाब देते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोविड-19 की आगामी लहर में बच्चों में काफी संक्रमण फैलेगा या उनमें ज्यादा मामले आएंगे इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनके अनुसार पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चे सामान्य तौर पर कोविड-19 से सुरक्षित हैं और अगर उनमें संक्रमण हो भी रहा है तो यह मामूली है।

वैसे तीसरी लहर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आये ही नहीं और विशेषज्ञों के साथ-साथ अन्य लोगों के भी आकलन गलत साबित हो जायें, देश व समाज के लिए यह सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी देश को समय रहते बच्चों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए ठोस कदम धरातल पर जल्द से जल्द दूसरी लहर से लड़ते हुए ही उठाने होंगे। कोरोना की पहली लहर के बाद हमारे देश के चंद जिम्मेदार पदों पर बैठे राजनेताओं व सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों ने दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी के बारे में जो बड़ी-बड़ी बातें की थी, अब उन सब बातों की पोल खुल चुकी है, समय रहते बचाव के लिए सही ढंग से प्रभावी कदम ना उठाये जाने की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाते हुए सभी चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोलखोल कर रख दी है। इसलिए हमारे देश के कर्ताधर्ता व सिस्टम को कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए समय रहते धरातल पर कार्य करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में अगर संक्रमण बड़े पैमाने पर बच्चों में होने लगा, तो आज के हालात में देश में बच्चों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक पुख्ता इंतजाम उपलब्ध नहीं हैं।

वैसे भी हाल के दिनों में उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, मई माह के मात्र 15 दिनों में लगभग 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गये हैं, राज्य में लगभग 5 हजार से अधिक बच्चे अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं राजस्थान के दो जनपदों में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी को चिंतित कर दिया है, दौसा में एक मई से 21 मई के तक 18 साल से कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर डूंगरपुर में भी बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, डूंगरपुर में 12 मई

से 22 मई तक 255 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश से भी चिंतित करने वाली खबरें आ रही है सागर जिले में पिछले 1 माह में लगभग 302 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं। देश में अलग-अलग जगहों पर बच्चों में कोरोना जैसे हलके-फुलके लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं।

इसलिए समय रहते ही तीसरी लहर से निपटने के लिए हमकों यह मानकर दिनरात काम करना होगा कि कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए नये सिरे से देश में बच्चों के लिए चिकित्सा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर तैयार करना है, समय रहते सिस्टम को बच्चों के इलाज से जुड़े जटिल मसलों के समाधान करने के बारे में मौजूदा परिस्थितियों में ही सोच कर उसका निदान करना होगा, क्योंकि अगर बच्चों में भविष्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए धरातल पर बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, उनका निदान समय रहते जल्द से जल्द करना बेहद आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संदर्भ में देश के शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों एवं नवजातों को बचाने के लिए तैयारियां तेज करनी चाहिए।

वैसे भी देश में मौजूदा समय में बच्चों के इलाज लिए शहर-शहर अलग से कोविड़ अस्पताल तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है, बेहतर परिणाम के लिए उनको सभी प्रकार के आधुनिक चिकित्सा संसाधनों युक्त एनआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स, स्पेशल पीडियाट्रिक केअर यूनिट, वेन्टीलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, दवाई व इंजेक्शन आदि से युक्त करना बेहद आवश्यक है। अभी की स्थिति में बच्चों के इलाज के लिए हमारे देश में ह्लचाइल्ड स्पेशलिस्टह्व डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की संख्या बहुत कम है, उसके के निदान के लिए बड़े पैमाने पर अन्य डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को समय रहते बच्चों के इलाज के हिसाब से प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक होगा, भविष्य में विकट से विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए सरकार को बच्चों के इलाज करने के लिए डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करके बड़े पैमाने पर स्टैंडबाई रखने की तैयारी करनी होगी, जो देश में कहीं भी हालात खराब होने पर उस क्षेत्र में जाकर युद्धस्तर पर इलाज की व्यवस्था तुरंत शुरू कर सकें। देश के कर्ताधर्ता व सिस्टम में बैठे सभी ताकतवर लोगों को यह समझना होगा कि बच्चे परिवार के साथ देश का उज्जवल भविष्य होते हैं, इसलिए उनसे जुड़े किसी भी मसले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे से बचाने के लिए हमें समय रहते हर संभव कदम उठाने होंगे। बच्चों के इलाज से संबंधित एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि बड़ों का इलाज तो कोविड़ अस्पताल में अकेले हो जाता है, लेकिन बच्चों के इलाज के मामले में उसके साथ एक एटेंडेंट का रहना आवश्यक होगा, सिस्टम के सामने बच्चे को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने की चुनौती के साथ-साथ उसके एटेंडेंट को कोरोना संक्रमण से बचाएं रखने की बड़ी चुनौती होगी, उसके लिए सरकार को बच्चों के युवा अभिभावकों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द दोनों डोज के साथ टीकाकरण करना होगा। बच्चों के हित में सरकार के सामने कुछ महीनों में करोड़ों की संख्या में युवा अभिभावकों को टीका लगा कर उन्हें सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार को यह भी तैयारी करनी होगी की बच्चों की समय पर कोरोना जांच होने में कोई समस्या ना हो, टेस्ट की रिपोर्ट जल्द मिल जाये, जिससे उनका इलाज समय रहते शुरू हो जाये और संक्रमण का स्तर खतरनाक लेवल पर ना पहुंच पाये। उनके लिए ऑक्सीजन कम ना पड़े, दवाई व इंजेक्शनों की कोई कमी ना रहे, कालाबाजारी करने वाले दानवों को लूटखसोट करने का मौका ना मिल पाये। बच्चों के इलाज के हिसाब से अभी से ही दवाई व इंजेक्शनों आदि जरूरतमंद आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाये। खैर कुछ भी हो कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर की तरह आपधापी व मारामारी वाले हालात से अब देश को बचाते हुए सरकार व सिस्टम को तीसरी लहर से बच्चों के साथ-साथ सभी को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम समय रहते उठाने चाहिए, ब्लैक फंगस के बच्चों में संभावित खतरे पर भी अभी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता अब किसी भी हाल में अपनों के खोने के जख्मों को झेलने की परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए समय रहते हर प्रकार के संभावित खतरे से लड़ने की युद्धस्तर पर तैयारी देश व समाज के हित में बेहद जरूरी है।

पठनीयता के संकट के बीच खुद को बदल रहे हैं अखबार

कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर ने भारत में शहर से लेकर गांव तक जमकर तांडव मचाया है। इस लहर ने भारत में उपलब्ध चिकित्सा क्षेत्र को ध्वस्त करके रख दिया है। हाल के दिनों की कठिन परिस्थितियों ने देश में चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। हमारे देश के नीतिनिमार्ताओं को आज के इस हालात से सबक लेकर भविष्य के लिए चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में असमय काल का ग्रास बने लोगों की जलती चिताओं ने अधिकांश देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है, वो भविष्य में अब इस तरह की आपाधापी वाली भयावह स्थिति को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। देश-विदेश के कोरोना विशेषज्ञ भी भारत में भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचाव के लिए हालात का लगातार गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन देश में जिस तरह से वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर में वायरस ने बुजुर्गों को अपना ज्यादा शिकार बनाया था, वहीं वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी ताकतवर लहर जो देश में अभी चल रही है वह युवाओं को अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रही है, वायरस के इस व्यवहार को देखकर कोरोना विशेषज्ञ इस की तीसरी लहर आने का आशंका व्यक्त करते हुए उसमें बच्चों को इसका अधिक शिकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं। वह सरकार व सिस्टम को इस तरह के हालात उत्पन्न होने पर उसे निपटने के लिए तैयारी करने के लिए लगातार चेता रहे है।

वैसे भी कुछ दिन पहले मई माह में ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ह्लके. विजय राघवनह्व ने कहा था कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैला हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि तीसरी लहर कब और किस स्तर की होगी, लेकिन हमें बीमारी की नई लहरों के लिए तैयारी करनी चाहिए।

भारत में कोरोना के मामलों को नजदीक से देख रहे विशेषज्ञों में से अधिकतर का मानना है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर इसी वर्ष 2021 के सितंबर के बाद शायद आ सकती है। इसके लिये कोरोना वायरस में होते तेजी से म्यूटेशन जिम्मेदार हैं, म्यूटेशन का अर्थ वायरस में होने वाला बदलाव होता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुनिया में इस घातक कोरोना महामारी की शुरूआत से अभी तक इस जानलेवा वायरस

के कई म्यूटेशन सामने आए हैं। इनमें से कुछ म्यूटेशन तो लोगों के जीवन के लिए बेहद घातक साबित हुए हैं, जैसे की आजकल ह्लबी.1.617ह्व स्ट्रैन ने अपना कहर बरपा रखा है। कोरोना वायरस के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता को देखते हुए ही विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर हमारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों पर होगा। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की हमारे देश में आबादी 32 करोड़ के लगभग है। वैसे भी हमारे देश में अभी 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए कोई भी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण का देश में हमारे बच्चे सबसे आसान शिकार बन सकते हैं।

हालांकि संतोष देने वाली बात यह है कि सोमवार को बच्चों पर तीसरी लहर के संभावित प्रभाव पर एक सवाल का जवाब देते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोविड-19 की आगामी लहर में बच्चों में काफी संक्रमण फैलेगा या उनमें ज्यादा मामले आएंगे इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनके अनुसार पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चे सामान्य तौर पर कोविड-19 से सुरक्षित हैं और अगर उनमें संक्रमण हो भी रहा है तो यह मामूली है।

वैसे तीसरी लहर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आये ही नहीं और विशेषज्ञों के साथ-साथ अन्य लोगों के भी आकलन गलत साबित हो जायें, देश व समाज के लिए यह सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी देश को समय रहते बच्चों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए ठोस कदम धरातल पर जल्द से जल्द दूसरी लहर से लड़ते हुए ही उठाने होंगे। कोरोना की पहली लहर के बाद हमारे देश के चंद जिम्मेदार पदों पर बैठे राजनेताओं व सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों ने दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी के बारे में जो बड़ी-बड़ी बातें की थी, अब उन सब बातों की पोल खुल चुकी है, समय रहते बचाव के लिए सही ढंग से प्रभावी कदम ना उठाये जाने की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाते हुए सभी चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोलखोल कर रख दी है। इसलिए हमारे देश के कर्ताधर्ता व सिस्टम को कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए समय रहते धरातल पर कार्य करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में अगर संक्रमण बड़े पैमाने पर बच्चों में होने लगा, तो आज के हालात में देश में बच्चों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक पुख्ता इंतजाम उपलब्ध नहीं हैं।

वैसे भी हाल के दिनों में उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, मई माह के मात्र 15 दिनों में लगभग 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गये हैं, राज्य में लगभग 5 हजार से अधिक बच्चे अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं राजस्थान के दो जनपदों में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी को चिंतित कर दिया है, दौसा में एक मई से 21 मई के तक 18 साल से कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर डूंगरपुर में भी बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, डूंगरपुर में 12 मई

से 22 मई तक 255 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश से भी चिंतित करने वाली खबरें आ रही है सागर जिले में पिछले 1 माह में लगभग 302 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं। देश में अलग-अलग जगहों पर बच्चों में कोरोना जैसे हलके-फुलके लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं।

इसलिए समय रहते ही तीसरी लहर से निपटने के लिए हमकों यह मानकर दिनरात काम करना होगा कि कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए नये सिरे से देश में बच्चों के लिए चिकित्सा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर तैयार करना है, समय रहते सिस्टम को बच्चों के इलाज से जुड़े जटिल मसलों के समाधान करने के बारे में मौजूदा परिस्थितियों में ही सोच कर उसका निदान करना होगा, क्योंकि अगर बच्चों में भविष्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए धरातल पर बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, उनका निदान समय रहते जल्द से जल्द करना बेहद आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संदर्भ में देश के शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों एवं नवजातों को बचाने के लिए तैयारियां तेज करनी चाहिए।

वैसे भी देश में मौजूदा समय में बच्चों के इलाज लिए शहर-शहर अलग से कोविड़ अस्पताल तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है, बेहतर परिणाम के लिए उनको सभी प्रकार के आधुनिक चिकित्सा संसाधनों युक्त एनआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स, स्पेशल पीडियाट्रिक केअर यूनिट, वेन्टीलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, दवाई व इंजेक्शन आदि से युक्त करना बेहद आवश्यक है। अभी की स्थिति में बच्चों के इलाज के लिए हमारे देश में ह्लचाइल्ड स्पेशलिस्टह्व डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की संख्या बहुत कम है, उसके के निदान के लिए बड़े पैमाने पर अन्य डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को समय रहते बच्चों के इलाज के हिसाब से प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक होगा, भविष्य में विकट से विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए सरकार को बच्चों के इलाज करने के लिए डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करके बड़े पैमाने पर स्टैंडबाई रखने की तैयारी करनी होगी, जो देश में कहीं भी हालात खराब होने पर उस क्षेत्र में जाकर युद्धस्तर पर इलाज की व्यवस्था तुरंत शुरू कर सकें। देश के कर्ताधर्ता व सिस्टम में बैठे सभी ताकतवर लोगों को यह समझना होगा कि बच्चे परिवार के साथ देश का उज्जवल भविष्य होते हैं, इसलिए उनसे जुड़े किसी भी मसले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे से बचाने के लिए हमें समय रहते हर संभव कदम उठाने होंगे। बच्चों के इलाज से संबंधित एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि बड़ों का इलाज तो कोविड़ अस्पताल में अकेले हो जाता है, लेकिन बच्चों के इलाज के मामले में उसके साथ एक एटेंडेंट का रहना आवश्यक होगा, सिस्टम के सामने बच्चे को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने की चुनौती के साथ-साथ उसके एटेंडेंट को कोरोना संक्रमण से बचाएं रखने की बड़ी चुनौती होगी, उसके लिए सरकार को बच्चों के युवा अभिभावकों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द दोनों डोज के साथ टीकाकरण करना होगा। बच्चों के हित में सरकार के सामने कुछ महीनों में करोड़ों की संख्या में युवा अभिभावकों को टीका लगा कर उन्हें सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार को यह भी तैयारी करनी होगी की बच्चों की समय पर कोरोना जांच होने में कोई समस्या ना हो, टेस्ट की रिपोर्ट जल्द मिल जाये, जिससे उनका इलाज समय रहते शुरू हो जाये और संक्रमण का स्तर खतरनाक लेवल पर ना पहुंच पाये। उनके लिए ऑक्सीजन कम ना पड़े, दवाई व इंजेक्शनों की कोई कमी ना रहे, कालाबाजारी करने वाले दानवों को लूटखसोट करने का मौका ना मिल पाये। बच्चों के इलाज के हिसाब से अभी से ही दवाई व इंजेक्शनों आदि जरूरतमंद आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाये। खैर कुछ भी हो कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर की तरह आपधापी व मारामारी वाले हालात से अब देश को बचाते हुए सरकार व सिस्टम को तीसरी लहर से बच्चों के साथ-साथ सभी को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम समय रहते उठाने चाहिए, ब्लैक फंगस के बच्चों में संभावित खतरे पर भी अभी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता अब किसी भी हाल में अपनों के खोने के जख्मों को झेलने की परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए समय रहते हर प्रकार के संभावित खतरे से लड़ने की युद्धस्तर पर तैयारी देश व समाज के हित में बेहद जरूरी है।

वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर पर टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक

अनूप नारायण सिंह

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और ईमानदारी के लिए जिनकी वर्षों तक मिसाल दी जाएगी कलम के जादूगर सुरेंद्र किशोर जी के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजद के नेता श्याम रजक ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके बाद सोशल मीडिया पर श्याम रजक की जमकर खिंचाई हो रही है पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी के एक पोस्ट पर श्याम रजक ने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर के लिए चमचागिरी और चाटुकारिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। विवाद यही से प्रारंभ हुआ है। लंबे अरसे तक देश की पत्रकारिता में सक्रिय रहे व विगत कई वर्षों से कई सारे बड़े अखबारों के लिए वे नियमित लेखन करते हैं पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत कुर्जी मोहम्मदपुर गांव के पास एक छोटे से घर में शांति पूर्वक जीवन बसर कर रहे सुरेंद्र किशोर से मिलने देश के दिग्गज लोग पहुंचते हैं सादगी के भी प्रतिक है सुरेंद्र किशोर।जो लोग बिहार की पत्रकारिता में है या देश के पत्रकारिता में है और प्रिंट से जिन का जुड़ाव रहा है उनके लिए भी सुरेंद्र किशोर एक मिसाल है जितना बड़ा कद है उतना ही सहज है सुलभ है शब्दों के जादूगर और उन्हें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कपूर्री ठाकुर जैसे बिहार में सामाजिक आंदोलन के पुरोधा मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे जब भी लिखते हैं तो बेबाक लिखते हैं, लिखते ही रहते हैं उनके बारे में शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट लिखा था जिस पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सोशल मीडिया पर श्याम रजक ट्रोल होने लगे हैं सुरेंद्र किशोर इतने आहत हुए है की उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपनी भावना का इजहार किया है बिहार की पत्रकारिता जगत में ही नहीं दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंची है हालांकि श्याम रजक से जब इस मुद्दे पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई उनसे संपर्क नहीं हो पाया उन्होंने सुरेन्द्र किशोर जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए इतने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया ऐसी क्या वेदना है जिससे उन्हें लगता है कि सुरेंद्र किशोर जैसे व्यक्ति किसी की चमचागिरी कर सकते हैं जितना बड़ा सुरेंद्र किशोर का कद है जिससे मुंह खोल दें कोई भी बड़ा राजनैतिक पद उन्हें तुरंत मिल सकता है पद्म पुरस्कारों के लिए बिहार पत्रकारिता से बड़ा नाम है,पर यह सिद्धांत वादी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे किसी पुरस्कारों की परिधि में बांध दिया जाए या कोई लाभ का पद दे दिया जाए या उसके नाम पर कोई दुकान चले उनके नाम पर कोई विवाद नहीं कर सकता जात पात से काफी दूर रहते हैं। एक पत्रकार और राजनेता का क्या संबंध होता है श्याम रजक अपने राजनीतिक करियर में इस बात को बेहतर जानते हैं बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक करना किसी के भी हित में नहीं होता है। श्याम रजक उसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक होते रहे है जहां सुरेंद्र किशोर जी ने अपना आवास बनाया है। बिहार की पत्रकारिता में जो नई सशक्त बुलंद पत्रकारों की टीम है उन्हें भी पुष्पित और पल्लवित सुरेंद्र किशोर जी ने ही किया है।

लंबे अरसे तक देश की पत्रकारिता में सक्रिय रहे व विगत कई वर्षों से कई सारे बड़े अखबारों के लिए वे नियमित लेखन करते हैं पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत कुर्जी मोहम्मदपुर गांव के पास एक छोटे से घर में शांति पूर्वक जीवन बसर कर रहे सुरेंद्र किशोर से मिलने देश के दिग्गज लोग पहुंचते हैं सादगी के भी प्रतिक है सुरेंद्र किशोर।जो लोग बिहार की पत्रकारिता में है या देश के पत्रकारिता में है और प्रिंट से जिन का जुड़ाव रहा है उनके लिए भी सुरेंद्र किशोर एक मिसाल है जितना बड़ा कद है उतना ही सहज है सुलभ है शब्दों के जादूगर और उन्हें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कपूर्री ठाकुर जैसे बिहार में सामाजिक आंदोलन के पुरोधा मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे जब भी लिखते हैं तो बेबाक लिखते हैं, लिखते ही रहते हैं उनके बारे में शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट लिखा था जिस पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है।

और अब गायकी में धमाकेदार इंट्री कर रही हैं भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी...

पटना।चार सौ से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री रानी चटर्जी का भोजपुरी गीत संगीत के क्षेत्र में बड़ा धमाका करने जा रही हैं रानी भोजपुरी के नवोदित गायक गोलू राज के साथ अपना नया एलबम ला रही है यह एलबम कई मायने में खास होगा जिसमें भोजपुरी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायक गोलू राज ने बताया कि अभी तक इस तरह का प्रयोग भोजपुरी में नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि भोजपुरी में सोहर झूमर छठ कांवर गीत पूर्वी निर्गुण बारामासा जैसे

गोलू ने बताया कि उनका यह एलबम रानी चटर्जी के साथ है।एक बड़े म्यूजिक कंपनी से जल्द ही यह रिलीज होगा उसकी शूटिंग पूरी कर ली गई है आज राजधानी पटना के विभिन्न लोकेशनो पर इस एलबम के गानों की शूटिंग की गई इसमें मुख्य भूमिका में रानी चटर्जी और गोलू राज ही नजर आएंगे।

पारंपरिक गीत है तो विवाह गीतों की एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे में कोई भी गायक इन पारंपरिक चीजों को छोड़कर जब अश्लीलता की तरफ की तरफ बढ़ते हैं तब भोजपुरी का मान मर्दन होता है। गोलू ने बताया कि उनका यह एलबम रानी चटर्जी के साथ है।एक बड़े म्यूजिक कंपनी से जल्द ही यह रिलीज होगा उसकी शूटिंग पूरी कर ली गई है आज राजधानी पटना के विभिन्न लोकेशनो पर इस एलबम के गानों की शूटिंग की गई इसमें मुख्य भूमिका में रानी चटर्जी और गोलू राज ही नजर आएंगे। अभिनेत्री रानी चटर्जी ने कहा कि भोजपुरी में प्रयोगवाद जरूरी है प्रयोगवाद के द्वारा ही भोजपुरी के गीत संगीत के स्तर को उठाया जा सकता है किसी भी व्यवस्था के खिलाफ केवल बोलना बेहतर नहीं इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि भोजपुरी उनकी बदौलत है पर ऐसा नहीं सभी लोग भोजपुरी के बदौलत है। रानी ने स्वीकार किया कि कलाकार वही करता है जो स्क्रिप्ट में शामिल होता है इसलिए कलाकार को निशाने पर नहीं लीजिए अगर बेहतरीन स्क्रिप्ट होगा और दर्शक ऐसी चीजों को देखेंगे तब ऐसी साफ-सुथरी चीजें तो बनेंगी ही। अपने नए भोजपुरी एल्बम को लेकर रानी काफी उत्साहित है उन्होंने कहा कि गोलू राज काफी प्रतिभा संपन्न है ही उससे बेहतर एक्टर हैं उनमें ढेर सारी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में भोजपुरी में एक बड़ा नाम बन कर उभरेंगे।

लॉकडाउन में बन्द स्कूल के बावजूद निजी विद्यालय द्वारा सम्पूर्ण फीस वसूली की संज्ञान ले राज्य सरकार : रजनीकांत पाठक

लॉक डाउन अवधि में स्कूल बंदी के दौरान निजी विद्यालय प्रशासन द्वारा मनमानी ढंग से वसूले जा रहे स्कूल फीस पर अंकुश लगाए जाने के सम्बंध में मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिख कर रजनीकांत पाठक ने मुख्यमंत्री बिहार से हस्तक्षेप की मांग की है।

सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत पाठक ने असंख्य स्कूली बच्चें के अभिभावक के दर्द को समझ कर आवाज उठाई है और हर हाल में फीस कटौती की मांग की है।उन्होंने मुख्यमंत्री के लिखे पत्र में मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है की , मार्च 2020 से राज्य व देश में वैश्विक महामारी करोना से उत्पन्न स्थिति के कारण सम्पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था । यहाँ यह भी गौरतलब हो कि, लॉक-ड़ाउन की अवधि में सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय सम्पूर्ण रूप से बंद रहे ।

ज्ञात हो कि इस बंद की अवधि के दौरान सभी निजी बड़े विद्यालयों द्वारा मनमानी ढंग से पूर्ण फीस वसूला गया है । यही नहीं जबकि चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में भी पटना के साथ - साथ अन्य ज़िलों में भी निजी विद्यालय द्वारा जबरन व मनमानी ढंग से पूरी फीस वसूली जा रही है । यहाँ यह भी आश्चर्य है की , जो सुविधाएँ निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को प्रदान नहीं किए जा रहे हैं उसका मासिक फीस भी खुल्लम - खुल्ला वसूला जा रहा है।

विदित हो कि फीस प्राप्ति रसीद में उल्लेखित विवरण के अनुसार जिस प्रकार फीस वसूला जा रहा है इससे निजी विद्यालय प्रशासन की मंशा ह्लआपदा में अवसर ह्ल की भावना को प्रकट करता है । कहने का तात्पर्य यह है की, जो सुविधा बच्चों को स्कूल जाने के बाद दिया जाता था स्कूल बंदी के दौरान भी वे सारे फीस बच्चों के अभिभावकों से वसूले जा रहे हैं । यह घोर अन्याय और कष्टकारी है ।

उदाहरण : स्कूल बंद के दौरान निम्नानुसार फीस वसूले जा रहे है -

1- ट्विसन फीस	- 6750
2- टर्म फीस	- 500
3- स्मार्ट क्लास फीस	- 300
4- डवलपमेंट फीस	- 1000
5- एक्टिविटी फीस	- 600
6- ई- केयर फीस	- 300
7- इग्जाम फीस	- 400
8- लाइब्रेरी फीस	- 150
9- कम्प्यूटर फीस	- 300
10- जेनरेटर चार्ज	- 200
11- बिल्डिंग मेंटेनेंस	- 1000
12- डायरी / कार्ड	- 200
13- स्टेबलिस्ट - 500	
14- जिम / खेल - 300	

इस प्रकार मनमाने ढंग से निजी विद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वसूलना कही से भी न्यायोचित नहीं है । जब स्कूल ही बन्द है तो इस प्रकार से मनमानी ढंग से फीस वसूलने क्या मतलब है ? क्या यह लूट नहीं ? आज असंख्य माता - पिता अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की चिंता के साथ साथ स्वयं के दैनिक जीवन - यापन यथा - रोजगार आदि से परेशान हैं । करोना जैसे महामारी और लम्बे समय से चले आ रहे लॉकदाऊन में मध्यम वर्ग को बहुत कमजोर कर चुका है । बिहार के माता पिता में सबसे बड़ी खासियत है कि वो खुद को दुखों में झोंककर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं । बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है । ऐसे स्थिति में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सामान्य जीवन यापन करने के साथ बच्चों की शैक्षणिक गतिविधि को जारी रखना चुनौतिपूर्ण है । मुख्यमंत्री जी , राज्य की जनता के लिए आप हमेशा मानवीय कर्तव्य को पूरा करते रहे हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि , बिहार के निजी विद्यालयों में स्कूल बंदी के दौरान लिए जा रहे मनमानी ढंग से फीस वसूलने पर रोक लगाते हुए बंदी के दौरान सिर्फ. ट्विसन फीस (वर्तमान में जो ड्ढल्ल'ल्ली पढ़ाया जा रहा है) लेने के लिए सख़्त निर्देश देने की कृपा करे ताकि राज्य के असंख्य माता - पिता को इस मनमानी ढंग से लिए जा रहे फीस के असहनीय बोझ से राहत मिले ।

लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव कर रही हैं लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित

आज तमाम नेता अभिनेता व सामाजिक लोग लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव पहली गायिका है जो कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों को गीतों के माध्यम से जागरूक कर रही हैं। " एह कोरोना से बचाई वैक्सीनेशन भैया-बहिनी ध्यान से सुनीर" इस बेहतरीन गीत को लिखा है सासाराम आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री संजय कुमार चतुवेर्दी जी ने। इस गीत के माध्यम से मनीषा लोगों को यह समझाना चाहती हैं कि इस कोरोना महामारी से वैक्सीनेशन ही बचाएगा।

फिलहाल कोरोना से बचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चाहे आपको को वैक्सिन पसंद हो या कोविशिल्ड, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराइए। इस कोरोना से अपनी जिंदगी बचाइए। गांव गांव में सरकार के लोग मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इस कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ मनीषा श्रीवास्तव एक से बढ़कर एक हिट लोकगीत दे रही हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

फिलहाल कोरोना से बचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चाहे आपको को वैक्सिन पसंद हो या कोविशिल्ड, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराइए। इस कोरोना से अपनी जिंदगी बचाइए। गांव गांव में सरकार के लोग मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इस कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ मनीषा श्रीवास्तव एक से बढ़कर एक हिट लोकगीत दे रही हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

संजय एवं मनीषा के लेखन गायन के इस जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले साल लॉकडाउन में संजय चतुवेर्दी जी ने मनीषा के मखमली आवाज के माध्यम से कुछ बेहद चुनिंदा एवं बेजोड़ रचनाओं को समाज को दिया था। संजय ने समय व हालात के अनुरुप कलम चलाया व मनीषा ने गाया। उन गीतों में समय के मारे मजदूरों का दर्द है या कोरोना वायरस से बचने का संदेश।

रघुवंशियों यदुवंशियों की गोलबंदी के सहारे राजद ने शुरू की सारण लोकसभा फतेह की तैयारी

अनूप नारायण सिंह

अभी भले ही लोकसभा चुनाव में विलंब है पर बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर रखी है सारण वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सांसद रहे हैं राजद के लिए यह सीट हमेशा मददगार रही है फिलहाल यहां से भाजपा के राजीव प्रताप रुढी सांसद हैं। राजीव प्रताप रूडी बड़े कद के नेता होने के बावजूद अपने ही दल में उपेक्षा के शिकार हैं वाजपेई सरकार और मोदी सरकार पार्ट वन में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे राजीव प्रताप रूडी का बेहतर रिकॉर्ड होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलना उनके समर्थकों वह जरूर मायूस करता है। सारण सीट पर यादव और राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। दोनों जातियों का अपना अपना वोट बैंक है चुनाव के समय जिस जाति का मामूली वोट बैंक भी दूसरी तरफ से होता है उस तरफ के प्रत्याशी जीत जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने यहां से चंद्रिका राय पर दांव लगाया था चंद्रिका राय को टिकट देने से लेकर चुनाव प्रचार तक में राजद के अंदर ही विरोध चल रहा था यह विरोध परिणाम में भी देखने को मिला तमाम कवायद के बावजूद चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए हालांकि उसके पहले के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं सोनपुर, गरखा सुरक्षित ,परसा ,अमनौर, मढ़ौरा और छपरा सदर। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर राजद का कब्जा है जिन 2 सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा वहा भी हार जीत का अंतर काफी कम रहा है। छपरा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव हारने वाले पूर्व विधायक रणधीर सिंह सारण के राजनीति के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं उनके साथ भितरघात हुआ वही अमनौर से चुनाव हारने वाले सुनील राय राजद के छपरा के जिला अध्यक्ष हैं। सुनील राय के साथ भी अंतिम समय में कैडर वोट बिखर गया। सारण की राजनीति में फिलहाल लोकसभा चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है कि अब लालू परिवार से इतर राजद स्थानीय स्तर पर चुनाव जीताऊ चेहरे की तलाश में लग गया है। बिस्कोमान के चेयरमैन राजद विधान पार्षद और पार्टी के बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष सोनपुर विधानसभा के डुमरी बुजुर्ग निवासी सुनील कुमार सिंह सारण लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकताओं से लेकर लोगों तक में पहली पसंद के रूप में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सुनील कुमार सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं पर सभी समाज के बीच में काफी लोकप्रिय हैं लालू परिवार से इनके काफी घनिष्ठ संबंध है राबड़ी देवी इनकी

मुंह बोली बहन है, बुरे वक्त में सुनील कुमार सिंह परिवार की सदस्य की भांति हर कदम नजर भी आते हैं इस कारण अगर सारण लोकसभा क्षेत्र से राजपूत बिरादरी के उम्मीदवार की चर्चा होती है तो सुनील कुमार सिंह अकेले दावेदार हैं। सुनील कुमार सिंह की कोरोना काल में पूरे सारण लोकसभा में सक्रियता भी भविष्य की राजनीति के बड़े बदलाव की तरफ संकेत करती है। दूसरी तरफ यादव समुदाय से मढ़ौरा से जीत का हैट्रिक लगाने वाले जितेंद्र राय सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं जितेंद्र राय के पिता यदुवंशी राय भी विधायक रहे जितेंद्र राय अपने चिकित्सक भाइयों के माध्यम से पूरे जिले के अंदर हेल्थ कैंप लगाकर लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं पार्टी में भी जितेंद्र राय गुड बुक में शामिल हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यादव समुदाय से आने वाले पार्टी के जिला अध्यक्ष व अमनौर से लगातार तीन बार कड़ी टक्कर देने वाले सुनील राय भी लोकसभा टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यादव समुदाय से आने वाले सोनपुर के विधायक डॉ रामानुज प्रसाद व हाल ही में पार्टी में शामिल होकर परसा से जीत का गिफ्ट देने वाले छोटे लाल राय भी लोकसभा टिकट के दावेदारों में शामिल है। जिला स्तर का कोई भी नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है पर जब तैयारियों के संदर्भ में पूछा जाता

है तो कहा जाता है कि जिस किसी को टिकट मिले इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी को हर मोर्चे पर घेरने के लिए राजद ने फुलप्रूफ रणनीति बना रखी है खामोश रहने वाले जिला स्तर के नेता भी अब मुखर हो गए हैं सोशल मीडिया व मेंस्ट्रीम मीडिया में अब खुलकर बोलने लगे हैं स्थानीय मुद्दों पर सांसद को घेरने लगे हैं। छपरा राजद जिला अध्यक्ष सुनील राय इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता की टिकट किसे मिलेगा पर जीत राजद की होगी इसकी हंड्रेड परसेंट गारंटी है।

भाजपा नेता अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में सोनपुर विस क्षेत्र में जारी है जन जागरूकता अभियान

आज उनके द्वारा सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के फुलवारी नगर राष्ट्रीय गंज दलित बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर तथा साबुन का वितरण किया गया इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम रंजन पटेल,जिला मंत्री श्वेता श्रीवास्तव, फुलवारी नगर मंडल अध्यक्ष रमेश यादव ने भी भाग लिया इस अवसर पर अभय कुमार सिंह ने कहा की पार्टी के द्वारा कोरोना जागरूकता सप्ताह के तहत मंडल अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकताओं के मदद से सोनपुर विधानसभा के गांव गांव में उनके द्वारा मास्क वितरण सैनिटाइजर और साबुन वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें कोरोना से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं अभी तक दर्जनों गांव में उनके द्वारा यह अभियान चलाया जा चुका है।

सोनपुर। कोरोना के कहर के बीच सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में लोगों के बीच मास्क सेनीटाइजर साबुन वितरण का कार्य अनवरत जारी है आज उनके द्वारा सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के फुलवारी नगर राष्ट्रीय गंज दलित बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर तथा साबुन का वितरण किया गया इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम रंजन पटेल,जिला मंत्री श्वेता श्रीवास्तव, फुलवारी नगर मंडल अध्यक्ष रमेश यादव ने भी भाग लिया इस अवसर पर अभय कुमार सिंह ने कहा की पार्टी के द्वारा कोरोना जागरूकता सप्ताह के तहत मंडल अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकताओं के मदद से सोनपुर विधानसभा के गांव गांव में उनके द्वारा मास्क वितरण सैनिटाइजर और साबुन वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें कोरोना से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं अभी तक दर्जनों गांव में उनके द्वारा यह अभियान चलाया जा चुका है लोगों का सहयोग मिल रहा है भीड़ भाड़ ना हो इस कारण से डोर टू डोर जाकर लोगों को मास्क व अन्य सहायता दी जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों से लोग काफी संतुष्ट है लेकिन इस महामारी से निजात पाने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा इसी क्रम में वह सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

तरैया में पप्पू यादव की रिहाई कम की मांग को लेकर जाप के प्रदेश सचिव संजय सिंह के नेतृत्व में निकला विरोध जुलूस

छपरा। छपरा जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र मे जाप के प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में जाप कार्यकताओं ने लोग न्याय मार्च निकाला जिसमें पप्पू यादव की रिहाई के साथ ही साथ बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार जनविरोधी है लोगों की मौतें हो रही हैं बाढ़ की समस्या है भूख है गरीबी है जो लोगों की सेवा कर रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं राजनीतिक कार्यकताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है पप्पू यादव जैसे जनप्रिय लोगों को बेवजह जेल में डाला जा रहा है हर अन्याय के खिलाफ जाप का जन आंदोलन जारी रहेगा। तरैया में भी जाप कार्यकताओं ने ह्यलोक न्याय मार्चह्न निकाला। इस दौरान कार्यकताओं ने अस्पतालों की बदहाली, सभी बंद पड़े स्वास्थ्य व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य

सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने, राशन कार्ड से वंचित लोगों को अविलंब राशन कार्ड उपलब्ध कराने, कोरोनारोधी वैक्सीन पंचायत स्तर पर लोगों को दिए जाने, बिजली बिल माफ करने, कोरोना मृतकों को अविलंब मुआवजा सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

भारत की अखंडता-संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है विदेशी सोशल मीडिया

विदेशी सोशल कम्पनी ह्लट्विटरह्ल और वॉटसएप का कुछ वर्ष पूर्व ठीक वैसे ही हिन्दुस्तान में पर्दापण हुआ था, जैसे कभी ह्लईस्ट इंडिया कम्पनीह्ल के नाम पर अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में पधारे थे।ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी थीं एलिजाबेथ प्रथम थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी,बात एशिया में कारोबार की होती जरूर थी,लेकिन कम्पनी की नजर सिर्फ और सिर्फ हिन्दुस्तान पर टिकी हुई थी। कम्पनी के पीछे के इरादों को कोई भांप नहीं पाया था। इसी के चलते यह कंपनी कारोबार करते-करते ही भारत में सरकार बनाने की साजिश तक में कामयाब हो गई। उसकी इस साजिश को अमलीजामा पहनाने वालों में कुछ हिन्दुस्तानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देश की हालत यह थी कि भारतवासी चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिंस ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि इस कंपनी की आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। कम्पनी का भारत की इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे आज की चीजों का असर और दखल रहता था। जैसे आज कंपनियां अपने फायदे के लिए हुक्मरानों-नेताओं ही नहीं अपने ही देश के खिलाफ षड़यंत्र रचने वालों के बीच भी कम्पनी लॉबीइंग करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर में ऐसी शख्सियतों से से नजदीकी रखती थी। नेताओं-राजाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी रहती थी। इसका भी मुख्यालय आज के गूगल, फेसबुक, टिव्टर-वॉटस एप जैसी कंपनियों के शानदार दफ्तरों जैसा होता था।जरूरत पड़ने पर यह कम्पनियां देश को दंगों की आग में झोंकने से भी नहीं चूकती है। चुनाव के समय ऐसे नेताओं और दलों को प्रचार-प्रसर में बढ़ावा देती हैं जिनके माध्यम से कम्पनी के हित सधते हैं।य वह नेता होता हैं जो कभी अमेरिका से प्रकाशित ह्लन्यूयार्क टाइम्सह्ल में छपी खबर के आधार पर देश को विदेश में बदनाम करते हैं तो कभी देश को नीचा दिखाने के लिए चीन-पाकिस्तान से गलबहिया कर लेते हैं।

इस्ट इंडिया कम्पनी की तरह की आज टिव्टर एवं वॉटस एप कम्पनिया भी भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए केन्द्र सरकार पर आंखे तरेर रही हैं। हालांकि अब समय बदल गया है,तब देश पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी, आज की ह्लईस्ट इंडिया कम्पनियांह्ल देश के बाजार पर कब्जा करने की होड़ में लगी हैं,इसी लिए वह अपनी पंसद की सियासत चलाने में लगी हैं ताकि उनको फायदा पहुंचाने वाले नेता सत्ता के करीब पहुंच जाए। इसके पीछे भी अपने देश की ही कुछ सियासी शक्तियां और लिबरल गैंग के लोग काम कर रहे हैं। अमेरिकी कम्पनियां भी व्यापार करते-करते हम भारतीयों को बताने लगी हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होता है।देश का संविधान हम नहीं, यह कम्पनियां तय करेंगी। किसकी पोस्ट हटाना-लगाना या सोशल मीडिया के एकांउट को सीज करना है और किसको आगे बढ़ाना है यह तय करने का अधिकार भी यह कम्पनियां अपने पास रखती है। इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। यह देश में आग लगाने वाली पोस्ट डालने वालों का नाम हमें-आपको तो क्या सरकार को भी नहीं बताएंगीं क्योंकि इनकी नजर में देश में आग लगाना भी अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसी देशद्रोही ताकतों को पकड़वाने में सरकार की मदद करने की बजाए यह उनके बारे में जानकारी छिपाने का भी काम करती है। जबकि देश तोड़ने की सोचने वालों के खिलाफ मुंह खोलने वालों को एकाउंट बन कर देने की धमकी दी जाती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए देशद्रोही ताकतों से अपने पक्ष में बयान जारी कराए जाते हैं। टिव्टर और वॉटस एप अपनी मुहिम को ठीकठाक चलाते रहते यदि 2014 में मोदी की आंधी नहीं आई होती। मोदी के आने से इनकी उम्मीदो पर पानी फिरना शुरू हुआ तो इस सोशल मीडिया की कम्पनी ने साजिशें रचना शुरू कर दीं। ऐसे लोगों को बढ़ाया जाने लगा जो मोदी विरोधी बयान देते थे। मुसलमानों पर अत्याचार की फर्जी खबरें फैलाते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों का साथ देते हैं।

याद कीजिए वह दौर जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के रूख और चैतरफा कूटनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान ने अपने विंग कमांडर अभिनंदन को 56 घंटों में ही सही सलामत भारत को वापिस कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपगैंडा मशीन ने इसे शांति के संदेश के तौर पर पेश करना शुरू किया। इसके बाद तो इंडिया में बैठे लिबरल ग्रुप ने तुरंत इसको इमरान खान का मास्टर-स्ट्रोक, इमरान खान द ग्रेट, इमरान फॉर पीस, गुडविल जेस्चर टाइप कैंपेन शुरू दिया। इमरान खान की शान में खूब कसीदे गढ़े गये। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चैधरी ने नेशनल एसेंबली में एक प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारतीय नेताओं द्वारा शुरू किये गये युद्धोन्माद के बाद भारत-पाकिस्तान के युद्ध को टालने के लिए इमरान खान ने एक संत की तरह रोल अदा किया है, जिसकी भारत में भी सराहना हो रही है। अतः इमरान खान को इसके चलते नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है। इस मुहिम को चलाने में सोशल मीडिया ने बढ़-चढ़कर प्रचार-प्रसार का काम किया था। टिव्टर हो या फिर वॉटस एप या अन्य कोई साइड्स। इसको हम-आप भले ही मैसेज आर एक-दूसरे से जुड़ रहने का ह्लहथियारह्व मानते हों,लेकिन कुछ लोगों के लिए यह साइड्स देश तोड़ने का साधन बन गया है। तमाम देश विरोधी प्रचार-प्रसार किया जाता है।कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जैसे तमाम लोगों के लिए न तो देश अहमियत रखता है और न ही आपदा. उन्हें बस अवसर की तलाश रहती है। यह अवसर उन्हे सोशल मीडिया ही बेधड़क बिना रोकटोक के उपलब्ध कराता है। राहुल के बारे में कौन नहीं जानता है कि राहुल की सिर्फ राजनीति ही नहीं. उनका एजेंडा भी हमेशा संदिग्ध होता है। इस हद तक कि उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध लगने लगती है, जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने विदेशी वैक्सीन के भारत में आयात की लॉबिंग की, उससे ज्यादा बेशर्मी से वह स्वदेशी वैक्सीन के मूल्य निर्धारण पर राजनीति कर रहे हैं, ये वही राहुल और उनकी टीम है जिसने स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविड-शील्ड को लेकर बखेड़ा खड़ा किया था। लोगों की जान से खिलवाड़ बताया था। यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोवैक्सीन की बेकद्री हुई और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो इसे इस्तेमाल करने पर ही रोक लगा दी थी। सवाल बहुत साफ और महत्वपूर्ण है. कि हमेशा देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नीति-निर्धारक हमेशा भारत विरोधी और विदेशी लॉबी के पक्ष में खड़े हो जाते है। यह दृश्य हमने चीन के साथ टकराव में देखा, ये हमने पुलवामा में देखा, ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, ये राफेल की खरीद में देखा.। आखिर कहां से जुड़े हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग और राहुल के हित. क्योंकि उनकी हरकतें तो बताती हैं कि कम से कम भारत के विकास और कल्याण में तो वह बाधक ही हैं।अब तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस तक द्वारा देश को बदनाम करने के लिए टूलकिट का सहारा लिया जाने लगा है। इसी को लेकर जब मोदी सरकार ने टिव्टर ओर वॉटसएप सोशल साइट्स पर शिकंजा कसा तो टूलकिट बनाने वाले का नाम बताने की बजाए यह कम्पनी सरकार को संविधान की याद दिलाने लगी। झूठा प्रोपोगंडा करने लगी कि उसे पुलिस से धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर ताजा विवाद चल रहा है। बहरहाल, मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह झुकने वाली नहीं है। लंबे अरसे से भारतीय कानूनों को नजरअंदाज कर रहे इंटरनेट मीडिया को अब रास्ते पर आना ही होगा। वाट्सएप के बाद सरकार ने ट्विटर को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय भारत के कानून का पालन करे। सरकार ने कहा कि ट्विटर अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत की छवि को धक्का पहुंचाना चाहती है। ट्विटर सिर्फ एक इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरीज है और उसे भारत के वैधानिक फ्रेमवर्क में दखलअंदाजी का कोई हक नहीं है। ट्विटर ग्राहकों की आजादी पर भी मनमाना ब्रेक लगाती है और भारत के साथ पक्षपात भी करती है। अपने ग्राहकों का डाटा व्यापारिक हित साधने के लिए निजी कम्पनियों को दे देती है। सरकार के पास कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ट्विटर-वाटसएस आदि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्मो से भारत के हितों और अखंडता को लगातार नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। जब इनके काले कारनामों का खुलासा होता है तो वह हो-हल्ला करने लगते हैं। इसी लिए तो भारत के आइटी नियमों को लेकर ट्विटर ने अपने बयान में कहा था कि वह उसमें बदलाव कराने की कोशिश करेगी, ताकि उसके प्लेटफार्म पर खुले और मुक्त रूप से वातार्लाप हो सके। ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में बताया था। हाल ही में भाजपा प्रवक्ता के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड चिह्नित करने पर पुलिस पूछताछ के लिए ट्विटर के दफ्तर में गई थी। ट्विटर ने इसे पुलिसिया धमकी वाली कार्रवाई बताया। इस पर इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने ट्विटर के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश से मुनाफे का कारोबार करने वाली ट्विटर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ न समझाए। भारत में आजादी मूलभूत है लेकिन ट्विटर का रवैया दोहरा है। वह खुद को बचाने के लिए आजादी को ढाल बना रही है, जबकि भारत में उसने अपना कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। उसका हर आदेश अमेरिका से आता है। भारत में शिकायत तक के लिए कोई मंच नहीं बनाया है। जब चाहे किसी को ब्लाक करती है और उसे सुनवाई का अधिकार तक नहीं दिया जाता। भारत ऐसी मनमानी सहने को तैयार नहीं है। सरकार ने भारत के प्रति ट्विटर की प्रतिबद्धता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि जब भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर वार्ता कर रहे थे तो ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के हिस्से के रूप में दिखा दिया। कई बार कहने के बावजूद इस बड़ी गलती को ठीक करने में ट्विटर ने काफी दिन लगा दिए। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान लाल किले पर उपद्रव से जुड़े ट्वीट जो भारत की अखंडता के लिए खतरनाक हो सकते थे, उन्हें हटाने के लिए ट्विटर को कई बार कहना पड़ा, जबकि इसी ट्विटर ने अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए उत्पात को लेकर तत्काल कदम उठाया था। भारत में वैक्सीन को लेकर हिचक पैदा करने वालों पर भी ट्विटर ने कोई कदम नहीं उठाया। कोरोना के डबल म्यूटेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंडियन वैरिएंट कहने से मना किया, लेकिन ट्विटर पर कुछ लोग इसे इंडियन वैरिएंट कह रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। ट्विटर ने इसकी भी सुध नहीं ली और खुद को भारत के लोगों का हितरक्षक बता रही है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि देश में सभी इंटरमीडिएरीज के हितों की रक्षा होगी, लेकिन उन्हें भारत के कानून का पालन करना ही होगा।

अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उलझता महिलाओं का निर्णय

भारतीय समाज के केंद्र में जब-जब महामारी आती है तो सिर्फ. महामारी ही नहीं आती, बल्कि उसके साथ आती है बहुत सारी भ्रांतियां, अंधविश्वास और ऊटपटांग आडंबर। भारत में जब 19वीं सदी में चेचक जैसी महामारी ने पैर पसारा तो ज्यादातर ग्रामीण इलाको में इसे देवी या माता का नाम देकर कई प्रकार के अंधविश्वास से जोड़ा गया। तब से लेकर आज तक, यदि किसी को ऐसा कुछ भी होता है तो ज्यादातर लोगों के मुंह से निकलता है कि- ह्लमाता आ गयी है।ह्व ऐसी ही स्थिति के बहुत से उदाहरण हमें 1961 की हैजा महामारी में भी नजर आये और पोलियो महामारी के दौरान भी दिखाई दिए थे। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में झगड़े या गुस्से की स्थिति में महिलाएं गुस्से में श्राप के तौर पर- ह्लतुम्हें हैजा माई उठा ले जाएंह्व जैसे वाक्यों का आसानी से प्रयोग करती दिखाई दे जाती हैं।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि हैजे जैसी महामारी को आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय प्रकोप के रूप में देखा जाता है। ऐसे में जहां एक तरफ ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब हो और दूसरी तरफ जनता महामारी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बजाये उसे दैवीय या चमत्कारी घटना से जोड़कर देखती हो, ऐसे में सरकार और प्रशासन को दोबारा से पलट कर पीछे मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी व्यवस्था में क्या छूट रहा है? क्या है जो एक तरफ गांव गांव में वीडियो कॉलिंग और फाइव जी के सहारे गांवो को आगे बढा कर चमका देने के दावे किये जा रहे हों वहीं दूसरी तरफ उसी फाइव जी के टावर के नीचे अंधविश्वासी कहानियां जन्म लेती हैं? केंद्र और प्रदेश की सरकार महिला शिक्षा पर पूरा जोर लगाए हुए है, फिर कहां से समाज और विशेष कर महिला समाज में अंधविश्वास और भ्रामक कहानियां जन्म ले लेती हैं?

सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसी कहानियों से बने समाज के बीच जो महिलाएं अपने घरों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेती हैं, वह करोना महामारी में दवा और वैक्सीन को लेकर क्या मजबूत निर्णय ले पायेंगी? हम इसकी पड़ताल करते है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, जहां हमने बात की नमिता द्विवेदी से, जो नंन्दौली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन दिनों बड़ी शिद्दत से कोरोना महामारी के लिए जागरूकता जगाने में जुटी हुई हैं।

हमारे सवाल पूछे जाने में पर कि महिलाएं वैक्सीन के बारे में क्या सोचती है? बताती

हैं- ह्लमहिला हो या पुरुष, वैक्सीन को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते है कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अब भी बहुत से लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी लोग बहुत डरे हुए हैं।

एक तो इस महामारी से और दूसरा वैक्सीन की अलग अलग कहानियों से। जब तक लोगो को ठीक से समझाया नही जायेगा, उन्हें इस पर पूरी तरह से भरोसा नही आयेगा।

विशेषकर ग्रामीण महिलाएं जो सबसे अधिक अशिक्षित हैं, उनमें वैक्सीन को लेकर सबसे अधिक भ्रम और अंधविश्वास अपनी जड़े जमा चुका है। जिसे समाप्त करना बहुत आवश्यक और बड़ी चुनौती है। हमने उनसे जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में जो पढ़ी लिखी जागरुक महिलाएं या पुरुष अपने घरो का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका घर के बाकी लोगो के साथ मतभेद हो रहा है? इस पर वह कहती हैं कि- मेरे निजी अनुभव से मैं बता सकती हूं कि हमारे गांव में ही ऐसे बहुत से घर है, जहां वैक्सीन को लेकर लगभग टकराव की स्थिति है।

घर के आधे सदस्य वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं और आधे लोग लगाने से मना कर चुके हैं।ह्व दरअसल लोगों को यह सही ढंग से बताने वाला कोई नहीं है कि वैक्सीन लगा कर बुखार क्यों आ जाता है? उन्हें इस सवाल का संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर कोई दवा आराम के लिए बनी है, तो उससे बुखार क्यों आ रहा है? ऐसे में लोगों में मौत का डर बहुत है। कुछ लोग वैक्सीन की दूसरी डोज की समय अवधि बढाये जाने में भी शंका की स्थिति बनाए हुए हैं। नमिता जी के पास वैक्सीन को लेकर बहुत सी कहानियां हैं। वह कहना यही चाहती थी कि ऐसी स्थिति में जब घरों के मत दो हिस्सों में बंटे हों, ऐसी परिस्थिति में किसी महिला का घर के लिए निर्णय लेना मतलब हर आने वाली स्थिति की ज़िम्मेदारी खुद पर डालने जैसा होगा। जो वह कभी करना नहीं चाहेगी।

इसी कड़ी में हमारी बात रायबरेली जिले के घाटमपुर गांव के रहने वाले पप्पू से हुई। वह बल्दीराय ब्लाक में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। जब हमने उनसे ग्रामीण परिवेश में महामारी को लेकर बात की और जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने हमें बताया- ह्लस्थिति काफी गंभीर है और गांवो में भी इसे बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन किसी भी महामारी के साथ हमें गांव की शिक्षा और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देने की जरुरत है। पोलियो महामारी के दौरान जब दवा पिलाई जाती थी तब बहुत सी कहानियां कुछ इस तरह फैला दी गयी कि इसके पीछे प्रशासन जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहता है और जिस बच्चे को दवा पिलाई जाएगी वह बच्चा भविष्य में पिता नहीं बन सकेगा। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह वैक्सीन पर इतनी जल्दी भरोसा दिखा सकेंगे?

उनकी बातों से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी प्रशासन के लिए गांवों स्तर पर नयी वैक्सीन के लिए विशेष जागरूकता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराने तरीके से स्थिति के गडमड बने रहने का पूरा अनुमान है। इसी दौरान हमने रामपुर बबुआन गांव की पूजा से बात की, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है। पूजा ने बताया कि वो बीएससी पास है। उनकी दो साल पहले ही शादी हुई है। पति और जेठ दूसरे शहर में काम करते है। वह बीमारी को लेकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती हैं, लेकिन घर में बाकी लोग परंपरावादी सोच वाले हैं। इसलिए बात बात पर उसकी अपनी सास और ससुर से ठन जाती है। पूजा कहती हैं झ्र ह्लमेरी एक साल तीन महीने की बेटी है। मैंने उसे सारे जरूरी टीके लगवा दिए हैं। अगर कोरोना का बच्चो के लिए टीका आया तो वह भी लगवा दूंगी। मेरे घर के बुजुर्ग थोड़े पुराने ख्यालों के हैं और वह मुझे बार बार टोकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जो कर रही हूं वह मेरे बच्चे के भविष्य के लिए सही है।

बहरहाल वैज्ञानिक नजरियों और अंधविश्वासों का झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक देश के हर ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा और सही सूचना नहीं पहुंच जाती है। जिस दिन ऐसा मुमकिन होगा, पूजा जैसी युवा गृहणी और नमिता जैसी जमीनी कार्यकर्ता के लिए समाज में निर्णय लेने की चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसे परिवेश को तैयार करने के लिए हम सब को आगे आने की जरूरत है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसी कहानियों से बने समाज के बीच जो महिलाएं अपने घरों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्णय लेती हैं, वह करोना महामारी में दवा और वैक्सीन को लेकर क्या मजबूत निर्णय ले पायेंगी? हम इसकी पड़ताल करते है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, जहां हमने बात की नमिता द्विवेदी से, जो नन्दौली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन दिनों बड़ी शिद्दत से कोरोना महामारी के लिए जागरूकता जगाने में जुटी हुई हैं। हमारे सवाल पूछे जाने में पर कि महिलाएं वैक्सीन के बारे में क्या सोचती है? बताती हैं- ह्लमहिला हो या पुरुष, वैक्सीन को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते है कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अब भी बहुत से लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी लोग बहुत डरे हुए हैं। एक तो इस महामारी से और दूसरा वैक्सीन की अलग अलग कहानियों से। जब तक लोगो को ठीक से समझाया नही जायेगा, उन्हें इस पर पूरी तरह से भरोसा नही आयेगा। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं जो सबसे अधिक अशिक्षित हैं, उनमें वैक्सीन को लेकर सबसे अधिक भ्रम और अंधविश्वास अपनी जड़े जमा चुका है। जिसे समाप्त करना बहुत आवश्यक और बड़ी चुनौती है।

दूसरी लहर से ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था की चिन्ता

कोरोना महाव्याधि एवं प्रकोप की दूसरी लहर जन-जीवन के लिये बहुत घातक साबित हो रही है और इसका न केवल स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। जीवन पर अनेक तरह के अंधेरे व्याप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित बाजार हुआ, बाजार के सन्नाटे ने अर्थव्यवस्था को चैपट किया। बाजार में मांग, खपत, उत्पादन, निवेश जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हिल गये हैं। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी, यह अनिश्चिय में है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा है, फिर भी असंगठित क्षेत्र की कंपनियों पर कुछ ज्यादा ही असर पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल व अन्य कुछ क्षेत्रों में अनेक छोटी कंपनियों ने अपने काम बंद कर दिए हैं। असर सभी पर है, लेकिन असंगठित क्षेत्र पर ज्यादा है और इसीलिए पलायन भी दिख रहा है। पिछले साल मार्च में देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरी लहर पर जोर देकर कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना जरूरी है, संभवतः वे भविष्य में संभावित आर्थिक परिदृश्यों की स्थितियों को देखकर ही ऐसा कहा था। उनके ऐसा कहने के पीछे ठोस वजहें हैं, मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के तेरह महीनों में कोविड संक्रमण की वजह से पूरा देश भारी मुश्किलों और चुनौतियों के दौर से गुजरा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करके देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें की गईं। लेकिन दूसरी लहर ने उन कोशिशों पर पानी फेर दिया।

अप्रैल-2021 में कोरोना वायरस की दूसरी भयावह लहर के कारण न केवल इस पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा है बल्कि रेटिंग एजेंसियों ने अपनी भविष्यवाणी में बदलाव करते हुए भारत की विकास दर को दो प्रतिशत घटा दिया है। निश्चित ही पहली एवं दूसरी लहर के बीच के छह महीने में आए आर्थिक उछाल पर पानी फिर गया है। पिछले दो माह में राज्य सरकारें लगभग रोज नए प्रतिबंधों की घोषणाएं करती रही हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई के बढ़ने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, उत्पाद अवरुद्ध हुआ और मजदूरों का बड़े शहरों से पलायन जारी है। इस बार अस्तव्यस्त होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं जनजीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार ने किसी तरह के आर्थिक पैकेज नहीं दिये गये हैं। इसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, उत्पादन कम होगा और उपभोग नीचे जाएगा। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर दूसरी लहर

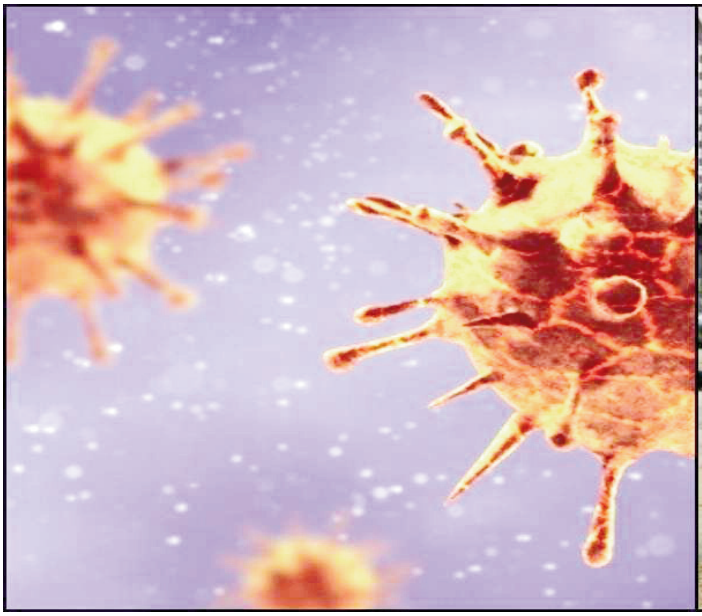

का असर पड़ेगा, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, या रियल एस्टेट, या बैंकिंग, एयरलाइंस, पर्यटन या फिर मनोरंजन।

ह्यसेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीह्न के आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च तक बेरोजगारी 6.5 प्रतिशत थी, यह 18 अप्रैल तक 8.4 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके अलावा, कई ऐसे प्रभाव होंगे जिसे आसानी से मापा नहीं जा सकता, सरकार के कर संग्रह में कमी आएगी। कंपनियां नुकसान कम करने के लिए खर्च को कम करेंगी या चीजों के दाम बढ़ाएँगीं, यह अनिश्चिय में हैं। दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से इन शहरों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। इससे खुदरा व्यापार, कंस्ट्रक्शन के कामों, मॉल और दुकानों पर फर्क पड़ना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि देश भर के मॉल अपने व्यवसाय का 90 प्रतिशत तक दोबारा हासिल चुके थे, लेकिन अप्रैल-2021 के बाद से एक बार फिर स्थिति बदलने लगी है। उद्योग प्रति माह राजस्व में 15 हजार करोड़ रुपये कमा रहा था, लेकिन स्थानीय प्रतिबंधों के साथ लगभग 50 प्रतिशत राजस्व में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में सरकारी प्रबंधों के कारण वाहनों के कारखानों में उत्पादन 50-60 प्रतिशत कम हो गया है। देश में वाहनों का सबसे अधिक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में है। इकनोमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक वाहन उत्पादन में इस कमी से रोजाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो रहा है। रियल एस्टेट पहले से ही संकट में है लेकिन इसका संकट और बढ़ गया है। रियल एस्टेट की एक कंसल्टिंग कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार इस साल जनवरी से मार्च तक किराए पर दिए गए ऑफिस स्पेस का कारोबार 48 प्रतिशत घटा है। सर्विसेज उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत जाने से बचने की सलाह दी है जबकि घरेलू पर्यटन भी कोरोना के डर से घटने लगा है। कहा जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर के लपेट में सबसे अधिक आने वाले हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन और एयरलाइंस पर दूसरी लहर का भी सबसे बुरा असर पड़ रहा है। 90 प्रतिशत रेस्टोरेंट बंद है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग

अप्रैल-2021 में कोरोना वायरस की दूसरी भयावह लहर के कारण न केवल इस पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा है बल्कि रेटिंग एजेंसियों ने अपनी भविष्यवाणी में बदलाव करते हुए भारत की विकास दर को दो प्रतिशत घटा दिया है। निश्चित ही पहली एवं दूसरी लहर के बीच के छह महीने में आए आर्थिक उछाल पर पानी फिर गया है। पिछले दो माह में राज्य सरकारें लगभग रोज नए प्रतिबंधों की घोषणाएं करती रही हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई के बढ़ने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, उत्पाद अवरुद्ध हुआ और मजदूरों का बड़े शहरों से पलायन जारी है। इस बार अस्तव्यस्त होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं जनजीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार ने किसी तरह के आर्थिक पैकेज नहीं दिये गये हैं।

में पिछले साल से अब तक अगर किसी की कमाई बढ़ी है तो वो घर पर खाना डिलिवर करने वाले लोग हैं। इनमें जोमैटो और स्विगी सब से आगे हैं।

आम तौर से उद्योग जगत पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ रहा है लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों के पास कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा, हालाँकि ये लॉकडाउन पिछले साल की तरह सख्त नहीं हैं। कई और राज्य सरकारें अब इस उधेड़बुन में हैं कि जान और जहान, दोनों को मिल रही चुनौती के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस संतुलन के साथ अर्थव्यवस्था का नियोजित करना भी जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के मोर्चे पर कोशिश कर रहा है कि असंगठित क्षेत्र को कारोबार जारी रखने के लिए पैसा मिले, जिससे असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति और न बिगडे.। जो छोटे कारोबारी होते हैं, उनके पास पूंजी बहुत कम होती है और वह जल्दी खत्म हो जाती है। जब ऐसी इकाइयों में काम बंद होता है, तब इनके लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंपनियों को फिर शुरू करना भी कठिन होता है। इसीलिए छोटे कारोबारियों को पैकेज दिया गया है कि वे बैंक से ऋण ले सकें, लेकिन इससे स्थिति नहीं सुधरेगी। अर्थ-व्यवस्था की चिन्ता में हम कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण से आंख भी नहीं मूंद सकते। मामले बढ़ते ही इसलिए हैं कि लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तब दो सप्ताह बाद मामले घटने लगते हैं। हमारे यहां फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो गई थी, तीन महीने होने जा रहे हैं। लॉकडाउन न लगाने का खामियाजा यह है कि हमारे यहां रिकॉर्ड संख्या में मामले बढ़े हैं और लोगों की जान भी जा रही है। एक दिक्कत यह भी है कि आंकड़े पूरे आते नहीं हैं या उपलब्ध नहीं कराए जाते। आज चिकित्सा व्यवस्था को बहुत तेजी से सुधारने की जरूरत है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ने एक पैकेज दिया है। मेडिकल ढांचा विकसित करने के लिए विशेष ऋण की जरूरत पड़ेगी, उसे इस विशेष पैकेज के जरिए मुहैया कराया जाएगा। अभी विदेश से काफी सहायता आ रही है, जैसे कोई दवा दे रहा है, तो कोई ऑक्सीजन टैंक दे रहा है। तीसरी लहर एवं भविष्य की चिन्ताओं को देखते हुए चिकित्सा क्षेत्र में आयात बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोशिशों का विस्तार करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो पैकेज घोषित किया है, वह अच्छा है, लेकिन तत्काल उससे फायदा नहीं होगा। सेना और आयात, दोनों से मदद लेनी पड़ेगी। संक्रमण गांव-गांव पहुंच गया है, नदियों में लाशें गांवों से ही आ रही है। गांवों में चिकित्सा ढांचा मजबूत करना होगा। यह साल खतरे से खाली नहीं है। अब सरकार को आगे आकर इसमें जहां-जहां काम रुक गया, बेरोजगारी बढ़ी है, वहां-वहां मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों को इस वक्त मदद की बहुत जरूरत है। मुफ्त अनाज, इलाज एवं जीवन निर्वाह के अन्य साधन जरूरी है। लोगों की हताशा-निराशा को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे।

अनाथ बच्चों को पालने की सोच को सच बनाएं

भारत को सशक्त ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, स्नेहिल एवं आत्मीय बनाने की भी जरूरत है, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने अनूठी एवं प्रेरक पहल की है। मोदी सरकार के सात साल पूरे होने के मौके पर कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस तरह का कहर ढाया कि कई परिवार उजड़ गए और सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपनी मां को और किसी ने माता-पिता दोनों खो दिये। कहते है कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। मगर ऐसे जन-कल्याणकारी आयाम के साथ परोपकार, वास्तविक जनसेवा एवं जनता के दुःख-दर्द को बांटने के लिये सरकार तत्पर होती है तो वह भगवान से कम नहीं होती। अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को मां मिले, बच्चों को घर जैसा वातावरण मिले, स्नेह की छांह मिले, अपनापन का स्पर्श मिले, इस दृष्टि से बालाश्रम एवं वात्सल्य घरों का निर्माण हो। समस्या काफी बड़ी है लेकिन सरकार एवं समाज अगर चाहे तो इन बच्चों के अभावों, दुःख-दर्दों, पीड़ाओं को दूर कर उन्हें भारत का श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। केन्द्र सरकार के साथ-साथ प्रांतों की सरकारों ने भी अनाथ बच्चों के पालन-पोषण का जिम्मा लेकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की एक अप्रैल से 25 मई के बीच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस हफ्ते बताया था कि देशभर में करीब 577 बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं।

अक्सर सरकारें मानवीयता एवं श्रेष्ठता के अवमूल्यन की शिकार रही है, क्योंकि जब सरकारों एवं उनका नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेताओं की समझ सही नहीं होती, विचारों में प्रौढ़ता एवं मानवीयता नहीं उतरती, व्यवहार एवं शासन-प्रक्रिया में संवेदनशीलता नहीं प्रकटती, कर्म एवं योजनाएं की दिशाएं लक्ष्य नहीं पकड़ती, सोच में कौशल नहीं होता, तब सरकारों की शासन-व्यवस्था श्रेष्ठताओं के अवमूल्यन की शिकार होती है। ऐसी सरकारें अपंग एवं विक्षिप्त ही कहलाती है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकारें ऐसी अपंग एवं विवेकशून्य नहीं है, यह हमारे वक्त का सौभाग्य है। इसी सौभाग्य का सूरज है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर फंड से अनाथ बच्चों के लिए कई योजनाओं की घोषणा। इस योजना के अन्तर्गत कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका हैल्थ बीमा किया जाएगा। 18 वर्ष तक उन्हें मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से दस लाख रुपए दिए जाएंगे। अनाथ हुए बच्चे के माता-पिता की कमी की तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे लेकिन उनकी सुरक्षा, जीवन-निर्वाह, शिक्षा और चिकित्सा-सहायता करना जहां सरकारों का दायित्व है, वहीं समाज के रूप में हमारा कत्रव्य है कि हम बच्चों की देखभाल करें और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा का सूरज उद्घाटित करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी की कठिन परिस्थिति में समाज के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्ज्वल भविष्य के लिए उनमें उम्मीद जगाएं। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है, उन्हें ह्यपीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत सहयोग दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी मदद करने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश करेगी। सरकार चाहती है कि वे मजबूत नागरिक बनें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। यद्यपि राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर अनाथ बच्चों की मदद का ऐलान किया है लेकिन इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस दृष्टि से की गयी पहल सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा नाम से योजना का ऐलान किया है। अनाथ हुई बालिकाओं की शादी के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार एक लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। दिल्ली, हरियाणा, असम, कर्नाटक और अन्य राज्य पहले ही योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। कोरोना महामारी ने एक अप्रत्याशित एवं असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। सबसे पहला काम तो अनाथ बच्चों की पहचान सुनिश्चित करना है। अनाथ बच्चों की दो श्रेणियां हैं, एक तो यह कि जिनके दोनों पेरेंट्स और गार्जियन कोरोना के कारण चल बसे, दूसरी श्रेणी में वैसे बच्चे हैं जिन्होंने कमाने वाले पेरेंट्स को खोया है। ऐसे बच्चों में बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं। इन्हें तुरन्त राहत पहुंचाना जरूरी है। विडम्बना है कि अक्सर ऐसी योजनाओं का लाभ वास्तविक पीड़ितों को नहीं मिल पाता है, समाज

एवं सरकारों में व्याप्त भ्रष्ट एवं लोभी लोग उनमें भ्रष्टाचार करने को तत्पर हो जाते हैं, सरकारों को सख्ती एवं जागरूकता से देखना होगा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त आक्सिजन एवं दवाओं की जिस तरह कालाबाजारी हुई, वह अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा थी, इन त्रासद एवं वीभत्स स्थितियों से समाज को बचाना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, तभी हम अनाथ बच्चों को पालने में समर्थ होंगे।

देश में ऐसे कई संगठन और संस्थान हैं जो निराश्रित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग ऐसे बच्चों के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने सुखों को त्याग कर आगे आते हैं, वह उनके जीवन में संजीवनी का काम करते हैं। हर शहर में धनाढ्य लोग या फिर सामाजिक संस्थाएं ऐसे बच्चों की मदद पैसे से कर देगीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बच्चों को स्नेह कौन देगा? अपनापन एवं पारिवारिकता का अहसास कौन देगा? समाज में अलग-अलग स्वभाव और अलग-अलग प्रवृत्ति के लोग हैं। अब जबकि केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनाथ बच्चों को हर तरह से सहायता देने का ऐलान कर दिया तो हो सकता है बच्चों के करीबी या दूरदराज के रिश्तेदार उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हो जाए। धन का लोभ बड़ों-बड़ों को बदल देता है। यह देखना समाज का काम होगा कि क्या ऐसे लोग अनाथ हुए बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या नहीं? जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर ऐसी कमेटियां स्थापित की जानी चाहिए जो इन बच्चों पर निगरानी रख सकें। देश में ऐसे बहुत से अनाथ आश्रम हैं जो ऐसे बच्चों और परित्यक्त महिलाओं को आवास, भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रबंध करती हैं लेकिन वहां यौन शोषण और अन्य आपराधिक घटनाओं की खबरें आती रहती हैं।

अप्रैल-2021 में कोरोना वायरस की दूसरी भयावह लहर के कारण न केवल इस पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा है बल्कि रेटिंग एजेंसियों ने अपनी भविष्यवाणी में बदलाव करते हुए भारत की विकास दर को दो प्रतिशत घटा दिया है। निश्चित ही पहली एवं दूसरी लहर के बीच के छह महीने में आए आर्थिक उछाल पर पानी फिर गया है। पिछले दो माह में राज्य सरकारें लगभग रोज नए प्रतिबंधों की घोषणाएं करती रही हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई के बढ़ने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, उत्पाद अवरुद्ध हुआ और मजदूरों का बड़े शहरों से पलायन जारी है। इस बार अस्तव्यस्त होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं जनजीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार ने किसी तरह के आर्थिक पैकेज नहीं दिये गये हैं।

हरियाणा के गुरुग्राम में दिव्यांग बच्चों के लिये चलाये जा रहे दीपाश्रम हो या वृंदावन शहर में साध्वी ऋतम्भरा के परमशक्ति पीठ द्वारा संचालित वात्सल्य ग्राम आदि ऐसे सेवा एवं स्नेह के आयाम है, जहां अनाथों को जीवन-रोशनी मिलती है। दीपाश्रम में 16 वर्ष के मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग विशाल का संरक्षण किया जा रहा है। विशाल को गोद लेने वाले माता-पिता जयपाल एवं जगवंती कोरोना महामारी के कारण अब संसार में नहीं रहे, वह दुबारा अनाथ हो गया था। उसे हरियाणा सरकार ने गोद लेकर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर विशाल से मिलने दीपाश्रम आये एवं अन्य दिव्यांगों से भी वे मिले।

हमें दीपाश्रम एवं वात्सल्य ग्राम जैसे सेवा-आयाम को जगह-जगह स्थापित करना होगा, जहां अनाथ, पीड़ित एवं अभावग्रस्त बच्चों को एक परिवार का परिवेश दिया जा सके। यह भी देखना होगा कि ऐसे बालक-बालिकाओं में हीन भावना व्याप्त न हो। वे अपनी परम्पराओं और संस्कृति में पले-बढ़ें। दीदी मां के नाम से चर्चित साध्वी ऋतम्भरा ने ऐसे बच्चों को गोद लेने और उनकी शिक्षा का प्रबंध करने की घोषणा की है। ऐसे बच्चों को लालची या आपराधिक प्रवृत्ति के करीबी लोगों से बचाने का दायित्व भी समाज को निभाना होगा। यह काम बड़ी सर्तकता से करना होगा कि निराश्रित बच्चे गलत हाथों में न पड़ जाएं। जो लोग बच्चों के लिए तरस रहे हैं, वे ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

खुद के संघर्ष के बल पर देश की राजनीति के चमकते सितारे बने थे रामविलास पासवान

अनूप नारायण सिंह

कभी कभी एक साधारण आदमी असाधारण बन जाता है। रामविलास पासवान ऐसे ही इतिहास मूर्ति थे। बिहार के खगड़िया जिले के फरकिया क्षेत्र के अलौली प्रखंड के छोटे से गांव में दलित परिवार में जन्म लेने वाले रामविलास पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1969 में अलौली क्षेत्र से विधायक बने और फिर राजनीति में लगातार विकास का सोपान चढ़ते रहे। उनके राजनीतिक गुरू और सर्वप्रथम सोशलिस्ट पार्टी से टिकट देकर जितवाने वाले पूर्व सांसद रामजीवन सिंह कहते हैं।

रामविलास पासवान में गजब की प्रतिभा निखरी। 89 वर्षीय श्री सिंह कहते हैं वर्ष 1969 में मैं मुंगेर जिला सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। जाड़े का मौसम था और नहाकर आया था। धूप में देह सुखाने के ख्याल से बैठा था और उस समय के पार्टी का अखबार जनता लेकर पढ़ रहा था। तभी देखा सड़क पर से एक कुतार्पाजामा पहने दुबला पतला लड़का पार्टी आफिस की तरफ आ रहा था। मैं अखबार पढ़ता रहा। वह लड़का मेरे सामने पहुंचा और प्रणाम कर खड़ा हो गया। मैंने पूछा किधर आए हैं ।

तो वे कहने लगे झ्र जी मेरा नाम रामविलास पासवान है और मैं अलौली क्षेत्र का निवासी हूं और आपसे सोशलिस्ट पार्टी का टिकट मांगने आया हूं। मैंने सामने की स्टूल बढ़ा दी और कहा -बैठिए। वह बैठ गया और कहा झ्र सर आप चाहेंगे तो मुझे टिकट मिल जाएगा। मैंने कहा झ्र आप चुनाव कैसे लडयिएगा। कहां सर ही न व्यवस्था कराएंगे। मैंने कहा -, कितने तक पढ़े लिखे हैं तो कहे कि बीए पास हूं। ठीक हे एक आवेदन टिकट के लिए लिखिए। वह सामने से हटकर आवेदन लिखने लगा।उस समय अलौली से कांग्रेस के विधायक मिश्री सदा हुआ करते थे। वे आजादी के बाद से ही लगातार जीत रहे थे।

वहां से सोशलिस्ट पार्टी से कोई लड़का हिम्मत कर टिकट मांगने आया था। मैंने मन में विचार किया ,इसकी मदद करनी चाहिए। तबतक वह आवेदन लिखकर दे आया था । हमने उसके आवेदन की गलतियों की फ्रूफ रीडिंग कर ठीक किया.

और कहा ठीक है मैं आज ही पटना जा रहा हूं और वहां से पार्टी सिंबल ले लूंगा। आप सोमवार को यहां से पार्टी सिंबल ले जाइएगा। मैं पटना गया और अपने पार्टी के नेता कपूर्री ठाकुर और अन्य को आवेदन दिखा सारी बात की जानकारी दी। वे लोग मेरे सुझाव को मानकर टिकट फाइनल कर दिया। उस समय बेगूसराय जिले के गढ़पुरा ब्लाक के कुछ पंचायत अलौली विधानसभा क्षेत्र में ही थे। जो मेरे क्षेत्र के बगल में था। मैंने उस क्षेत्र में इनकी मदद की।

इसके बाद वे लगातार राजनीतिक सोपान चढ़ते गए। वर्ष 1972 का विधानसभा चुनाव में मिश्री सदा से हार गए। इसके बाद हुए छात्र आंदोलन में कूद पड़े। वर्ष 1977 में हाजीपुर से रेकर्ड मतों से जीते और जनता पार्टी के एमपी बन गए। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। सांसद, विभिन्न विभागों के केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के लगातार अध्यक्ष बनते रहे।राजनीति के मौसम वैज्ञानिक से लेकर अवसरवाद और परिवार के कुनबों को राजनीति में बढ़ाते देश के शीर्ष राजनीति में हावी रहे। केन्द्र की बदलती सरकारों के साथ सरोकार जोड़ने की रणनीति के ये सिद्धहस्त थे। ऐसे नेता के निधन से देश ने एक जमीनी नेता को दिया।

क्या कोरोना पर भारी पड़ेगा क्यूबा का टीका

क्यूबा एक साम्यवादी विचारों का देश है जहां भारत के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 3.5 प्रतिशत (109,884 वर्ग किमी) और केवल 1.10 करोड़ की आबादी है। यह देश आज कोरोना के 5 वैक्सीन विकसित करने की राह पर है। यह क्यूबा और लैटिन अमेरिकी का पहला टीका है। एक बार में 5 वैक्सीन विकसित करने वाला यह दुनिया का एकमात्र देश होगा।

इस छोटे से देश ने वह हासिल किया है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के पास नहीं है। अपने स्वयं के टीके विकसित करके, क्यूबा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और बायोटेक के क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। आज, क्यूबा कुछ चुनिंदा विकासशील देशों के साथ खड़ा है जिनके पास अपने स्वयं के टीकों का निर्माण और निर्यात करने की क्षमता है।

विकासशील क्यूबा ने सीमित संसाधनों के चलते दवा बनाने या भोजन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे का एक पैसा भी कोविड की वैक्सीन बनाने में नहीं लगाया है। अन्य परियोजनाओं के लिए उनके पास मौजूद सभी संसाधनों को रचनात्मक रूप से इस दिशा में मोड़ दिया गया था। वहां के वैज्ञानिकों को बहुत कम चीजों पर काम करने की आदत है, इस बार यह काम आया।

कोविड और क्यूबा

पिछले साल जब कोविड की बीमारी देश में आई थी, तब क्यूबा के 28,000 से अधिक मेडिकल छात्रों ने सक्रिय स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से देश की 90 लाख की लगभग पूरी आबादी तक पहुंच बनाई थी। देश की सीमाओं को बंद कर दिया गया था और अलगाव केंद्र और परीक्षण और पता लगाने की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की गई थी। कोविड के कारण देश की जीडीपी में 11 फीसदी की गिरावट आई और जहाँ पहले प्रतिवर्ष 40 लाख पर्यटक आत थे वो घटकर केवल 80,000 ही रह गए। इसने पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और भी पंगु बना दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आर्थिक उपाय संभव नहीं थे। कोरोना की बीमारी देश को महंगी पड़ी। उन्होंने कठिन आर्थिक स्थिति के कारण बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से कोविड वैक्सीन नहीं खरीदने या विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक कोवैक वैक्सीन साझा करने की पहल के लिए साइन अप न करने का विकल्प चुना।

लेकिन हार न मानते हुए क्यूबा ने कोरोनावायरस से जूझते हुए और देश भर में गंभीर खाद्य और दवा की कमी का सामना करते हुए, कोविड के लक्षणों के इलाज के लिए 13 अलग-अलग दवाएं विकसित कीं। अब कोरोना वायरस के पांच टीके बनने की प्रक्रिया में हैं, कि घोषणा ने एक तरह से पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। उनमें से दो टीकाकरण के अंतिम चरण में हैं। पिछले महीने, हवाना में फिनले इंस्टीट्यूट के शोधकताओं ने घोषणा की कि उनका सोबराना 2 टीका अत्यधिक प्रभावी है और नैदानिक परीक्षणों के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। यदि परीक्षण सफल होते हैं, तो क्यूबा अपना खुद का कोरोनावायरस वैक्सीन विकसित करने वाला एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में भारी गिरावट के कारण भीषण मंदी के दौर से गुजर रहे टीके न केवल उनकी अपनी आबादी को इस घातक बीमारी से बचाएंगे, बल्कि क्यूबा को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेंगे। यदि सोबराना -2 सफल होता है, तो क्यूबा राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयास समाप्त होने के बाद इसे कम कीमत पर निर्यात करने की योजना बना

रहा है। जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार हो सकता है।

वैक्सीन के नाम में क्या है?

वैक्सीन के नाम में क्यूबा का इतिहास और मजबूती भी झलकती है। दो टीकों को सोबराना कऔर क्कक्कहा जाता है। स्पेनिश शब्द का अर्थ है संप्रभुता। पहले सोबराना परीक्षण की घोषणा के बाद लोगों को यह नाम इतना पसंद आया कि इसे बदलना नामुमकिन सा हो गया। क्यूबा में इस नाम को इतने गर्व से लिया गया कि सरकार के पास वैक्सीन के लिए सोबराना नाम का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्यूबा की क्रांति के नायक जोस मार्टी द्वारा लिखी गई एक कविता के बाद एक और का नाम अब्दला रखा गया। पांचवे टीके का नाम क्यूबा के एक क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, जिसने स्पेनिश उपनिवेशवाद, माम्बिसा के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब्दाला और मम्बिसा दोनों को नाक स्प्रे के माध्यम से टीका लगाया जाना है। सोबराना 2 और अब्दाला परीक्षण के तीसरे और अंतिम चरण में हैं। सोबराना 2 के लिए क्लिनिकल परीक्षण का अंतिम चरण पिछले महीने शुरू हुआ था। वैक्सीन के अंतिम परीक्षण में 44,000 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। क्यूबा के 1,24,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले ही अब्दाला टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन का परीक्षण अब ईरान और वेनेजुएला समेत संबंधित देशों में भी किया जा रहा है।

सोबराना 2 और अब्दाला दोनों टीके पारंपरिक संयुग्म टीके हैं, जिसका अर्थ है कि कोरोनावायरस स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से को एक वाहक अणु के साथ जोड़ा जाता है जो दक्षता और स्थिरता दोनों को बढ़ावा देता है। वे बिना किसी विशेष प्रशीतन आवश्यकताओं के कई हफ्तों तक रहेंगे और 46.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर दीर्घकालिक भंडारण के लिए भी योग्य होंगे. यदि ऐसा हुआ, तो यह बिना शीत भंडारण श्रृंखला वाले ये टीके गरीब उष्णकटिबंधीय देशों के एक वरदान सिद्ध होंगे। पश्चिमी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से टीके खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे विकासशील देशों के लिए यह एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पूरा भरोसा होनें के चलते कुछ देशों ने क्यूबन सरकार से 10 करोड़ खुराक खरीदने के लिए संपर्क किया है। कई गरीब देश अब अधिक किफायती टीकों के लिए क्यूबा की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में निर्मित टीके सस्ते नहीं हैं। मेक्सिको और अर्जेंटीना ने क्यूबा के टीकों में रुचि दिखाई है। क्यूबा वर्तमान में प्रति वर्ष दस लाख टीकों का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इसलिए बढ़ती मांग क्यूबा के वैक्सीन निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। सरकार ने इस महीने की शुरूआत में घोषणा की थी कि वेनेजुएला अब्दा वैक्सीन अपने देश में विकसित करेगा। इस मुकाम तक का सफर क्यूबा के लिए कितनी मुश्किलों से भरा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

ऐतिहासिक क्यूबा क्रांति:

क्यूबा, जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लूटपाट और लूट का केंद्र था, पर एक अमेरिकी कठपुतली फुलगेन्सियो बतिस्ता की सैन्य तानाशाही का शासन था। जुलाई 1953 और दिसंबर 1958 के बीच, फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने तानाशाही के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह किया और बतिस्ता को बेहद प्रतिकूल और संसाधनहीन परिस्थितियों में भयंकर लड़ाई और बलिदान के साथ बाहर खदेड़ दिया। मार्क्सवाद झ लेनिनवाद की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होकर, इन क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1965 में अपनी पार्टी का नाम बदलकर क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। यह पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस के बीच शीत युद्ध का समय था। क्यूबा अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से केवल 165 किमी दूर है, ये मुंबई से नासिक तक इतनी ही दूरी है। शक्तिशाली अमेरिका के तट के पास ही हुई क्यूबा की क्रांति आज तक उसके लिए गहरा घाव बना हुआ है।

क्यूबा को बर्बाद करने के लिए प्रतिबंध:

क्रांति के बाद, महान अमेरिका ने इस छोटे से देश पर प्रतिबंधों का हथियार उठा लिया। क्यूबा के गन्ने के खेतों, कारखानों और शहरों पर बमबारी की गई। सीआईए ने फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा की हत्या के लिए हर संभव कोशिश की। क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध दुनिया के पिछले 60 सालों के इतिहास में चला सबसे लंबा प्रतिबन्ध है।

अमेरिकी व्यापारियों और व्यवसायों पर क्यूबा के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यूबा ने हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया अक्टूबर 1960 में, जब अमेरिकी सरकार ने घुटने टेकने के लिए क्यूबा को तेल निर्यात करने से इनकार कर दिया, जब क्यूबा सोवियत रूसी कच्चे तेल पर निर्भर हो गया, क्यूबा में अमेरिकी कंपनियों ने उस कच्चे तेल को परिष्कृत करने से इनकार कर दिया। अंत में, क्यूबा ने अमेरिकी स्वामित्व वाली क्यूबा की तेल रिफाइनरियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के लगभग सभी नियातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य देशों को क्यूबा के साथ खाद्य पदार्थों का व्यापार करने पर उनकी वित्तीय सहायता में कटौती की धमकी दी।संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस अन्यायकारी निर्णय की आलोचना की गई थी। अमेरिका द्वारा यह भी घोषणा की गई, कि अमेरिकी कंपनियां या अमेरिकी भागीदारी वाली कंपनियां क्यूबा में व्यापार करने पर प्रतिबंधों के जोखिम पर ऐसा करें। हालांकि, क्यूबा को सभी आयातों के लिए नकद भुगतान करने की अनिवार्यता तय कर दी गई। उन्हें ऋण लेनें ऋण की भी अनुमति नहीं दी गई। दोषियों को 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया। 1962 में जॉन एफ. कैनेडी की अध्यक्षता के दौरान व्यापार प्रतिबंधों का दायरा कड़ा कर दिया गया था। पहले जो प्रतिबन्ध क्यूबा में बने उत्पादों पर लागू था उसका दायरा बढ़ा कर अब उन्हें क्यूबा द्वारा देश के बाहर असेम्बल या एकत्रीकरण करके बनाए सभी क्यूबन उत्पादों तक लागू कर दिया गया। क्यूबा को सहायता प्रदान करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधित कर दिए जाने का प्रावधान बनाया गया। कैनेडी ने भोजन और दवा की बिना सब्सिडी वाली बिक्री को छोड़कर क्यूबा के सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कैनेडी ने 1963 में यात्रा प्रतिबंध भी लागू कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूबाई नागरिकों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। क्यूबा का पर्यटन ठप पड़ गया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा से आने और जाने वाले यात्रियों को दुनिया भर में हवाई टिकट करों का भुगतान करना अपने कानून के तहत अपराध घोषित कर दिया।

सोवियत संघ की मदद से पैर जमाने का प्रयास कर रहे क्यूबा को सोवियत रूस के पतन से तगड़ा झटका लगा। क्यूबा की जीडीपी 34 फीसदी गिर गई और व्यापार आधा रह गया। रूस के साथ आयात और निर्यात में 60 से 75 प्रतिशत की गिरावट आई और अर्थव्यवस्था ने खुद को गंभीर संकट से घिर गई। अमेरिका इस फिराक में था कि आर्थिक अराजकता से कब लोगों का विश्वास फिदेल और क्रांति से उठ जाए। 1992 में, क्यूबा में व्यापार करने वाले अन्य देशों की विदेशी कंपनियों को संयुक्त राज्य में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। १९९६ में, कानून को और कड़ा किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूबा के साथ व्यापार करने वाले अन्य देशों की कंपनियों पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। ओबामा ने कानून को निरस्त करने की जहमत भी नहीं उठाई। ये प्रतिबंध समुद्री परिवहन पर भी लागू हुए। क्यूबा के बंदरगाहों पर रुके जहाजों को छह महीने तक अमेरिकी बंदरगाहों पर रुकने पर रोक लगा दी गई। 2000 में थोड़ी ढील देकर ह्लमानवीयह्व कारणों से, क्यूबा को केवल सीमित मात्रा में कृषि उत्पादों और दवाओं को बेचने की अनुमति दी गई। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में 60 वर्षों तक दबे छुपे, क्यूबा के सामान बेचने वाली कंपनियां को इतना डरा दिया गया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपना व्यापार खोने के डर से उन्होंने क्यूबा के साथ अपना कारोबार बंद कर दिया। अकेले वर्ष 2020 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा पर 100 से अधिक नए प्रतिबंध खोजखोजकर लगाए गए।

संघर्ष और प्राथमिकता:

दशकों के अमेरिकी प्रतिबंधों ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को असीम नुकसान पहुंचाया है। इन कड़े प्रतिबंधों ने क्यूबा के आर्थिक विकास को बाधित किया। इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए, कास्त्रो ने एक मजबूत सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जिसने निजी संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्कूल और उच्च शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया। क्यूबा की साम्यवादी विचारों की सरकार ने राज्य की योजना में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया। बड़े पैमाने पर राज्य-नियंत्रित नियोजित अर्थव्यवस्था और समाजवादी सिद्धांतों का पालन किया जाने लगा।जिसके कारण उत्पादन के अधिकांश साधन सरकारी स्वामित्व वाले हैं और सार्वजनिक संपत्ति के रूप में संचालित हैं, और 75 प्रतिशत रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र में है।

क्यूबा के पूर्व नेता फिदेल कास्त्रो ने सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त कर दी। अमेरिकी प्रतिबंध द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे क्यूबा में जैव प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया। अत्याधुनिक

जैव प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान में भारी निवेश करके, देश में एक शक्तिशाली स्वास्थ्य क्षेत्र का निर्माण करते हुए अधिकांश दवाओं और टीकों का उत्पादन करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। दवाओं की कमी से जूझ रहे क्यूबा के पास कोई विकल्प भी नहीं था।

क्रांति के बाद उभरी चिकित्सा चुनौतियां:

1959 की क्रांति के बाद नए सरकारी उपायों ने प्रणाली के सभी स्तरों के लिए एक एकीकृत नियामक ढांचा तैयार किया। उस समय, चिकित्सा संगठन देश के सबसे धनाढ्य और शक्तिशाली संगठन थे। राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारणों से,,ल्ल चिकित्सा सगठनों के फायदों के हिसाब से कानून बनाए गए थे। परिवर्तन और क्रांतिकारी सोच से असहमति जताते हुए, आर्थिक नुकसान की आशंका से और असुरक्षा के डर से, क्यूबा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों में से आधों ने देश छोड़ दिया। जब तक कोई सरकारी विनियमन नहीं था, विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थीं। इस काम में सबसे आगे चिकित्सा प्रयोगशालाओं, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित चिकित्सा कर्मचारियों की एक श्रृंखला थी। लेकिन क्रांति के बाद, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कई विदेशी कंपनियां पीछे हट गईं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष ने कई कंपनियों को बंद कर दिया और आपूर्ति संकट पैदा कर दिया। 1929 में क्रांति से पहले मौजूद कैंसर संस्थान और 1937 में स्थापित ट्रॉपिकल मेडिसिन इंस्टीट्यूट जैसे प्रमुख शोध संस्थानों ने वैचारिक मतभेदों के कारण क्रांति के बाद देश छोड़ दिया। 1959 से 1967 तक 60 लाख की आबादी वाले क्यूबा के 6,300 डॉक्टरों में से 3000 डॉक्टर्स देश छोड़ कर जा चुके थे। चिकित्सा शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय थी कि केवल एक मेडिकल कॉलेज और कुल 22 मेडिकल प्रोफेसर पीछे रह गए। एक बहुत छोटा, विशेषज्ञ समूह बचा था। उन्होंने, नई सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक युवा, अनुभवहीन प्रोफेसर, साथ ही पढ़ाने के लिए आमंत्रित विदेशी विशेषज्ञों ने क्यूबा में वैज्ञानिक स्थान को फिर से बनाने में मदद की।

वैचारिक प्रतिबद्धता को चुनौती देने की शुरूआत:

1960 में, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्रांति के बाद, सरकार ने निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में हस्तक्षेप किया, जो अत्यधिक मुनाफे का केंद्र थे, और देश के लिए चिकित्सा शिक्षा और इसके दर्शन को प्रोत्साहित किया। सरकार ने अपने पूर्ण लक्ष्य सार्वजनिक निवेश को एक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बना दिया और डॉक्टरों को प्रशिक्षण देते समय निवारक दवाओं पर प्राथमिकता के रूप में ध्यान केंद्रित किया। चिकित्सा स्नातकों को उनके शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने और निजी अभ्यास में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। नए निजी अस्पतालों के खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और 1970 तक लगभग सभी निजी अस्पतालों को सार्वजनिक स्वामित्व बना दिया गया था। औषधालयों और अस्पतालों को सहकारी आधार पर सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। कुछ ने एक निजी क्लिनिक या अच्छी तनख्वाह वाली स्थिति में जाने का फैसला किया, लेकिन वैचारिक प्रशिक्षण के कारण, अधिकांश ने शहरी या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने का फैसला किया।

उस समय के सन्दर्भ में और वैचारिक संघर्ष के माहौल में देखा जाए तो क्रांति से अभिभूत कई लोगों ने बेहतर वेतन और अधिक आरामदायक जीवन का त्याग कर उच्च आदर्शों के लिए इस मार्ग को चुना। इसका श्रेय निश्चित रूप से उन युवा क्रांतिकारियों को जाता है जिन्होंने शोषण से मुक्त और समानता पर आधारित साम्यवाद-समाजवाद की विचारधारा को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यही कारण है कि वे भौतिक धन और प्रतिष्ठा को दरकिनार करते हुए, अंतर्निहित प्रेरणा के साथ अपना जीवन लोगों को समर्पित कर रहे थे।

क्यूबा ने ज्ञान साझा करने और सहयोग के लिए एक खुला वातावरण बनाया। एक केंद्रीकृत, राष्ट्रव्यापी प्रणाली के माध्यम से, स्वास्थ्य क्षेत्र में समय और धन दोनों की बचत हुई। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण सामुदायिक अस्पतालों और क्लीनिकों के विकेंद्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान गुणवत्ता और मानकीकृत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की एक विशाल योजना था जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया।

इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से जनसंख्या स्वास्थ्य और रोग पैटर्न के बारे में समुदाय-आधारित जानकारी का संकलन और संश्लेषण हुआ। यह डेटा संग्रह आगे चला गया और बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोगी हो गया। क्यूबा की व्यापक, एकीकृत राष्ट्रीय चिकित्सा रिकॉर्ड प्रणाली यह निर्धारित करती है कि समाज में सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम कहां है, जिससे सरकार को संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित करने की अनुमति मिलती है। इस संरचना ने दवाओं की लागत को कम करने में भी मदद की क्योंकि नैदानिक परीक्षणों में सूचना-सहमति पंजीकरण ने गति पकड़ी। इससे दवा और उपचार की एक विधि का विकास हुआ। सरकार ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे संस्थागत शिक्षा और सामाजिक दक्षता के लिए प्रणाली तैयार की।

सफलता की कहानी सरकार की योजनाबद्ध इच्छा पर आधारित है। विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद, वह नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहीं। नतीजतन, देश अभिनव, विश्व स्तरीय उत्पादों को प्राप्त करने और शोध करने और नवाचार करने के बारे में अधिक उत्साहित हो गया। नए संस्थान बनाए गए। 1960 के दशक में विज्ञान के लिए अथक प्रयास 1980 के दशक में फल देने लगे। वैज्ञानिक अनुसंधान को सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल नीति में एकीकृत किया गया था।

क्यूबा की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह (हाल ही में) एक कम्युनिस्ट-समाजवादी देश है, जिसकी पूरी राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था है जो मजबूत आर्थिक प्रतिबंधों की भीख मांगे बिना बहादुरी से इसका सामना करती है। पूर्व-क्रांतिकारी समय में, देश फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा के लिए जिस प्रणाली पर निर्भर था, उसमें विदेशी सहायक कंपनियों ने 50% बाजार को नियंत्रित किया, आयातकों ने 20% और शेष 30% स्थानीय उत्पादकों को नियंत्रित कर रखा था। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सरकार के आने से पहले चिकित्सा उत्पादन का व्यवसाय काफी हद तक गिरावट में था। 60 के दशक में, सरकार ने निजी स्थानीय उत्पादकों का अधिग्रहण किया और विदेशी उत्पादकों ने आयात कम कर दिया। 1970 के दशक में, सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए एक दवा निर्माण परियोजना में अपना पहला निवेश शुरू किया। प्रारंभ में, ये प्रयास पश्चिमी और पूर्वी यूरोप दोनों से दवाओं की खरीद के साथ शुरू हुए, और फिर जैव प्रौद्योगिकी आई।

क्यूबा बायोफार्मा क्षेत्र की शुरूआत:

क्यूबा का बायोफार्मा उद्योग पिछले चार दशकों में तेजी से बढ़ा है। उस अवधि में इसके विकास पर नजर रखना क्यूबा सरकार और द्वीप के वैज्ञानिकों की संसाधनपूर्ण समझ और वैचारिक प्रतिबद्धता को दशार्ता है। 1965 में जन्मे, सीएनआईसी की स्थापना की गई थी। क्यूबा के प्रमुख फार्मासिस्टों ने गैर-लाभकारी डॉक्टरों के एक समूह, सीएनआईसी में अपना पहला वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्होंने सरकार के बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए खुद को समर्पित करने के आह्वान का जवाब दिया। सीएनआईसी ने विभिन्न विशिष्टताओं के रसायनज्ञों और इंजीनियरों को भी एक साथ लाया। ये लोग, जो स्नातक छात्र या शोधकर्ता थे, उन्हें आकर्षक वेतन और प्रशिक्षण के लिए नहीं, बल्कि केवल विज्ञान में उनकी रुचि और इस जिम्मेदारी को निभाने में उनके कौशल के लिए चुना गया था। उस प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण के लिए केवल 13 छात्रों का चयन किया गया था। ऐसे ही एक वैज्ञानिक को प्रशिक्षण में प्रवेश करने से पहले एक सहायक प्रोफेसर के रूप में 600 क्यूबन पेसो के वेतन पा रहे थे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनके प्रेम और समर्पण के कारण, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में केवल 200 पेसो काम कर रहे थे।

सीएनआईसी, एक स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए बनाया गया था। पहले कुछ वर्षों का मुख्य लक्ष्य विज्ञान और गणित में युवा चिकित्सा स्नातकों के ज्ञान को बढ़ाना और उन्हें शोध कार्य में प्रोत्साहित करना था। इसके लिए सीएनआईसी ने क्यूबा और विदेशी प्रोफेसरों द्वारा पढ़ाए जाने वाले कई पाठ्यक्रम शुरू किए। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद, कई युवा शोधकताओं ने पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय देशों में अध्ययन करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं। जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में आधुनिक शोध की सुविधा मिली। सीएनआईसी के कई शोधकताओं ने पाश्चर इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय और ज्यूरिख विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में दाखिला लिया। यह विचारधारा और देशभक्ति के प्रति उनकी निष्ठा थी जिसने उन्हें विदेशी अवसरों को अस्वीकार करने और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के अध्ययन और अनुसंधान की नींव रखने के लिए क्यूबा लौटने के लिए प्रेरित किया। क्यूबा का बायोटेक उद्योग बयाना में शुरू हुआ।

1970-75 के बीच, सीएनआईसी रासायनिक और

जैविक प्रायोगिक अनुसंधान के लिए एक बहु-विषयक संस्थान बन गया। वह क्यूबा के अन्य वैज्ञानिक संस्थानों की मां बनीं। उदाहरण के लिए, 1978 की शुरूआत में, सीएनआईसी के माइक्रोबायोलॉजिकल जेनेटिक्स विभाग के शोधकर्ता आनुवंशिक पुनसंयोजन के लाभों से अवगत थे और पहले से ही सूक्ष्मजीवों और आणविक जीव विज्ञान के आनुवंशिकी पर काम कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें, पुनसंयोजन में विभिन्न जीवों से आनुवंशिक सामग्री को मिलाकर (या संयोजन) करके नई आनुवंशिक सामग्री (डीएनए अणु) का निर्माण शामिल है। 1986 में, यू.एस. आधारित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी चिरोन ने हेपेटाइटिस बी का टीका प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग (या डीएनए पुनः संयोजक) तकनीक विकसित की; उसी वर्ष, क्यूबा के पुनः संयोजक वैक्सीन को सस्ते में विकसित किया गया था।

1966 में सीएनआईसी में स्थापित एक छोटी लेकिन प्रभावी न्यूरोफिज़ियोलॉजी इकाई 1990 में क्यूबन न्यूरोसाइंस सेंटर बन गई। केंद्र ने परीक्षण इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (क्यूईईजी) का उपयोग करने के लिए दुनिया की पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बनाई, जो दोषों या समस्याओं की मात्रात्मक पहचान करने के लिए मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का विश्लेषण करती है।

क्यूबा के बायोफार्मा उद्योग पर ध्यान देने के साथ, सीएनआईसी ने 1990 के दशक में उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कंपनी के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वैचारिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस और सह-विपणन समझौतों के रूप में काम करना शुरू किया।

साइंटिफिक पोल, जिसे पश्चिम हवाना बायोक्लस्टर के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 1992 में बनाया गया। ऑन्कोलॉजिस्ट रिचर्ड ली क्लार्क, जिन्होंने 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले कैंसर अस्पताल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने एक उत्तरी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां की यात्रा की और क्यूबा के वैज्ञानिकों को इंटरफेरॉन पर शोध करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अपने शानदार शोध पर चर्चा करते हुए, क्लार्क ने जल्द ही अपने शोध और कौशल को ूस्टन, टेक्सास में अपने अस्पताल में क्यूबा के दो वैज्ञानिकों के साथ कैंसर के इलाज की लड़ाई में साझा किया। क्यूबा के शोधकताओं ने मानव कोशिकाओं से इंटरफेरॉन के अलगाव का अध्ययन किया है। कैरी कैंटेल की हेलसिंकी स्थित प्रयोगशालाओं में प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने बड़ी मात्रा में इंटरफेरॉन को पुनः उत्पन्न करना सीखा। अपनी वापसी पर, उन्होंने क्यूबा में इंटरफेरॉन बनाने के लिए हवाना के एक छोटे से घर में एक विशेष प्रयोगशाला की स्थापना की। यह 1981 में उस वर्ष के अंत में एक सफलता थी। आखिरकार, यह उत्पाद कैंसर के खिलाफ आश्चर्यजनक दवा साबित नहीं हुआ, बल्कि डेंगू बुखार में बहुत फायदेमंद साबित हुआ। 1980 के दशक में क्यूबा में डेंगू से परेशान था।

बाद के वर्षों में, सरकार की नीतियों ने नए अंतःविषय कार्य समूहों द्वारा संचालित कई छोटी पायलट परियोजनाओं की शुरूआत की, जैसे कि 1981 में बायोलॉजिक फ्रंट और 1982 में जैविक अनुसंधान केंद्र। जब संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ने विकासशील देशों को जैव प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक उत्कृष्ट निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया, तो क्यूबा ने रिक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन वो जगह भारत को मिली। आगे बढ़ने की इच्छा से प्रेरित क्यूबा सरकार ने बाद में अपने सीमित संसाधनों के साथ अपना स्वयं का संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया।

1986 तक, क्यूबा ने सीआईजीबी लॉन्च कर दिया था, जो अब देश की सबसे उल्लेखनीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को भी शुरू किया गया। इनमें से एक इम्यून सेंटर है, जिसकी स्थापना 1987 में नैदानिक प्रणालियों के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए की गई थी। फिनले इंस्टीट्यूट को आधिकारिक तौर पर 1991 में लॉन्च किया गया था, और 1994 में सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी ने कई क्यूबन्स को मल्टीबिलियन-डॉलर बायोफर्मासिटिकल उत्पादों को विकसित करने और बेचने में मदद की।

कुछ दवाओं की सफलता से उत्साहित होकर, क्यूबा ने बायोटेक के क्षेत्र में और प्रगति की और कई नई दवाओं और टीकों का विकास किया है। इस लेख में पहले बताए गए फेफड़ों के कैंसर और एचआईबी टीकों के अलावा, गन्ना-व्युत्पन्न पॉलीकोसानॉल (पीपीजी) भी एक ऐसी दवा है जो एथेरोस्क्लोरोटिक हृदय रोग के कारण होने वाले कई विकारों की मृत्यु को कम करती है। उत्पाद को सीएनआईसी द्वारा विकसित किया गया था, और 1996 में इस शोध को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। मधुमेह पैर की समस्याओं के इलाज के लिए सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित हैबरप्रोट-पी ने भी स्वर्ण पदक जीते। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मेले में इस दवा को सर्वश्रेष्ठ युवा आविष्कारक वीआईपीओस्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था।

अक्सर, क्यूबा में दवा अनुसंधान को उतना प्रचार

नहीं मिला, जितना वह हकदार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया का पहला उपलब्ध टीका, सेरोग्रुप वीए-मेनगोक-बीसीॅ था, जो क्यूबा में मेनिन्जाइटिस का कारण बनने वाले मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किया गया था। वैक्सीन निमार्ता, फिनले इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित, उत्पाद को 1989 में डब्ल्यूआईपीओ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। हालांकि, वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान तब तक नहीं मिला जब तक कि इसने विशाल दवा कंपनी स्मिथक्लिन बीचम (अब गैलेक्सीस्मिथक्लिन का हिस्सा) का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वर्षों बाद, स्विस दवा निमार्ता नोवार्टिस को मेनिन्जाइटिस बी से गलत तरीके से लड़ने के लिए अपनी तरह का पहला टीका विकसित करने का श्रेय दिया गया। लेकिन 24 साल पहले, क्यूबा में वैक्सीन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।

2005 में, सिंथेटिक एंटीजन, हवाना विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान संकाय से संबद्ध एक छोटी प्रयोगशाला, ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (या एचआईबी) के खिलाफ दुनिया की पहली सिंथेटिक वैक्सीन विकसित करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में, फेफड़ों के कैंसर के लिए उक्टअश्अ-एऋक्ष्टवैक्सीन, क्यूबा का पहला बायोफार्मास्युटिकल उत्पाद है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नैदानिक परीक्षणों के लिए अमेरिकी दवा नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। उत्पाद आणविक इम्यूनोलॉजी केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, जो एंटीबॉडी, ऑन्कोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में माहिर है।

क्यूबा द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण दवाएं:

क्यूबा ने 1989 में बच्चों में दिमागी बुखार को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित और पंजीकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी शत्रुता बनाए रखी और जब पेटेंट की अवधि समाप्त हो फाइजर ने 2014 में टीका विकसित किया तब इसे संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस असाधारण दवा उत्पाद को पंजीकृत किया। सीमावैक्स—ईजीएफ वैक्सीन को पहली बार क्यूबा में 1994 में क्यूबन सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी द्वारा खोजा गया था। गैर-छोटे सेल फेफड़ों के कैंसर (एनएससीएलसी) के इलाज के उद्देश्य से एक जांच अध्ययन में एनएससीएलसी रोगियों के जीवित रहने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन बीस से अधिक वर्षों के उत्पादन के बाद, न्यूयॉर्क के बफेलो में रोजवेल पार्क कैंसर संस्थान ने एनएससीएलसी से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए इस टीके की प्रभावकारिता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा अपनी वर्णक कोशिकाओं (मेलानोसाइट्स) को खो देती है। यह त्वचा, बालों और श्लेष्मा झिल्ली सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बड़े सफेद धब्बे पैदा कर सकता है या पैच में त्वचा के रंग को कम कर सकता है। क्यूबा में, मेलागेनिना प्लस दवा को मानव प्लेसेंटा से अल्कोहल-आधारित लोशन के रूप में विकसित किया गया था। इसे लगाने से त्वचा पर सफेद धब्बों में मेलानोसाइट्स उत्तेजित होकर त्वचा का रंग पहले जैसा हो जाता है। दुनिया भर में 20 से अधिक वर्षों से उपलब्ध इस दवा को चमत्कार विटिलिगो दवा कहा गया है।

मां से बच्चे में एचआईवी और सिफलिस के प्रसार को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश था। तब तक हजारों बच्चे मारे जा चुके थे।

हेबरफेरॉन इस दवा को हवाना में सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में विकसित किया गया था। यह दो इंटरफेरॉन का संयोजन है। इसकी जटिल प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि ट्यूमर की वृद्धि, विशेष रूप से बेसल सेल कार्सिनोमा (सीबीसी), इसके आकार, स्थान और उपप्रकार की चिंता के बिना रोकी जाती है। यह अधिकांश त्वचा कैंसर में प्रभावी दिखाया गया है।

इंजेक्शन हेबरप्रोट-पी का आविष्कार क्यूबा ने 2006 में किया था। तब से, 15 और देशों ने इसे पंजीकृत कराया है और दुनिया भर में दस लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया गया है। हेबरप्रोट-पी एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर (ईजीएफ) है और मधुमेह के तीव्र अल्सर वाले रोगियों में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है जिनपर उपचार के अन्य तरीके काम नहीं करते और जिन्हें बड़ी सर्जरी का खतरा रहता है। 2009 में खोजा गया निमोतोजुमाब एक बेहतरीन ऐड-ऑन थेरेपी है। सिर और गर्दन के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के निदान वाले रोगियों में रेडियोथेरेपी की तुलना में अकेले रेडियोथेरेपी प्राप्त करने वाले रोगियों के समूह की तुलना में तीन गुना जीवित रहने की दर देखी गई है। लगभग 80% से 85% फेफड़े के कैंसर नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं। 2013 में खोजे गए रेक्टोमोमैब ने एनएससीएलसी के अंतिम चरण के रोगियों के जीवित रहने में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई। लैटिन अमेरिका में दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस मामले में अमेरिका अभी भी पीछे है।

दैनिक चुनौतियां छोटी नहीं हैं:

इसका स्पष्ट और कठिन लक्ष्य क्यूबा के बायोफार्मास्युटिकल उद्योग के निर्यात को पांच वर्षों में सालाना दर 1 बिलियन से अधिक करना है। निवेशकों और संभावित खरीदारों को आकर्षित किए बिना अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव के कारण फिलहाल यह असंभव लगता है।

कच्चा माल प्राप्त करना अब भी एक निरंतर संघर्ष है, खासकर जब डोनाल्ड ट्रम्प की अध्यक्षता में अमेरिकी प्रतिबंधों को कड़ा करने के बाद यह असंभव हो गया। क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध उन चिकित्सा उपकरणों को प्रतिबंधित करता है जिन्हें द्वीप पर आयात किया जा सकता है। टीकों पर काम कर रहे क्यूबा की विभिन्न शोध टीमों में केवल एक स्पेक्ट्रोमीटर है, जो गुणवत्ता नियंत्रण और टीकों की रासायनिक संरचना के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्यूबा अब स्पेयर पार्ट्स खरीदने में सक्षम नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर के ब्रिटिश निमार्ता, माइक्रोमास को अमेरिकी कंपनी वाटर्स ने खरीद लिया। चयनित आपूर्तिकताओं पर दशकों से प्रतिबंध लगाया गया है। चिकित्सा उपकरण अमेरिका जैसे पड़ोसी देश के बजाय चीन जैसे दूर से मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए आपूर्ति बहुत महंगी और जटिल हो गई है।

क्यूबा के डॉक्टरों को अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता है। उन्हें अन्य देशों के डॉक्टरों की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है, जो कि 52 पाउंड या केवल 5,400 रुपये है। इसके अलावा, वे नवीनतम नैदानिक तकनीक के बिना काम करते हैं। कई बार बिना बिजली या पर्याप्त पानी के भी काम करना पड़ता है। बुनियादी उपकरणों के आने के लिए अस्पतालों को कई सप्ताह इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे, मशीनों और उपकरणों की कमी के कारण उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया जा रहा। कभी-कभी पेरासिटामोल और अन्य पट्टियों जैसी बुनियादी दवाओं का नियमित स्टॉक नहीं होता है। फिर भी आदर्शवादी समाजवादी विचारधारा के बल पर ही वे सभी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हुए प्रशंसनीय सेवा देने का प्रयास करते हैं। सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में दो टीकों के विकास का नेतृत्व करते हुए, डॉ. गेरार्डो गिलन की सैलरी 200 पाउंड है, जो भारतीय रुपये में सिर्फ 20,718 रुपये है। उनके शब्दों में, ह्लहम अपने देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। हम कुछ सीईओ को अश्लील रूप से अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्यूबन बायोफार्मा उद्योग क्यूबा के कई क्षेत्रों में विफलता का अपवाद है। क्यूबा की समग्र अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय और वैश्विक रैंकिंग में पीछे है। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा के मुख्य व्यापारिक भागीदार सोवियत संघ के पतन के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के मद्देनजर, क्यूबा को कई क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

बायोफार्मा की सफलता और लाभ:

आज 30 से अधिक शोध संस्थान और निमार्ता हैं, जो राज्य द्वारा संचालित समूह बायोक्यूबा फार्मा के तहत काम कर रहे हैं। सीमित संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के बावजूद, इस छोटे से द्वीप राष्ट्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्रणाली के पास लगभग 1,200 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं और 50 से अधिक देशों में ये दवाएं और उपकरण बेचता है। उद्योग पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और प्रबंधित है और दुनिया की सबसे कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। इसका लक्ष्य सभी लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए रणनीतिक महत्व की दवाओं का विकास करना है। क्यूबा ने मलेरिया, पोलियो, टिटनेस और खसरा का सफाया कर दिया है। यह देश सफलतापूर्वक कोविड से लड़ रहा है, इसका मुख्य कारण प्राथमिक देखभाल और जनसंख्या के स्वास्थ्य पर ध्यान देने में उसके वर्षों का निवेश है। 1980 के दशक के अंत में, क्यूबा ने दुनिया का पहला मेनिन्जाइटिस वैक्सीन विकसित किया। आगे बढ़ते हुए, देश में नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले दस में से आठ टीकों का निर्माण यहां किया गया और अरबों खुराक विदेशों में निर्यात की गईं। देश ने 2014 और 2016 में क्रमशः1.193 बिलियन और 9 1.940 बिलियन की बचत की, क्योंकि उसे दवाओं का आयात नहीं करना पड़ता था।

1980 और 1990 के दशक में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगभग 1 अरब डॉलर्स का निवेश करने के अपने साहसिक निर्णय को दुनिया ने क्यूबा का बिलियन डॉलर्स का बायोटेक जुआह्व माना था। आज यह सबसे सफल क्यूबा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम बन गया है, जो अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। आज के क्यूबन बायोटेक उद्योग का बड़ा हिस्सा बायोक्यूबा फार्मा में केंद्रित है। इस क्षेत्र में 2012 में सरकारी आर्थिक सुधारों द्वारा निर्मित एक विशाल होल्डिंग है जिसमे 21,600 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली 33 कंपनियाँ कार्यरत हैं। उनमें से सैकड़ों विभिन्न अनुसंधान-उत्पादन उपक्रमों में गहराई से काम कर रहे हैं। 2014 से विशेष वेतन वृद्धि की गई है, जिससे साढ़े चार लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ हुआ है। अधिकांश लोगों का वेतन दोगुना हो गया है। बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल (बीएमआई) के शोध का अनुमान है कि व्यापार 2015 में 86 मिलियन से बढ़कर 2020 तक 119 मिलियन हो गया। इस क्षेत्र में अग्रणी देशों के प्रदर्शन की तुलना में ये निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हैं।

क्यूबा के बायोफार्मा उद्योग की सफलता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि देश में इस्तेमाल होने वाली 60 फीसदी से ज्यादा दवाएं उसी देश में बनती हैं। यह क्षेत्र 1995 से निर्यात में इतना लाभदायक रहा है कि इसने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने में मदद की है। चिकित्सा उत्पादों की खरोदफरोख्त में इस उद्योग से मिले लाभ का बड़ा हाथ है। क्यूबा के बायोफार्मा उद्योग की गुणवत्ता को अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना शुरू हो गया है।

बायोफार्मास्युटिकल उद्योग की सफलता की कहानी के पीछे के कारणः

फार्मा उद्योग, जो नकदी पर चलता है, उच्च तकनीक पर आधारित है और सफलतापूर्वक संपत्ति के अधिकार, स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा, विनियमन, कॉर्पोरेट प्रशासन पर चलता है, क्यूबा जैसे गरीब- विकासशील देश में, यह अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास के पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देते हुए सफलतापूर्वक विकसित हुआ है। अक्सर, उदारीकरण और निजीकरण को अनिवार्य और प्राकृतिक पूर्व शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उस ढांचे के बाहर विश्लेषण नहीं किया जाता है। इसलिए क्यूबा की सफलता की कहानी महत्वपूर्ण और अलग है। क्यूबा के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है, बाकी दुनिया के लिए वो अभी भी लगभग अपरिचित है। क्यूबाई बायोफार्मास्युटिकल उद्योग के इतिहास के गर्भ में कई साहसी और शक्तिशाली कहानियां हैं जो जिनमें शोधकताओं को उनकी शोध का लाभ भी दिया गया।ये मॉडल दुनिया भर में अधिकांश पारंपरिक अध्ययनों की एकरूपता को चुनौती देता हैं। क्यूबा का बायोटेक उद्योग निस्संदेह उस देश के आर्थिक इतिहास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के सबसे सफल मामले का प्रतिनिधित्व करता है।

क्यूबा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अनूठी डिजाइन, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, अनुसंधान और नवकल्पना, देश में सार्वजनिक निवेश ये सभी बायोफार्मासिटिकल उद्योग की सफलता के पीछे प्रमुख कारक हैं। क्यूबाई मॉडल उस ऐतिहासिक भूमिका का एक उदाहरण है जो एक संगठन किसी राष्ट्र को आकार देने में निभा सकता है। क्यूबा के बायोफर्मासिटिकल उद्योग पूरी आबादी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सफलता के लिए डिजाइन किया गया। इसे आर्थिक जरूरतों और क्यूबा के सार्वजनिक सेवा मूल्यों के लिए एक सस्ती दवा के रूप में विकसित किया गया है। प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए क्यूबा के चिकित्सा दर्शन के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरतों के अनुरूप कम लागत वाले, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने वाले गरीब देश को सस्ती सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का यह एकमात्र व्यवहार्य तरीका था। आज, क्यूबा चिकित्सा उत्पादों, विशेष रूप से बायोफार्मास्युटिकल्स का एक सफल निर्यातक बन गया है।

क्यूबा स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्डः

क्यूबा की साक्षरता दर 99.8 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। सरकार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 30,000 रुपये खर्च करती है। शिशु मृत्यु दर 4.2 प्रति हजार जन्म है। पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और महिलाओं की 83 वर्ष है। क्यूबा एक घोषित नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके 45 प्रतिशत नागरिक किसी धर्म को नहीं मानते हैं।

मेडिकल कॉलेज में सिखाई जाने वाली पहली चीजों में से एक ये है कि क्यूबा में डॉक्टर बनने का मतलब, पैसे छापना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। डॉक्टर-रोगी अनुपात प्रति 150 लोगों पर 1 है। जिसमे दुनिया के तमाम विकसित देश काफी पीछे हैं। यूके की दर प्रति 10,000 रोगियों पर केवल 2.8 डॉक्टर्स हैं। शुरू में ही रोग के प्रतिबन्ध की कोशिश होती है, इसलिए केअर नामक सार्वभौमिक और मुफ्त कार्यक्रम के तहत रोगी व्यक्ति का वर्गीकरण ४ प्रकारों में किया जाता हैः स्पष्ट रूप से स्वस्थ, बीमारी के जोखिम वाला, रोगग्रस्त और पुनर्वासित। अधिक वजन वाले, मधुमेह या उच्च रक्तचाप वाले लोगों की अन्य बीमारियाँ रोकने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टरों को उन लोगों की आर्थिक और सामाजिक संरचना का गहन ज्ञान होता है जिनमें वे काम कर रहे होते हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल सार्वभौमिक और मुफ्त है और दुनिया में डॉक्टरों का अनुपात सबसे ज्यादा है। वहां हर नागरिक की नियमित जांच होती है और अगर वह व्यक्ति अस्पताल नहीं जाता है तो डॉक्टर उसकी तलाश में उसके घर आ जाते हैं. व्यवहार में समस्या की पहचान कर इसकी रोकथाम पर अधिक बल दिया जा रहा है।

क्यूबा के हेनरी रीव ब्रिगेड का गठन 2005 में हुआ था। उन्होंने आपदाओं और महामारियों से निपटने के लिए दुनिया भर से स्वास्थ्य पेशेवरों के कैडर भेजे हैं। जब 2010 में आए भूकंप के बाद हैजा का प्रकोप शुरू हुआ, तब क्यूबा के डॉक्टर हैती में बचाव कार्य में लगे थे; वे 2013-16 में इबोला संकट के दौरान पश्चिम अफ्रीका पहुंचे। और जब कोविड 19 पूरे यूरोप में फैल गया, हेनरी रीव की दो टीमें इटली पहुंचीं और डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद की। अप्रैल, 2020 के अंत तक, 1,000 से अधिक क्यूबा के स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुनिया भर के कई देशों को कोविड 19 से निपटने में मदद कर रहे थे। चिकित्सा मिशन या चिकित्सा पर्यटन से होने वाले लाभ का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों में किया जाता है।

कौन सा मॉडल उपयुक्त हैः

दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को वित्त-केंद्रित मॉडल के आधार पर विकसित किया गया है, जबकि क्यूबा में यह 100% सरकारी निवेश पर आधारित है। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से परे, अधिकांश देशों में, सरकारी निवेश ने दुनिया भर के बायोफर्मासिटिकल उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई उदाहरणों को देखें जैसे अमेरिकन बायोटेक का निर्माण अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) द्वारा, या जर्मन फेडरल ऑफ एज्युकेशन अँड रिसर्च मंत्रालय में भी सार्वजनिक पैसा लगा था इस लिहाज से जैव प्रौद्योगिकी में क्यूबा सरकार का निवेश या भागीदारी असामान्य बात नहीं है। लेकिन कई अन्य बातें उसे खास बनाती हैं।

नेचर पत्रिका में 2009 के एक संपादकीय में लिखा, ह्लक्यूबा नें दुनिया के सबसे स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों में से एक को विकसित किया है, जो उद्यम अमीर देशों को पूर्वशर्त लगने वाली पूंजीकेन्द्रित वित्तीय मॉडल से अलग होने के बावजूद तेजी से बढ़ रहा है।ह्व क्यूबन मॉडल दिखाता है कि यह स्पष्ट है, कि सक्षम, जिद्दी और समाजवादी विचारों के प्रति समर्पित वैज्ञानिक किसी देश की आर्थिक संरचना को सुधारने में किस तरह निर्णायक कारक बनते हैं। जबकि दुनिया भर के कई देश शुरूवाती दौर में जैव प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र पर संदेह कर रहे थे, क्यूबा के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि इस क्षेत्र की क्षमता क्या कर सकती है। अनुसंधान और नवाचार पर समय और पैसा खर्च करना उस गरीब देश के लिए खतरनाक था और अभी भी है, लेकिन अब तक इसने दुनिया को क्यूबा के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलने में मदद करने के लिए बहुत प्रभावशाली काम किया है।

अपने 2021 के वार्षिक बजट में, क्यूबा ने अपने 178.8 बिलियन पेसो में से 24 प्रतिशत शिक्षा के लिए और 28 प्रतिशत स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं के लिए अलग रखा है। क्यूबा अपने कुल बजट का 52% शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर खर्च करता है। इसलिए, इस मुद्दे पर चर्चा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रायोजक के रूप में सरकार की भूमिका की वैधता तक सीमित नहीं है। क्यूबा का उदाहरण कई तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं और सक्षम सरकारी नीति और योजना की सफलता को दशार्ता है। क्यूबा का मार्ग हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए, निश्चित रूप से, यह वैध या आवश्यक हो सकता है। अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल्यों के लिए जनता के साथ खड़ा होना सीखने लायक है।

ओटीटी प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए कोई संस्था नहीं है

आज के युग में तकनीक जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं वो लगातार और तीव्रता के साथ बदल रही है। इसके व्यवहारिक पक्ष को हम सभी ने कोरोना काल में विशेष तौर पर महसूस किया जब घर बैठे कार्य करने के लिए वर्चुअल और ऑनलाइन मीटिंग्स, स्कूल की कक्षाओं का संचालन या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसे विभिन्न माध्यम आस्तित्व में आए।इतना ही नहीं कल तक जो फिल्में और टीवी विश्व भर में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन थे आज इंटरनेट और विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्म उनकी जगह ले चुके हैं। जब 2008 में भारत में पहला ओटीटी प्लेटफार्म लॉन्च हुआ था तब से लेकर आज जबकि लगभग 40 ओटीटी प्लेटफार्म हमारे देश में मौजूद हैं, इसने काफी लम्बा सफर तय किया है।

केजीएमजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की 2018 की एक रिपोर्ट का कहना था कि भारत का ओटीटी बाजार 2023 तक 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा। लेकिन कोरोना काल में इसने यह लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया।दअरसल लॉक डाउन के दौरान सिनेमा और मल्टीप्लेक्स बंद होने के कारण ओटीटी प्लेटफार्म ने भारत समेत सम्पूर्ण विश्व में हर आयु वर्ग के आकर्षण के साथ साथ जबरदस्त स्वीकार्यता भी प्राप्त की।

लेकिन जहां एक ओर इसने मनोरंजन और इस क्षेत्र में संघर्षरत युवाओं के लिए नए आयाम खोले हैं वहीं कई विवादों और चिंताओं को भी जन्म दिया है। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार ओटीटी प्लेटफार्म के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं।अगर इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो फिल्म और सीरियल जगत में कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले हर उम्र के लोगों के लिए इसने बगैर किसी भेदभाव के अनेकों द्वार खोल दिए हैं।

कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले हर उम्र के लोगों के लिए इसने बगैर किसी भेदभाव के अनेकों द्वार खोल दिए हैं।

आज एक आम चेहरे अथवा साधारण आवाज या फिर बिल्कुल आम शारीरिक बनावट के साथ किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए यहाँ असीमित अवसर हैं। जहां फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच के चलते बहुत से प्रतिभावान युवा मायूस हो जाते थे आज इन्हीं ओटीटी प्लेटफार्म के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। वहीं दर्शकों को भी एक फिल्म देखने के लिए टिकट के भारी भरकम पैसों के अलावा इंटरवल में कोक कॉफी पॉपकार्न जैसी चीजें मल्टीप्लेक्स में कई महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती थीं आज वो लगभग मुफ्त में घर बैठे इन चीजों का आनंद ले रहा है।

अगर ओटीटी के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो मनोरंजन, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार की सामग्री इनके माध्यम से आज

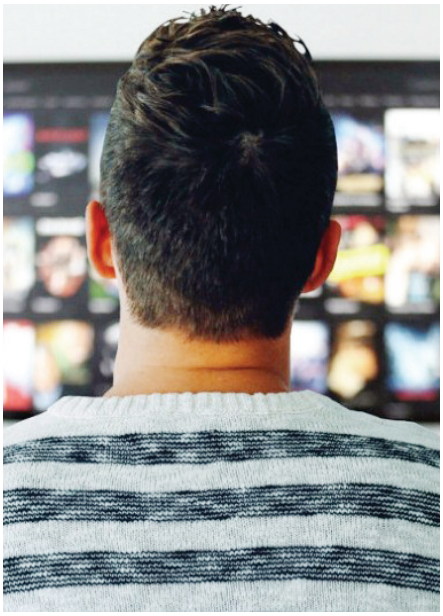

परोसी जा रही है वो देश के आमजन से लेकर बुद्धिजीवियों और अब तो सरकार तक के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। यह विषय इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफार्म देश के वर्तमान कानूनों के दायरे के बाहर हैं।

दरअसल फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, टीवी के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है लेकिन ओटीटी प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए कोई संस्था नहीं है।

और तो और इनको अपनी सामग्री दर्शकों तक पहुंचाने के लिए केबल ऑपरेटर या सैटेलाइट कनेक्शन जैसे किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। ये दर्शकों तक स्मार्ट फोन, लैपटॉप स्मार्ट टीवी जैसे साधनों से आसानी से पहुँच जाते हैं।आज ओटीटी प्लेफॉर्म ही नहीं आज बल्कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जो चाहे अपलोड कर सकता है। इसी बात का लाभ इन ओटीटी प्लेटफार्म को मिल जाता है। यही कारण है कि फिक्शन या कल्पना या कलात्मक सृजनात्मकता के नाम पर ये प्लेटफार्म कुछ भी दिखाने का साहस कर पाते हैं। चाहे हिन्दू धर्म और उसके देवी देवताओं का अपमान हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके दर्शकों को सिखाना (जामताड़ा) या फिर हत्या और क्राइम करके कानून से बचने के तरीके दिखाना। यही कारण है कि कई बार मिजार्पुर पाताल लोक या तांडव जैसी सिरीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की जाती हैं।

लेकिन अगर कोई स्पष्ठ और सख्त कानून मौजूद होता जो इनकी ह्लरचनात्मकता, अभिव्यक्ति और सृजनात्मकताह्व को सीमाओं के साथ परिभाषित करता तो लोगों या संस्थाओं को ओटीटी प्लेटफार्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती अपितु ये स्वयं कानून के दायरे में रहते और अपनी सीमाओं को भी पहचानते। लेकिन आज की हकीकत यह है कि इस प्रकार की सिरीज में अमर्यादित भाषा और आचरण से लेकर क्रूरता से भरी हिंसा दिखाई जा रही है जो हमारे समाज पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही है।

आज जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों द्वारा अपराध करने की घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं कहीं न कहीं हमें ओटीटी प्लेटफार्म द्वारा परोसी जाने वाली सामग्री पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस करा रहीं हैं। क्योंकि सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट पर स्मार्ट फोन पर बेहद सरलता से उपलब्ध है। उस स्मार्ट फोन पर जो आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो ओटीटी प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश उसके सामने प्रस्तुत करे। इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है। इंटरनेट और स्मार्ट फोन के आविष्कार के साथ नई चुनौतियों और समस्याओं का भी अविष्कार हुआ है जिनसे विश्व का हर देश जूझ रहा है। भारत में भले ही हमारी सरकार ने आज इस दिशा में सोचना शुरू किया है लेकिन विश्व के कई देश नए कानून बनाकर ओटीटी प्लेटफार्म को इन कानूनों के दायरे में ला चुके हैं। अमेरिका में 2019 में इनके लिए कानून बन गया था।योरोपीय यूनियन में भी पिछले साल इन पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ओटीटी प्लेटफार्म के नियंत्रण के लिए ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेटरी कानून 2000 में ही कानून बना लिया गया था। सऊदी अरब में तो इंटरनेट पर परोसी जाने वाली समस्त सामग्री का नियमन एन्टी साइबर क्राइम लॉ में द्वारा किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस एक कानून से ही वो इंटरनेट पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर रोक लगा सकता है। हमारी सरकार देर से ही सही लेकिन जागी तो है। अगर इसके नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देकर उस पर लगाम लगाने के प्रयास किए जाएं तो ओटीटी प्लेटफार्म जो आज मनोरंजन के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुका है निश्चित ही समाज में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के संचार का महत्वपूर्ण जरिया भी बन सकता।उम्मीद है कि शीघ्र ही हमारे देश में भी ओटीटी प्लेटफार्म के नकारात्मक पक्ष पर कानूनी रूप से अंकुश लगाया जाए ताकि अपने सकारात्मक पक्ष के साथ यह खुलकर समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके।

क्या स्वप्न सच के प्रतिबिम्ब होते हैं ?

स्वप्न का हमारे जीवन के साथ गहरा तादात्म्य है। स्वप्न क्यों आते हैं, उनका वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, क्या स्वप्न सच के प्रतिबिम्ब होते हैं, क्या स्वप्न जीवन को प्रभावित करते हैं- ऐसे अनेक प्रश्न है जो बंद पलकों के पीछे की इस रोमांचक दुनिया से जुडे.है। इस ख्वाबों की दुनिया के रहस्य की पडताल सदियों से होती रही है। लेकिन अनेक अनुसंधानों और खोजों के बावजूद आज भी स्वप्न की यह मायाबी दुनिया रहस्य ही बनी हुई है।

सपने क्या हैं? क्या ये बात सही है कि जिसकी जैसी सोच होती है, उसे वैसे ही स्वप्न आते हैं। क्या इनका रिश्ता होता है अतीत, पिछले जन्म और भविष्य से? सपनों की अनगिनत कहानियां हैं और वैसे ही तो हैं रंग-बिरंगे स्वप्न। प्रसिद्ध दार्शनिक सिगमंड फ्रायड ने पहली बार स्वप्नों की प्रक्रिया, संरचना, रहस्यों और कारणों पर प्रकाश डाला। उनका कहना है कि जब हम नींद की स्थिति में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। हर इंसान स्वप्न देखता है, निद्रा की अवस्था में उसके बिम्ब उभरते हैं। आंखें खुलते ही स्वप्न की सारी दुनिया बिखर जाते हैं। स्वप्न बहुत नाजुक होते हैं, तितली के परों सरीखे, वे गुलाब की पंखुरी पर ओस की एक मोती-सी बूंद जैसे होते हैं।

सपने क्या हैं? क्या ये बात सही है कि जिसकी जैसी सोच होती है, उसे वैसे ही स्वप्न आते हैं। क्या इनका रिश्ता होता है अतीत, पिछले जन्म और भविष्य से? सपनों की अनगिनत कहानियां हैं और वैसे ही तो हैं रंग-बिरंगे स्वप्न। प्रसिद्ध दार्शनिक सिगमंड फ्रायड ने पहली बार स्वप्नों की प्रक्रिया, संरचना, रहस्यों और कारणों पर प्रकाश डाला। उनका कहना है कि जब हम नींद की स्थिति में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। हर इंसान स्वप्न देखता है, निद्रा की अवस्था में उसके बिम्ब उभरते हैं।

वास्तव में स्वप्न एक ऐसी स्थिति है, जहां हम जाग्रत नहीं बल्कि निद्रावस्था में होते हैं। यह निद्रावस्था रात्री के आखिरी प्रहर की होती है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। हमारी आंखें बंद पलकों के पीछे ज्यादा सक्रिय होती है और तेजी से घूमती है। मस्तिष्क भी ज्यादा क्रियाशील होता है। इसीलिए हम कई बार देखे गए सपने को सुबह उठने के बाद भी हू ब हू याद रखते हैं, कई बार बस हल्की सी एक झलक भर याद रह जाती है। जिससे पता चलता है, हमारी सपने में किसी से मुलाकात हुई थी, सपने में हम किसी के पास आए थे, सपने में हमें किसी

स्थान-विशेष पर ले जाया गया था, किसी रहस्य से पर्दा उठाया गया था लेकिन यादों की यह डोर बहुत कमजोर और टूटी-फूटी सी होती है। सपनों का वह समूचा जगत इसके साथ गहरे तक जुड़े लोगों के लिए तो मायने रखता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समझ और सक्रिय दिमाग की विवेचना शक्ति से इस सबको महज भ्रम साबित कर देते हैं।

लेकिन सपनों की दुनिया के बारे में, अभी अंतिम रूप से दुनिया कुछ नहीं कह सकती। इसकी एक वजह यह भी है कि तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें उन महान आविष्कारों की जानकारी और समझ किसी दिन सोते हुए सपने में आयी और न सिर्फ यह सपना याद रहा बल्कि उन्होंने महान आविष्कार कर डाले। वैज्ञानिकों की ये बातें मनोवैज्ञानिकों की उन बातों को काटती हैं, जिसमें वो कहते हैं सपने कुछ नहीं हमारे दिन भर की गतिविधियों के ही नतीजे होते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई थ्योरी या ऐसा कोई आविष्कार भी हमारी दिन भर की दिमागी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है, जिसका अभी तक दुनिया में अस्तित्व ही न हो?

कुछ लोग अपने सपनों को दूसरों से बता तो नहीं पाते मगर ऐसे लोग पुरजोर दावे से कहते हैं उनके दिलों दिमाग में एक परछाई की तरह कोई धुंधला दृश्य, कोई धुंधली तस्वीर घूम रही है, पर इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा कि उसका मकसद क्या है? उसका कहना क्या है? दरअसल कुछ सपने बेहद निजी होते हैं, वह हमारे जिंदगी के अच्छे किसी खास मौके का टुकड़ा होते हैं या उसकी कुछ अच्छी काल्पनिक का विस्तार होते हैं, ऐसे सपने हमें याद रहते हैं। ऐसे सपने हमारे दिल के करीब होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो लुप्तप्राय जगह को खोजने को प्रेरित करते हैं, कुछ सपने आने वाले खतरे के प्रति सावधान करते हैं, कुछ सपने जिन्दगी और मौत के बीच जूझ रहे व्यक्ति के लिये जीवनदान बन कर आते हैं। किसी को सपने में मृत्यु के दर्शन होते हैं तो किसी को खोयी वस्तु के संकेत मिल जाते हैं।

ऐसे सपनों को लेकर एक थ्योरी है। माना जाता है कि सहज मृत्यु की स्थिति में शरीर के अंदर मौजूद आत्मा किसी दूसरे शरीर को अपना घर बनाती है। लेकिन जब अकाल मौत होती है या हमारी नजर में वह प्राकृतिक मौत है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, तब नए शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा भटकती रहती है और इस भटकन के दौरान वह भी यदाकदा मृत्यु से पहले के साथी संगियों और परिजनों के के साथ सपनों में संवाद करती है। कभी-कभी ऐसी मृतात्माएं ऐसे लोगों को परेशान करती है, या बदला लेती है जिन्होंने या तो अकाल मृत्यु में सहायता की है या उसके जीवन में तरह-तरह की बाधाएं, परेशानियां एवं हिंसक घटनाओं के द्वारा जीने को जटिल बना दिया है।

प्राचीन समय में सपनों के जरिए इलाज भी होता था, इसे ड्रीम थैरेपी कहा जाता था। सम्मोहन के जरिए ड्रीम थैरेपी की जाती थी। यूनान में चार सौ से भी ज्यादा मंदिरों में इस थैरेपी के इस्तेमाल के उदाहरण मिलते हैं। ईसा से दो शताब्दी पहले तक ग्रीक और रोमन साम्राज्य में उपचार के लिए ड्रीम थैरेपी बहुत आम थी।

कुछ लोग अपने सपनों का साफतौर पर बयां नहीं कर पाते। लेकिन वे कुछ संकेत देते हैं जैसे उनके दिलों दिमाग में एक परछाई की तरह कोई धुंधला दृश्य, कोई धुंधली तस्वीर घूम रही है, पर इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल

वास्तव में स्वप्न एक ऐसी स्थिति है, जहां हम जाग्रत नहीं बल्कि निद्रावस्था में होते हैं। यह निद्रावस्था रात्री के आखिरी प्रहर की होती है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। हमारी आंखें बंद पलकों के पीछे ज्यादा सक्रिय होती है और तेजी से घूमती है। मस्तिष्क भी ज्यादा क्रियाशील होता है। इसीलिए हम कई बार देखे गए सपने को सुबह उठने के बाद भी हू ब हू याद रखते हैं, कई बार बस हल्की सी एक झलक भर याद रह जाती है। जिससे पता चलता है, हमारी सपने में किसी से मुलाकात हुई थी, सपने में हम किसी के पास आए थे, सपने में हमें किसी स्थान-विशेष पर ले जाया गया था, किसी रहस्य से पर्दा उठाया गया था लेकिन यादों की यह डोर बहुत कमजोर और टूटी-फूटी सी होती है। सपनों का वह समूचा जगत इसके साथ गहरे तक जुड़े लोगों के लिए तो मायने रखता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समझ और सक्रिय दिमाग की विवेचना शक्ति से इस सबको महज भ्रम साबित कर देते हैं। लेकिन सपनों की दुनिया के बारे में, अभी अंतिम रूप से दुनिया कुछ नहीं कह सकती। इसकी एक वजह यह भी है कि तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें उन महान आविष्कारों की जानकारी और समझ किसी दिन सोते हुए सपने में आयी और न सिर्फ यह सपना याद रहा बल्कि उन्होंने महान आविष्कार कर डाले। वैज्ञानिकों की ये बातें मनोवैज्ञानिकों की उन बातों को काटती हैं, जिसमें वो कहते हैं सपने कुछ नहीं हमारे दिन भर की गतिविधियों के ही नतीजे होते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई थ्योरी या ऐसा कोई आविष्कार भी हमारी दिन भर की दिमागी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है, जिसका अभी तक दुनिया में अस्तित्व ही न हो? कुछ लोग अपने सपनों को दूसरों से बता तो नहीं पाते मगर ऐसे लोग पुरजोर दावे से कहते हैं उनके दिलों दिमाग में एक परछाई की तरह कोई धुंधला दृश्य, कोई धुंधली तस्वीर घूम रही है, पर इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा कि उसका मकसद क्या है?

पा रहा कि उसका मकसद क्या है? उसका कहना क्या है? दरअसल कुछ सपने बेहद निजी होते हैं, वे हमारे जिंदगी के अच्छे किसी खास मौके का टुकड़ा होते हैं या उसकी कुछ अच्छी कल्पना का विस्तार होते हैं, ऐसे सपने हमें याद रहते हैं। ऐसे सपने हमारे दिल के करीब होते हैं।

लेकिन सपनों की दुनिया के बारे में, अभी अंतिम रूप से कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनी है। विज्ञान मानता है कि सभी स्तनधारी और जानवर सपने देखते हैं, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक मनुष्य ही ऐसा होता है, जो सपने देखता है। वैसे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं।

स्वप्न का जन्म कब, कैसे और कहां हुआ? इसकी जन्मतिथि एवं मिति क्या है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तो बताना संभव है कि जिस दिन मानव ने सृष्टि पर चरणन्यास किया उसी समय से स्वप्नपरी के सुंदर दृश्यों एवं नाटक का श्रीगणेश हो गया। गर्भस्थ शिशु तो क्या पशु-पक्षी भी स्वप्नलोक में विचरण करते हैं तभी तो कहावत प्रसिद्ध है ह्यसोयी बिल्ली तो चूहों के ही स्वप्न देखा करती है।

तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें उन महान आविष्कारों की जानकारी और समझ किसी दिन सोते हुए सपने में आयी और न सिर्फ यह सपना याद रहा बल्कि उन्होंने महान आविष्कार कर डाले। जबकि कतितय मनोवैज्ञानिक कहते हैं सपने कुछ नहीं हमारे दिन भर की गतिविधियों के ही नतीजे होते हैं। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के बीच विरोधाभास है।

दुनिया और इसमें जीने वाले लोगों में स्वप्न की मान्यता का व्यापक प्रभाव है। इस प्रभाव एवं सपनों के संसार पर गहन अध्ययन समय-समय पर होते रहे हैं। हाल ही में जैन साध्वी डॉ. ललितरेखा ह्यखाटूह्ल की एक पुस्तक ह्यसफर सपनों काह्ल प्रकाशित होकर सामने आयी है। यह सपनों की दुनिया की विविध कोणों से विवेचना करती हुए एक महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इसे एक संकलन और शोध-प्रस्तुति भी कहा जा सकता है। इस पुस्तक में स्वप्नों की मान्यता का विशद प्रभाव को देखने को मिलता है, स्वप्न-फल की अनेक व्याख्यायें एवं जो धारणाएं प्रचलित हैं, उनको प्रस्तुति देते हुए लेखिका कहती है कि उन्हें अगर अनेकांत और स्याद्वाद की दृष्टि से देखा जाए तो सभी धारणाएं सत्य प्रतीत होती हैं। वस्तुत अनेकांतवाद से किसी मत का एकांततः खण्डन उचित नहीं है।

सभी दृष्टियों में सत्यांश तो छिपा हुआ ही है, किन्तु इन प्रचलित धारणाओं के होने के बावजूद भी सभी दर्शनों में बिखरी सुंदर स्वप्नों की सौरभ सबको सहज ही आकृष्ट कर लेती है। अतः भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में बिखरे हुए एक-एक स्वप्न सुमनों को संजोकर स्वप्नमाला गूंथने का यह लघु प्रयास मानव की सोच को नया आयाम देता है।

रॉबर्ट स्टीव का मानना है कि जीवित रहने के लिए स्वप्न अनिवार्य है। स्वप्नों के प्रति ग्रहणशीलता हमारे जीवन को सुखद बनाने में बेहतर सहायक सिद्ध हो सकती है। मनुष्य स्वप्नों के संसार में क्रीड़ाएं अधिक करता है। एक जगह बैठने की अपेक्षा भ्रमण ज्यादा करता है। हमारे चैंतीस प्रतिशत स्वप्न भ्रमण एवं सवारी करने से संबंधित होते हैं। ग्यारह प्रतिशत दृश्यों में किसी से बतियाते हैं। सात प्रतिशत स्वप्न दृश्यों में हम बैठे रहते हैं। हमारे छह प्रतिशत स्वप्न सामाजिक समारोह से संबंधित होते हैं। पांच प्रतिशत स्वप्न में हम खेलते-कूदते हैं। तीन प्रतिशत में शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य करते हैं तीन प्रतिशत

क्या स्वप्न सच के प्रतिबिम्ब होते हैं?संयुक्त परिवार की शक्ति का केंद्र बिंदु हैं महिलाएं

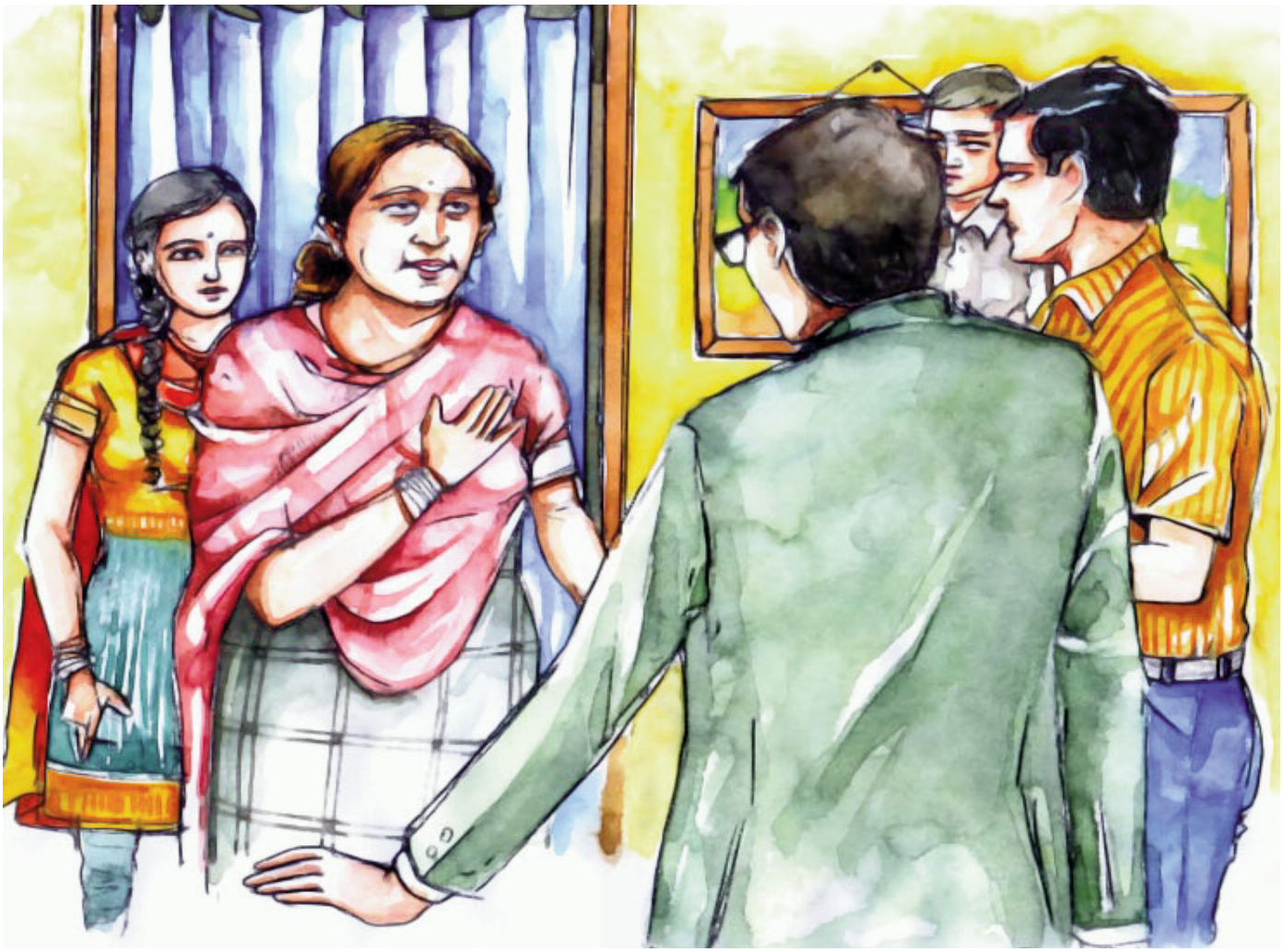

प्राचीन भारतीय सभ्यता में संयुक्त परिवार हुआ करते थे।परिवार को सम्बल प्रदान करने की विशेषता सिर्फ संयुक्त परिवार में हुआ करती है। परिवार की एकता ही उसकी शक्ति की परिचायक होती है।जैसा कहा भी गया है झ यूनिटी इज स्ट्रेंथ अर्थात एकता में ही शक्ति निहित है।जो भी परिवार संयुक्त हैं वहाँ एकता(यूनिटी) है।संयुक्त-परिवार ही विषम परिस्थितियों में शक्ति का परिचायक हुआ करती है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में त्राहिमाम मचा दिया।आंकड़े बताते हैं की दूसरी लहर में होम आइसोलेशन कितना जरुरी हो गया।होम-आइसोलेशन संयुक्त परिवार के लिए राम बाण दवाई साबित हुई।संयुक्त परिवार में मरीज की देखभाल, खान पान,और उचित व्यवस्था परिवार के लोग ही कर लेते हैं।जिसका परिणाम यह हुआ की होम आइसोलेशन में संयुक्त परिवार में रहने वाले मरीज ज्यादा तर ठीक हो गए और अस्पतालों के चक्कर से बच गए। जो परिवार संयुक्त नहीं थे और उसमे कोई कोरोना पॉजिटिव आया तो उसके पास हॉस्पिटल के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा।परिणामतः ऐसे परिवारों को कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ कर रख दियोपरिवार दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक ही बात कहूंगा की संयुक्त परिवार ही श्रेष्ठ परिवार है ।कोरोना की दूसरी लहर ने प्राचीन भारतीय सभ्यता की याद दिला दी और परिवारों को सबक दे गई की प्राचीन भारतीय सभ्यता को अपनाएं न की पाश्चात्य सभ्यता को।संयुक्त परिवार में व्यक्ति अकेला नहीं होता।जो परिवार संयुक्त नहीं हैं वहाँ अकेलापन का अहसास होता है।अकेलेपन में तनाव है। तनाव में ऋणात्मक ऊर्जा काम करती है।जहां अकेलापन नहीं है वहां सकारात्मक ऊर्जा काम करती है।अर्थात वहां तनाव नहीं है। सकारात्मकता से कोरोना को हराया जा सकता है और लोगों ने हराया। कहने का तात्पर्य है की संयुक्त परिवार ही तनाव रहित है। तनाव ही सारी बीमारी की जड़ है।संयुक्त परिवार में महिलाओं की अहम् भूमिका होती है।महिलाएं संयुक्त परिवार की शक्ति का केंद्र होती हैं। बिना महिलाओं के संयुक्त परिवार की कल्पना व्यर्थ है।

संस्कृत में एक श्लोक है-ह्ययस्य पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः।अर्थात,जहां नारी की पूजा होती है,वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे हिन्दू धर्म में वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण,गरिमामय,उच्च स्थान प्रदान करते हैं।वेदों में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा, शील,गुण,कर्तव्य,अधिकार और सामाजिक भूमिका का सुन्दर वर्णन पाया जाता है।वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक,पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं।वेदों में स्त्री यज्ञीय है अर्थात यज्ञ समान

पूजनीय।वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली,सुखझसमृद्धि लाने वाली,विशेष तेज वाली,देवी, विदुषी,सरस्वती,इन्द्राणी,उषा- जो सबको जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं।वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हैझउसे सदा विजयिनी कहा गया है और उन के हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्यन- अध्यापन से लेकर रणक्षेत्र में भी जाती थी। जैसे कैकयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रखते हैं।अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की द्रष्टा हैं- अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदितिदाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी आदि। वेदों में नारी के स्वरुप की झलक इन मंत्रों में देखें जा सकते हैं-यजुर्वेद 20:9(स्त्री और पुरुष दोनों को शासक चुने जाने का समान अधिकार है)।यजुर्वेद 17:45(स्त्रियों की भी सेना हो। स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें)।यजुर्वेद 10:26(शासकों की स्त्रियां अन्यों को राजनीति की शिक्षा दें।जैसे राजा,लोगों का न्याय करते हैं वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हों)।अथर्ववेद 11:5:18(ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में कन्याओं के लिए भी ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण करने के बाद ही विवाह करने के लिए कहा गया है।यह सूक्त लड़कों के समान ही कन्याओं की शिक्षा को भी विशेष महत्त्व देता है)कन्याएं ब्रह्मचर्य के सेवन से पूर्ण विदुषी और युवती होकर ही विवाह करें ।अथर्ववेद 14:1:6(माता- पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धीमत्ता और विद्याबल का उपहार दें। वे उसे ज्ञान का दहेज दें)।जब कन्याएं बाहरी उपकरणों को छोड़ कर,भीतरी विद्या बल से चैतन्य स्वभाव और पदार्थों को दिव्य दृष्टि से देखने वाली और आकाश और भूमि से सुवर्ण आदि प्राप्त करनेझकराने वाली हो तब सुयोग्य पति से विवाह करे।ऋग्वेद 10.85.7(माता- पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्याबल उपहार में दें। माता- पिता को चाहिए कि वे अपनी कन्या को दहेज भी दें तो वह ज्ञान का दहेज हो) ।ऋग्वेद 3.31.1 (पुत्रों की ही भांति पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी है)। देवी अहिल्याबाई होलकर,मदर टेरेसा,इला भट्ट,महादेवी वर्मा,राजकुमारी अमृत कौर,अरुणा आसफ अली,सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी आदि जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मन-वचन व कर्म से सारे जग-संसार में अपना नाम रोशन किया था। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का बायां हाथ बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़-संकल्प के बल पर भारत व विश्व राजनीति को प्रभावित किया था। उन्हें लौह-महिला यूं ही नहीं कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने पिता,पति व एक पुत्र के निधन के बावजूद हौसला नहीं खोया। दृढ़ चट्टान की तरह वे अपने कर्मक्षेत्र में कार्यरत रहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तो उन्हें ह्यचतुर महिलाह्न तक कहते थे, क्योंकि इंदिराजी राजनीति के साथ वाक्-चातुर्य में भी माहिर थीं। कोरोना संकट का सबसे ज्यादा भार परिवार में महिलाओं पर आ पड़ा। कोरोना के भारी संकट में पूरे परिवार में यदि किसी पर सबसे ज्यादा संकट आया तो वह घर की महिला ही है जिसकी भूमिका अचानक बहुत बढ़ गई और घर में न केवल उसके काम बढ़े

बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र में दूसरे लोगों का अनधिकृत प्रवेश भी बढ़ गया। हर कोई उस पर हुक्म चलाया या फिर उससे काम करवाया। लॉकडाउन में बाहर सब कुछ बंद था तो सबको घर पर ही रहने की मजबूरी थी। लॉकडाउन ने महिलाओं के काम के बोझ को बढ़ा दिया था। बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे उन्हें या तो घर पर पढ़ाओ या नई-नई चीजें खिलाते रहो या मनोरंजन करो नहीं तो वे उधम मचायेंगे। जो बुर्जग हैं उन्हें कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा था,उनकी देखभाल अलग। बड़े आराम से घर में कोरोना से बचाव के लिए घर वालों ने तय कर दिया कि हाउस हैल्प और काम करने वाली बाई को मत आने दो। फिर खाना बनाने,बर्तन मांजने, झाड़ू चौका, कपड़े धोने का काम सब महिला पर ही आ गया। महिलायें पुरुषों की तुलना में किसी भी संकट में ज्यादा सतर्क और सक्रिय होती हैं। बेहतर प्रबंधक और बुरे हालात में भी बड़ी हिम्मत से परिवार और समाज को संभाले रहती हैं ये अलग बात है जब संकट नहीं रहता तब वे परिवार और समाज दोनों में ही फिर से उपेक्षित हो जाती हैं। कोरोना के इस संकट में उन्होंने कुछ अतिरिक्त जिम्मेवारियों का वहन किया।भारतीय संस्कृति में महिलाओं की अत्यंत गौरवशाली व महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत एकमात्र देश है जहां महिलाओं के नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है।यहां नारी को शक्ति स्वरूपा, भारतीय संस्कृति की संवाहक,जीवन मूल्यों की संरक्षक,त्याग,दया,क्षमा,प्रेम,वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। उसे गृहलक्ष्मी की मान्यता दी गई। अतएव हम कह सकते हैं महिलाएं,संयुक्त परिवार की शक्ति का केंद्र बिंदु हैं।

कोरोना ने समझाया पेड़ का महत्व फ्री ऑक्सीजन सप्लायर है पेड़

विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण और स्वच्छता के स्तर में गिरावट के पीछे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी अहम वजह है। धरती बेशुमार पेड़ों से आच्छादित है, लेकिन लोग अपनी सुविधा और फायदे के लिए इन्हें जमकर काट रहे हैं। परिणाम यह है कि एक-एक कर जंगल खत्म हो रहे है। कई इलाके बंजर हो गए हैं, तो कुछ होने वाले हैं। वैज्ञानिकों की ताजा सर्वे रिर्पोट की मानें तो दुनियाभर में तीन ट्रिलियन यानी 3,040,000,000,000 (एक लाख करोड़) पेड़ हैं। हर साल 15.3 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तरह से 2 पेड़ प्रति व्यक्ति से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव सभ्यता की शुरूआत (करीब 12 हजार साल पहले) के समय धरती पर जितने पेड़ थे, उसमें आज की तारीख में 46 फीसदी की कमी आई है। भारत के लिहाज से बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ ही आते हैं। भारत में पेड़ों की संख्या करीब 35 अरब है। जबकि चीन में 139 अरब पेड़ हैं और प्रति व्यक्ति के लिहाज से 102 पेड़ आते हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेड़ रूस में है जहां 641 अरब पेड़ हैं तो इसके बाद कनाड़ा, ब्राजील और अमेरिका का नंबर आता है जहां क्रमशः 318, 301 और 228 अरब पेड़ हैं।

परिणाम यह है कि एक-एक कर जंगल खत्म हो रहे है। कई इलाके बंजर हो गए हैं, तो कुछ होने वाले हैं। वैज्ञानिकों की ताजा सर्वे रिर्पोट की मानें तो दुनियाभर में तीन ट्रिलियन यानी 3,040,000,000,000 (एक लाख करोड़) पेड़ हैं। हर साल 15.3 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तरह से 2 पेड़ प्रति व्यक्ति से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव सभ्यता की शुरूआत (करीब 12 हजार साल पहले) के समय धरती पर जितने पेड़ थे, उसमें आज की तारीख में 46 फीसदी की कमी आई है। भारत के लिहाज से बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ ही आते हैं। भारत में पेड़ों की संख्या करीब 35 अरब है। जबकि चीन में 139 अरब पेड़ हैं और प्रति व्यक्ति के लिहाज से 102 पेड़ आते हैं।

प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे घने पेड़ उत्तरी अमेरिका, स्कैंडेनविया और रूस में हैं। इन इलाकों में करीब 750 बिलियन पेड़ (750,000,000,000) हैं जो वैश्विक स्तर का करीब 24 फीसदी है। दुनिया के जमीनी क्षेत्र में करीब 31 फीसदी क्षेत्र जंगलों के

घिरे हुए हैं, लेकिन इनमें तेजी से गिरावट आती जा रही है। 1990 से 2016 के बीच दुनिया से 502,000 स्क्ववायर मील (13 लाख स्क्वायर किलोमीटर) जंगल क्षेत्र खत्म हो गए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, 2017 में भारत में 708,273 स्क्वायर किमी यानी देश की कुल जमीन का 21.54 फीसदी हिस्से पर ही जंगल हैं। जबकि सीआईए की वर्ल्ड फैक्ट बुक 2011 के अनुसार, दुनिया में 39,000,000 स्क्वायर किमी जमीन पर जंगल हैं। विश्व बैंक के अनुसार, अब तक दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा बड़े इलाके के जंगल दुनिया से खत्म हो गए हैं।

पिछले 50 सालों में अमेजन जंगल के क्षेत्र में 17 फीसदी की कमी आई है। कहा जा सकता है दुनिया में भले ही लोग अपने फायदे के लिए पेड़ काट रहे हों और जंगलों को खत्म करते जा रहे हों, लेकिन इसी जंगल के कारण दुनिया में 1 करोड़ 32 लाख लोगों (13.2 मिलियन) को रोजगार मिला हुआ है। जबकि करीब 4 करोड़ 10 लाख लोगों को इस सेक्टर से जुड़े अन्य मामलों में रोजगार मिला हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों के लगातार कटाव से वन क्षेत्र लगातार खत्म होते जा रहे हैं। हम सलाना 1 करोड़ 87 लाख (1.87 मिलियन) एकड़ जंगल खोते जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द धरती का बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा। जंगल खत्म हो गए तो करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छीन जाएगी। ऐसे में जरुरी है कि जंगल भी बचाए जाएं और धरती को हरी-भरी रखी जाएं जिससे आने वाली पीढ़िया भी खूबसूरत धरती को निहार सके।

दुनिया में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरुक करना है। हम अपने आसपास पेड़-पौधे लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग न करके पर्वावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण के साथ छेडछाड़ की जाएगी, पर्यावरण की रक्षा नहीं की जाएगी, तो इसका सीधा असर हमारे आज और आने वाले कल पर पड़ेगा। ऐसे में गार्डन, छत पर, बालकनी और बंजर स्थान आदि जगहों पर पेड़-पौधे हम लगा सकते हैं। परिवार का हर एक सदस्य अगर एक-एक पौधा भी लगाता है, तो इस दिन हम एक घर, एक मोहल्ले, एक राज्य और एक देश के तौर पर काफी संख्या में पौधे लगाकर अपनी धरती को हरा-भरा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अगर अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें हर हाल में पेड़ों की, नदियों समेत अन्य चीजों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। कोरोना माहमारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली गिलोय-तुलसी की उपयोगिता के कारण अब इसकी भी डिमांड बढ़ी है। विश्व पर्यावरण दिवस को तब ही सफल बनाया जा सकता है जब हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तब ही इस धरती पर जीवन संभव है।

विश्व पर्यावरण दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है और हर साल इसकी एक नई थीम होती है। जिसके आधार पर सरकार, निगम, समुदाय, गैर-सरकारी संगठन और मशहूर हस्तियां लोगों को

पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति जागरूक करती हैं। जैव-विविधता या बायोडायवर्सिटी का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतुओं से जोड़कर भी देखा जाता है। अब चूंकि कोरोना संकट के चलते लगाये गए लॉकडाउन ने जैव-विविधता को एक नया जीवन दिया है, इसलिए पर्यावरण दिवस की थीम भी इसी पर आधारित है।

2020 के मार्च से 2021 के मई तक भले ही कोरोना संकट के चलते लोगों के लिए बुरे सपने में तब्दील हो गया हो, लेकिन पर्यावरण के लिए यह काफी अच्छा साबित हो रहा है। कोरोना को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, कारखानों का शोर सबकुछ बंद हो गया। जिसकी बदौलत न केवल वायु प्रदूषण में कमी आई, बल्कि दुर्लभ जीव-जंतु भी देखने को मिले। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति के साथ रिश्ते की जिस डोर को मनुष्य ने अपनी कारगुजारी के चलते तोड़ दिया था, वह फिर जुड़ती नजर आ रही है।

इस अवसर पर पूरे विश्व में जागरूकता अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चलाई जाती है जिससे स्वच्छ वातावरण में मनुष्य और जीव-जंतु खुलकर सांस ले सकें। इसके लिए जरुरी है कि हमें हर दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना होगा। तभी हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे। अक्सर हम बहुत ही आसानी से अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते है, हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम वायु प्रदूषण के स्तर में आश्चर्यजनक रुप से कमी ला सकते हैं। कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साईकिल का प्रयोग करें। कार पूल करें या सार्वजनिक वाहन प्रणाली का प्रयोग करें। अपने घर, फ्लैट या सोसाइटी में हर साल एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करके उसे एक पूर्ण वृक्ष बनाएं ताकि वह विषैली गैसों को सोखने में मदद कर सके। अपने भवन में चाहे व्यक्तिगत हो या सरकारी कार्यालय हो, वर्षा जल संचयन प्रणाली तकनीक प्रयोग में लाएं। बिजली के उपकरण जैसे पंखा, ट्यूब लाइट, कूलर, एसी, कंप्यूटर आदि को उपयोग के तुरंत बाद स्विच ऑफ कर दें। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम करने के लिए सोलर पावर तथा स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करने के बाद नल को तुरंत बंद कर दें। कपड़े धोने के बाद साबुन वाले पानी से फर्श की सफाई करें और तीन आर- रिसाइकल, रियूज और रिड्यूस का हमेशा ध्यान रखें। कूड़ा करकट, सूखे पत्ते और अपशिष्ट न जलाएं। डिस्पोजेबल वस्तुओं जैसे प्लास्टिक गिलास, पानी की छोटी-छोटी बोतल और प्लेट के प्रयोग से परहेज करें। फसलों के अवशेष न जलाएं। इससे पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव मर जाते हैं और वायु प्रदूणष स्तर में वृद्धि होती है। छात्र उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर या कॉपी के खाली पन्नों को व्यर्थ न फेकें बल्कि उन्हें रफ कार्य में उपयोग करें।

हम सभी लगातार सुन रहे हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो खतरनाक है। क्योंकि सेहत और पर्यावरण के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक लाखों लोगों की हो जाएगी मौत। 70 से ज्यादा देशों के 250 वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा जारी की छठी ग्लोबल इनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को विज्ञान, प्रौद्योगिकी व वित्त से ज्यादा सतत विकास के रास्ते पर जाने की जरूरत है। हालांकि, अभी भी जनता, व्यापार व राजनीतिक नेताओं का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी भी राजनेता पुराने उत्पादन व विकास के मॉडलों से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की कार्यवाहक कार्यकारी निदेश जोयेस मसूया ने आईएएनएस से कहा, ह्लनवाचार प्रगति का बड़ा हिस्सा है, हमने अबतक बहुत-सी पर्यावरण चुनौतियों का सामना किया है। यह सभी तरीके से प्रदूषण से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसे बनाए पोस्टर जिससे लोग प्रभावित हो। क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो प्रत्येक 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए मनाया जाता है। ऐसे अभियान की शुरूआत करने का उद्देश्य वातावरण की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने और हमारे ग्रह पृथ्वी को सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए है। वैसे भी कोविड का समय चल रहा है ऐसे में बाहर भी नहीं जा सकते हैं। आज के समय में हमारा समाज बहुत आधुनिक समाज बन गया है लेकिन उनसे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान है। अपने पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए।

कोरोना काल में मानवता पर भारी पड़ता लोभ और लालच

हिंदुस्तान में आज लाखों लोगों को कोरोना नहीं मार रहा, इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान का लोभ एवं लालच इंसान को मार रहा है। ऐसे स्वार्थी लोगों को राक्षस, असुर या दैत्य कहा गया है जो समाज एवं राष्ट्र में तरह-तरह से कोरोना महामारी को फैलाने में जुटे हैं। असल में इस तरह की दानवी सोच वाले लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। ऐसे लोग धन-संपत्ति आदि के जरिए सिर्फ अपना ही उत्थान करना चाहते हैं, भले ही इस कारण दूसरे लोगों और पूरे समाज ही मौत के मुंह में जा रहे हो, यह मानवीय संवेदनाओं के छीजने की चरम पराकाष्ठा है। विभिन्न राजनीतिक दल एवं लोग प्रधानमंत्री एवं सरकारों को गाली दे रहे हैं, लेकिन, जो 700- 800 का ऑक्सीमीटर 3000. में बेच रहे, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो रेमडेसीविर को 20000. प्लस में बेच रहे हैं, जो श्मशान की लकड़ियों में बेईमानी कर रहे हैं, नारियल पानी हो या फल, सब्जी, अंडा, चिकन, दाल में लूट करने से लेकर अस्पतालों में बेड दिलाने तक का झांसा देने वाले लोगों ने ही कोरोना को फैलाया है। यह कैसी विडम्बना एवं विसंगतिपूर्ण दौर है जिसमें जिसको जहां मौका मिला वह लूटने में लग गया, यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ तब तक ही ईमानदार है जबतक उसको चोरी करने का या लूटने का मौका नहीं मिलता।

देश में कोरोना महामारी महासंकट बन असंख्य लोगों की जान ले रहा है, तब दवाइयों और इंजेक्शनों के तमाम जमाखोर सक्रिय हो गये हैं। इस जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिशें सफल होती नजर नहीं आ रही हैं। संकट में पड़े अपनों का जीवन बचाने के लिये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी आतुरता का फायदा उठाने के लिये आपदा में अवसर ढूंढ़ने वाले मनमाने दाम वसूल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कई जगह जीवनरक्षक इंजेक्शनों की जगह नकली इंजेक्शन तैयार करने की खबरें आ रही हैं। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कालाबाजारी के इन गोरखधंधों में कुछ दवा निमार्ताओं और डॉक्टरों तक की गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन इस कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाने की कोशिशें सफल होती नजर नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी कालाबाजारी पर नियंत्रण करने वाले विभागों व पुलिस को इंसानियत के ऐसे दुश्मनों की कारगुजारियों की भनक न हो। मगर, समय रहते ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन दरिन्दों एवं कालाबाजारियों की शक्ति एवं संगठन ज्यादा ताकतवर है, यही इस देश की बड़ी त्रासदी एवं विडम्बना है।

दुर्भाग्य देखिये कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने गये एक मरीज को कुछ लोगों ने अग्निशमन में काम आने वाले सिलेंडर बेच दिए। महिला की शिकायत के बाद दो युवकों की गिरफ्तारी हुई। कुछ इंसान चंद रुपयों के लालच में किस हद तक गिर जाते हैं कि संकट में फंसे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने पर उतारू हो जाते हैं। जाहिर-सी बात है कि महामारी का जो विकराल एवं वीभत्स रूप हमारे सामने है, उसमें ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत स्वाभाविक है। लेकिन यह किल्लत इसलिये सामने आयी कि स्वार्थी एवं लालची लोगों ने इसका संग्रह करना एवं मनमाने दामों में बेचना शुरू कर दिया। यह पहली बार है कि मरीजों को जीवनदायिनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत इतनी बड़ी मात्रा पर हुई हो। दरअसल, मांग व आपूर्ति के संतुलन से चीजों की उपलब्धता होती है। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग सितंबर के बाद जनवरी तक न के बराबर हो गई थी, इसलिए कंपनियों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया था। अब अचानक महामारी के फैलने के बाद मांग बढ़ने से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे इसकी कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है।

हम कितनें लालची एवं अमानवीय हो गये हैं,

हमारी संवेदनाओं का स्रोत सूख गया है, तभी तो लॉकडाउन की खबर सुनते ही गुटके की कीमत 5 से 7 कर देते हैं, तभी शराब की दुकानों पर लम्बी कतारे लग जाती है, तभी डॉक्टरों द्वारा विटामिन सी अधिक लेने की कहने पर 50 रुपये प्रति किलो का नींबू 150 रुपये प्रति किलो बेचने लगते हैं, तभी 40-50 रुपए का बिकने वाला नारियल पानी 100 का बेचने लगते हैं, तभी ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करनी शुरू कर देते हैं, तभी अपना ईमान बेच कर इंजेक्शन में पैरासिटामोल मिलाकर बेचने लगते हैं, डेड बॉडी लाने के नाम पर पानीपत से फरीदाबाद तक के 36000 मांगने लगते हैं, तभी मरीज को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नोएडा स्थित किसी हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात करते हैं तो एंबुलेंस का किराया 10 से 15 हजार मांगने लगते हैं, क्या वास्तव में हम बहुत मानवीय हैं या लाशों का मांस नोचने वाले गिद्ध? गिद्ध तो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है पर हम तो अपनी तिजोरियां भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे ऐसी दौलत या फिर किसके लिए?

यह कैसी मानवीयता है?

अस्पतालों में बेड, दवाइयां और वेंटिलेटर नहीं हैं, क्योंकि इस महासंकट में मनुष्य का एक घिनौना, क्रूर एवं अमानवीय चेहरा इनकी कालाबाजारी कर रहा है। एक तो नई महामारी का कोई कारगर इलाज नहीं है, दूसरा इस बीमारी में काम आने वाली तमाम जरूरी दवाइयां लालची लोगों ने बाजार से गायब कर दी हैं। यह बीमारी इन राक्षसों के कारण ही बेकाबू हुई है। सरकारें इन त्रासद स्थितियों एवं बीमारी पर नियंत्रण पाने में नाकाम साबित हुई है। देश के लाखों लोग कातर निगाहों से शासन-प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि कोई तो राह निकले। सरकार का व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर होता दिख रहा है। हमारे पास न तो पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता है और न ही उपलब्ध ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की कारगर व्यवस्था। इस महामारी में किसी हद तक शुरूआती दौर के उपचार में कारगर बताये जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर भारी कालाबाजारी की जा रही है। जीवन के संकट से जूझ रहे मरीजों से इनके मुंहमांगे दाम वसूले जा रहे हैं। मरीजों से पचास हजार से लेकर एक लाख तक की कीमत वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं। बड़े निजी अस्पताल भी अवसर की गंभीरता को देखते हुए नोट छापने की मशीन बने हैं। सरकारी अस्पतालों पर वीवीआईपी का कब्जा है। आम आदमी जाए तो कहां जाये?

विश्व को श्रेष्ठ, नैतिक एवं मानवीय बनने का उपदेश देने वाला देश आज कहां खड़ा है? आज इन मूल्यों एवं संवेदनाओं की दृष्टि से देश कितना खोखला एवं जर्जर हो गया है, कोरोना महामारी ने इसे जाहिर किया है। कोरोना महामारी ऐसी ही दूषित सोच एवं अपवित्र जीवन की निष्पत्ति है। कोरोना महामारी से मुक्ति की सुबह तभी होगी जब मानव की कुटिल चालों एवं दूषित आर्थिक सोच से मानवता की रक्षा की जाएगी। ऐसा करने की आवश्यकता कोरोना महामारी ने भलीभांति समझायी है। आज भौतिक एवं स्वार्थी मूल्य अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुके हैं कि उन्हें निर्मूल करना आसान नहीं है। मनुष्य का संपूर्ण कर्म प्रदूषित हो गया है। सारे छोटे-बड़े धंधों में अनीति प्रवेश कर गई है। यदि धर्म, प्रकृति एवं जीवन मूल्यों को उसके अपने स्थान पर सुरक्षित रखा गया होता तो कोरोना महाव्याधि की इतनी तबाही कदापि न मचती। संकट इतना बड़ा न होता।

समाज की बुनियादी इकाई मनुष्य है। मनुष्यों के जुड़ने से समाज और समाजों के जुड़ने से राष्ट्र बनता है। यदि मनुष्य अपने को सुधार ले तो समाज और राष्ट्र अपने आप सुधर जायेंगे। इसलिए परोपकार, परमार्थ की महिमा बताई गई है, निज पर शासन फिर अनुशासन का घोष दिया गया है। मनुष्यों के जीवन और कृत्य के परिष्कार के लिए उससे बढ़कर रास्ता हो नहीं सकता। अगर मनुष्य का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग एवं संयम आदि पर आधारित होगा तो वह अपने धंधे में किसी प्रकार की बुराई नहीं करेगा और न जीवन में विसंगतियों की धुसपैठ होने देगा। जीवन एवं कर्म की शुद्धता ही कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण की आधार-शिला है।

भारत में तेजी से कोरोना महामारी का दायरा बढ़ता जा रहा है, दवाओं व ऑक्सीजन की कालाबाजारी एक कलंक बनकर उभरा है। निस्संदेह यह संकट जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे में सरकारों को दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी। कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर सख्ती की भी जरूरत है। साथ ही संकट को देखते हुए तमाम चिकित्सा संसाधन जुटाने की जरूरत है।

महिलाओं की आजादी छीनने की कोशिशें और त्रासदीपूर्ण घटनाएं

कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के दौर में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार और रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ा और इसके साथ-साथ घर में कैद की स्थिति में असंतुलन, आक्रामकता एवं तनावपूर्ण रहने की नौबत आई। जाहिर है, यह दोतरफा दबाव की स्थिति थी, जिसने जीवन में अनेकानेक बदलावों के साथ व्यवहार में निराशा, हताशा और हिंसा की मानेवृत्ति को बढ़ाया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों से मारपीट, उनकी प्रताड़ना, अपमान आदि की घटनाएं बढ़ी। पति-पत्नी और पूरा परिवार लम्बे समय तक घर के अंदर रहने को मजबूर हुआ, जिससे जीवन में ऊब, चिड़चिडापन एवं वैचारिक टकराव कुछ अधिक तीखे हुए और महिलाओं एवं बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ीं।

इन नये बने त्रासद हालातों की पड़ताल करने के लिये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से देश के बाईस राज्यों और केंद्र प्रदेशों में एक अध्ययन कराया गया जिसमें घरेलू हिंसा के बीच महिलाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर जो तस्वीर उभरी है, वह चिंताजनक है और हमारे अब तक के सामाजिक विकास पर सवालिया निशान है। महिलाओं की आजादी छीनने की कोशिशें और उससे जुड़ी हिंसक एवं त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने बार-बार हम सबको शर्मसार किया है। भारत के विकास की गाथा पर यह नया अध्ययन किसी तमाचे से कम नहीं है। इस व्यापक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में तीस फीसद से ज्यादा महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। सबसे बुरी दशा कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार में है। कर्नाटक में पीड़ित महिलाओं की तादाद करीब पैंतालीस फीसद और बिहार में चालीस फीसद है। दूसरे राज्यों में भी स्थिति इससे बहुत अलग नहीं है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं में तेज इजाफा होने की आशंकाएं भावी पारिवारिक संरचना के लिये चिन्ताजनक है। संयुक्त राष्ट्र भी कोरोना महाव्याधि के दौर में महिलाओं और लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में ह्यभयावह बढ़ोतरीह्न दर्ज किये जाने पर चिंता जता चुका है। यह बेहद अफसोसजनक है कि जिस महामारी की चुनौतियों से उपजी परिस्थितियों से पुरुषों और महिलाओं को बराबर स्तर पर जूझना पड़ रहा है, उसमें महिलाओं को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ी है। कोरोना की पूर्णबंदी खुलने के बाद भी ऐसी घटनाएं चिंताजनक स्तर पर कायम रहना एक गंभीर स्थिति है। इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी, रोजगार और कामकाज का बाधित होना या छिन जाना था। महानगरीय जीवन में तनाव और हिंसा की स्थितियां सामान्यतया देखी जाती हैं। इसकी वजहों के कई कारण हैं। आर्थिक तंगी की वजह से कई लोग अपने भीतर का तनाव परिवार के सदस्यों पर निकालते हैं। महिलाएं और बच्चे उनका आसानी से शिकार बनते हैं। इसके अलावा महात्वाकांक्षाएं भी एक वजह है, जिसके चलते महानगरीय चमकदमक में कई लोग सपने तो बड़े पाल लेते हैं, पर जब वे पूरे होते नहीं दिखते तो उसकी खीझ पत्नी और बच्चों पर निकालते हैं। पूर्णबंदी के दौरान बालविकास मंत्रालय ने घरेलू हिंसा रोकने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों को और बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन सरकारी प्रयासों के अलावा जन सोच को बदलना होगा।

एक टीस से मन में उठती है कि आखिर घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? नारी एवं मासूम बच्चों पर हिंसा का यह कहर क्यों बरपाया है? पतियों की हिंसा से बच

भी जाये तो बलात्कार, छेड़खानी एवं सामाजिक विकृतियों की आग में वह भस्म होती है। हम भले ही समाज के अच्छे पहलुओं की चर्चा कर लें, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि महिलाओं के प्रति आम सामाजिक नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। बल्कि कई बार घरेलू हिंसा तक को कई बार सहज और सामाजिक चलन का हिस्सा मानकर इसकी अनदेखी करके परिवार के हित में महिलाओं को समझौता कर लेने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में घरों की चारदिवारी में पलती हिंसा एक संस्कृति के रूप में ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है। महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अन्याय, अत्याचारों की एक लंबी सूची रोज बन सकती है। न मालूम कितनी महिलाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन-प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती यह कालिख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, नारी को अपमानित करते हैं, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। दरअसल, यह एक सामाजिक विकृति है, जिससे तत्काल दूर करने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है, जब सरकारों की नीतिगत प्राथमिकताओं में सामाजिक विकास और रूढ़ विचारों पर नजरिया और मानसिकता बदलने का काम शामिल हो। माना जाता है कि जिन समाजों में शिक्षा का प्रसार ठीक से नहीं हुआ है, उन्हीं में महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार अधिक होता है। मगर यह धारणा अनेक घटनाओं से गलत साबित हो चुकी है। पढ़े-लिखे और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में भी महिलाएं न तो सुरक्षित हैं और न उन्हें अपेक्षित सम्मान हासिल है।

कोरोना संक्रमण के दौरान ही नहीं बल्कि भारत में पिछले कुछ सालों में घर से लेकर सड़क और कार्यस्थल तक महिलाओं के उत्पीड़न एवं हिंसा का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना है। मीटू आंदोलन ने इसे और ऊंचाई दी है और खासकर कामकाजी दायरे में यौन शोषण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। लेकिन गौर करने की बात है कि अभी सारी बहस महिलाओं के सार्वजनिक जीवन को लेकर ही हो रही है। महिलाओं की घरेलू हिंसा के बारे में तो अभी बात शुरू भी नहीं हुई है कि घर के भीतर उन्हें कैसी त्रासद एवं हिंसक घटनाओं को झेलना पड़ रहा है। इस विषय पर चर्चा शायद इस लिए भी नहीं होती कि भारत में घर को एक पवित्र जगह के तौर पर देखा जाता है और इसके भीतरी माहौल को सार्वजनिक चर्चा के दायरे में लाना मयार्दा के खिलाफ समझा जाता है। पुरुष-प्रधान समाज को उन आदतों, वृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं एवं कट्टरताओं को अलविदा कहना ही होगा जिनका हाथ पकड़कर वे उस ढ़लान में उतर गये जहां रफ्तार तेज है और विवेक अनियंत्रित हैं जिसका परिणाम है नारी एवं बच्चों पर हो रही घरेलू हिंसा, नित-नये अपराध और अत्याचार। पुरुष-प्रधान समाज के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर-तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार-बार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी महिलाओं को घर से लेकर कामकाज तक के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की वंचनाओं, विकृत सोच और भेदभावों का शिकार होना पड़ता है। यह रवैया आगे बढ़ कर हिंसा की अलग-अलग शक्ल में सामने आता है, जिसे समाज में अघोषित तौर पर सहज माना जाता है।

इस मामले पर चिंता तो लगातार जताई जाती रही है, लेकिन आज भी ऐसी संस्कृति नहीं विकसित की जा सकी है, जिसमें महिलाएं अपने अधिकार और गरिमा के साथ सहजता से जी सकें। विडंबना यह है कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं को इस तरह की घरेलू हिंसा से कोई खास शिकायत भी नहीं है। मतलब यह कि उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्यों?

घर-आंगन में पिस रही औरतों के अधिकार का प्रश्न बीच में एक बार उठा, जिससे निपटने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया। लेकिन उसका भी अनुपालन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि प्रायः स्वयं महिलाएं ही परिवार की मयार्दा पर आघात नहीं करना चाहतीं। फिर उन्हें यह भी लगता है कि पति के खिलाफ जाने से उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसका एक कारण पति पर उनकी आर्थिक निर्भरता होती है लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, वे भी घरेलू हिंसा कानून का सहारा नहीं लेतीं क्योंकि उन्हें यह डर सताता है कि परिवार से अलग होते ही वे न सिर्फ लंपट पुरुषों के बल्कि पूरे समाज के निशाने पर आ जाएंगी। सचाई यह है कि कोई अकेली आत्मनिर्भर महिला भी चैन से अपना जीवन गुजार सके, ऐसा माहौल हमारे यहां अभी नहीं बन पाया है। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य के लिए घरेलू हिंसा बर्दाश्त करती हैं।

हमें समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। हम बदलना शुरू करें अपना चिंतन, विचार, व्यवहार, कर्म और भाव। मौलिकता को, स्वयं को एवं स्वतंत्र होकर जीने वालों को ही दुनिया सर-आंखों पर बिठाती है। घर-परिवार में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिये जरूरी है कि एक ऐसे घर का निर्माण करे जिसमें प्यार की छत हो, विश्वास की दीवारें हों, सहयोग के दरवाजे हों, अनुशासन की खिड़कियाँ हों और समता की फुलवारी हो।

दुनिया भर में बढ़ते बाल अपराध की घटना ने सोचने पर किया मजबूर

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छात्र कि हरकत ने समाज को स्तब्ध कर दिया। 14 साल के स्कूली छात्र ने अपने ही सहपाठी को इसलिए गोली मार दी कि स्कूल में बैठने को लेकर उसका और सहपाठी का आपस में झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए घटना के दूसरे दिन अपनी स्कूल बैग में चाचा कि लाइसेंसी पिस्तौल लेकर आए छात्र ने सहपाठी को गोली मार दिया। हालाँकि बाद में स्कूल स्टॉप की तत्परता से उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन समाज में बढ़ते बाल अपराध के मनोविज्ञान ने हमें चौका दिया है।

सामाजिक बदलाव और तकनीकी विकास का मानव जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। सीखने और समझने की क्षमता भी अधिक बढ़ी है। जिसका नतीजा है अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। भारत में बाल अपराध के आंकड़ों की गति भी हाल के सालों में कई गुना बढ़ी है। जिस अपराध की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस कार्य को नाबालिक किशोरों ने कर समाज और व्यवस्था को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

निर्भया कांड में भी एक बाल अपराधी की भूमिका अहम रही थीं। बाद में जुवेनाइल अदालत से वह छूट गया था। संयुक्तराष्ट्र 18 साल के कम उम्र के किशोरों को नाबालिग मानता है। जबकि भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते बाल अपराध की घटना ने सोचने पर मजबूर किया है। जिसकी वजह है कि दुनिया के कई देशों ने नाबालिग की उम्र घटा दिया है। कई देशों में बाल अपराध की सजा बड़ों जैसी है। भारतवर्ष में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने की उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष है। इसी तरह मिश्र में 7 वर्ष से 15 वर्ष, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष तथा ईरान में 11 से 18 वर्ष है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हाल के सालों में बाल अपराध की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं।

समाज में इस तरह की घटनाएँ हमारे लिए चिंता का विषय हैं। इसे हम नजरंदाज नहीं कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में इस तरह की अनगिनत घटनाएँ हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बड़ी बात है। यह घटना साफ तौर पर इंगित करती है हम किस सामजिक बदलाव की तरफ बढ़ रहें हैं। हम असहिष्णु समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी में संवाद, संयम और सहनशीलता, धैर्य, क्षमा का अभाव दिखने लगा है। 14 साल की उम्र भरतीय समाज में विशेष रुप से सीखने की होती उस उम्र के किशोर प्रयोगवादी कहाँ से हो गए हैं। हम समाज और आने वाली पीढ़ी को कौन सा महौल देना चाहते हैं। 14 साल की उम्र का नाबालिग किशोर पिस्तौल में गोली भरना और ट्रिगर दबाना कैसे सिख गया ? यह सब तकनीकी विकास और पारिवारिक महौल पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

संवेदनशील आग्नेयास्त्र बच्चों कि पहुँच तक घर में कैसे सुलभ हो गए। इस तरह के शस्त्र क्या बच्चों की पहुँच से छुपा कर रखने की वस्तु नहीं हैं। फिर इस शस्त्र को घर में इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों रखा गया था। नाबालिग किशोर उस आग्नेयास्त्र तक कैसे पहुँच गया। छात्र के बैग में टिफिन रखते वक्त क्या माँ ने उसका स्कूल बैग चेक नहीं किया। जिस चाचा की

पिस्तौल लेकर वह किशोर स्कूल गया था वह सेना में कार्यरत बताया गया है। अवकाश पर घर आया था, फिर क्या यह उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती थीं कि इस तरह के शस्त्रों को बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाय।

निश्चित रुप से हम समाज में जिस महौल को पैदा कर रहें हैं वह हमारे लिए बेहद दुखदायी है। इंसान खुद को टाइम मशीन बना लिया है। वह बच्चों, परिवार, समाज और समूह पर अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पा रह है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती तो सम्भवतः इस तरह के हादसे को टाला जा सकता था। अगर उस शस्त्र को बच्चों की पहुँच से सुरक्षित स्थान पर किसी लाकर में रखा जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। इस घटना से सबक लेते हुए स्कूल प्रबंधन को भी चाहिए की बच्चे की स्कूल गेट पर हर छात्र की तलाशी ली जाय, क्योंकि अपराध किसी चेहरे नहीं लिखा है। स्कूलों में मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाने चाहिए।

हमने मासूम बच्चों पर स्कूली किताबों का बोझ अधिक लाद दिया है। पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की होड़ में किशोरवय अल्हड़ता को छीन लिया है। आधुनिक जीवन शैली ने सामाजिक परिवेश को जरूरत से अधिक बदल दिया है। हम प्रतिस्पर्धी जीवन में बच्चों और परिवार पर समय देना बंद कर दिया है। जिसकी वजह से बच्चों में एकांकीपन बढ़ रहा है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है। परिवार नाम की संस्था और नैतिकमूल्य की उनमें समझ नहीं पैदा होती। उन्हें समाज, परिवार जैसे संस्कार ही नहीं मिल पाते। शहरों में माँ- बाप के कामकाजी होने से यह समस्या और बड़ी और गहरी बन जाती है। क्योंकि इस तरह के परिवार में बच्चों के लिए समय ही नहीं बचता है। स्कूल से आने के बाद बच्चों पर टयूशन और होमवर्क का बोझ बढ़ रहा है। माँ- बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। दादा-दादी का तो वक्त खत्म हो चला है, नहीं तो कम से कम शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन होता था।

समाज में इस तरह की घटनाएँ हमारे लिए चिंता का विषय हैं। इसे हम नजरंदाज नहीं कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में इस तरह की अनगिनत घटनाएँ हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बड़ी बात है। यह घटना साफ तौर पर इंगित करती है हम किस सामजिक बदलाव की तरफ बढ़ रहें हैं। हम असहिष्णु समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी में संवाद, संयम और सहनशीलता, धैर्य, क्षमा का अभाव दिखने लगा है। 14 साल की उम्र भरतीय समाज में विशेष रुप से सीखने की होती उस उम्र के किशोर प्रयोगवादी कहाँ से हो गए हैं। हम समाज और आने वाली पीढ़ी को कौन सा महौल देना चाहते हैं।

मनोचिकित्सक मानते हैं कि किशोरों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के पीछे अभिभावकों भी हैं। क्योंकि बच्चों पर वे उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी वजह कई परिवारों में माता-पिता में आपसी संबंध सही न होने से बच्चों को समुचित समय नहीं मिल पाता है। किशोरों द्वारा हिंसक वीडियो गेम खेलने से भी उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से उनमें हिंसक प्रवृति बढ़ती है।

किशोरों में सांवेगिक नियंत्रण की कमी होती है और वे फैसले अपने संवेग के आधार पर लेते हैं। डा.तिवारी के अनुसार किशोरवय के साथ हम क्रोध के बजाय मित्रवत व्यवहार करें। उनके साथ साथ खेलें और बातचीत करें। उन्हें अधिक समय तक मोबाइल एवं टेलीविजन के साथ अकेले न छोड़े। बच्चों को अकेले बहुत अधिक समय व्यतीत न करने दें। बच्चे के व्यवहार में किसी भी तरह के असामान्य परिवर्तन होने पर उसके कारणों को जानने का प्रयास करें और संभव हो तो मनोवैज्ञानिक परामर्श लें। हालाँकि कोरोना काल में स्थितियां बदली हैं। वर्क फ्रॉम होम और स्कूली की तालाबंदी होने से अभिभावकों ने बच्चों को काफी वक्त दिया है। कोविड- 19 से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका भले लगा हो, लेकिन परिवार नाम की संस्था का मतलब लोगों के समझ में आ गया है। इसके पूर्व शहरी जीवन में बच्चों को बड़ी मुश्किल से रविवार उपलब्ध हो पाता था। जिसमें माँ- बाप बच्चों के लिए समय निकाल पाते थे, लेकिन कोरोना परिवार नामक संस्था को मजबूत किया है। बुलंदशहर की घटना हमारे लिए बड़ा सबक है। हमें बच्चों के लिए समय निकालना होगा। किताबी ज्ञान के इतर हमें पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा भी बच्चों देनी होगी।

किशोर उम्र बेहद नाजुक होती है यह अपनी दिशा तेजी से तय करती है। आपका बच्चा स्कूल और कालेज जा रहा है तो वहाँ क्या कर रहा है उसकी निगरानी भी आपको करनी है। बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखें। बच्चों की स्कूल बैग टिफिन के बहाने देखें। स्कूल बैग में अगर कोई भी ऐसी वस्तु तो नहीं रखी है जिससे उसके बुरे व्यवहार का पता चलता हो। बच्चों को समय दें और शाम को स्कूली दिनचर्या के बारे में जानकारी लें। स्कूल और टयूशन शिक्षक से भी सम्पर्क बनाएं रखें। इन सब बातों से आप उसकी गतिविधियों पर नजर रख कर माँ- बाप के रुप में एक नैतिक शिक्षक आप खुद बन सकते हैं और बच्चों में बढ़ते अपराध की प्रवित्ति को नियंत्रित कर सकते हैं।

पारंपरिक औषधि का वैश्विक-केंद्र बनता भारत

दुनिया की फामेर्सी के बाद भारत वैश्विक आरोग्य का केंद्र भी बनकर दिखा सकता है ये कल्पना मात्र नहीं, बल्कि अब ये घोषित सत्य बन चुका है . पारंपरिक औषधि का वैश्विक-केंद्र के रूप में भारत के चुनाव की ये घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेडरोज ऐडहानाम नें भारत को विडियो के माध्यम से भेजे अपने सन्देश में उस समय की जब ५वें आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी नें भविष्य में तैयार होने वाले जयपुर और जामनगर में स्थित दो आयुर्वेदिक संस्थानों का विडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया.पिछले साल की तुलना में इस साल सितम्बर में आयुर्वेदिक-उत्पादों का निर्यात ४५% बढ़ा है, जो ये समझने के लिए काफी है कि आयुर्वेद पर दुनिया के देशों नें कितना भरोसा दिखाया है. और यही कारण है कि जिसका परिणाम डब्लू एच ओ की इस घोषणा के रूप में सामने आया है.

दुनिया भर में पायी जाने वाली जड़ी-बूटीयों में आधे से अधिक भारत में पैदा होतीं हैं. लेकिन इसकी सही मायने में सुध तभी जाकर ली गयी, जब सन २००० में अटल बिहारी की एनडीऐ सरकार नें पहली बार भारतीय चिकत्सा पद्धतियों के लिए अलग से राष्ट्रीय नीति बनायी. जिसके अंतर्गत आयुर्वेद तथा यूनानी चिकत्सा पद्धति को हरित उद्धोग की श्रेणी में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया गया. और तभी जाकर आंवला, अश्वगंधा, चन्दन आदि आयुर्वेद में उपयोग होने वाली जड़ी-बूटीयों को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नें पहली बार उनके संरक्षण-संवर्धन को लेकर योजना बनाने पर ध्यान देना शुरू किया. और अटलजी की सरकार के दौरान ही कोच्ची[केरल] में प्रथम विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन व हर्बल मेला आयोजित कर दुनिया को बताया कि उसके पास उसे देने को उसकी अपनी क्या बेमिसाल निधि है. इस आयोजन में अमेरिका, स्विट्जरलैंड दक्षिण अफ्रीका,डेनमार्क, केनेडा समेत दुनिया के ५० देशों के २५०० प्रतिनिधियों नें बढ़चढ़कर भाग लिया था. कोरोना के इस काल में निराश मानव जाति के लिए आयुर्वेद नयी आशा की किरण लेकर आया है. यहाँ तक कि देश की सीमा लांघ विदेश तक में अब इसने सुर्खियाँ बटोरना शुरू कर दिया है-ह्य कोरोना वायरस टोंसिल से फेफड़े में पहुंचकर शरीर में तेजी से फैलता है. हल्दी और चूना मिलकर विषनाशक बन जाते हैं.शरीर में फ्री रेडिकल्स और यूरिक एसिड नहीं बन पता, जिससे लंग्स समेत अन्य अंगों में सूजन नहीं आती.दोनों औषधि[हल्दी-चूना] प्रतिरोधक-क्षमता बढ़ाती हैं, जो कोरोना मरीज को देने से सिद्ध भी हुआ है . अमेरिका के मेडिकल जर्नल में इस पर शोध छपा है.यह शुगर समेत कई अन्य बीमारियों का भी इलाज है.ह्न-डॉ देवदत्त भाद्लीकर,आयुर्वेद प्रोफेसर, और हल्दी-चूने से रोगों के उपचार की विधि के विशेषज्ञ. पंचभौतिक [धरती,अग्नि,जल,वायु और आकाश]अवधारणा पर आधारित आयुर्वेद में मनुष्य

जीवन के भौतिक व अध्यात्मिक दोनों ही पक्षों का संतुलित विचार होता है. इसलिए इसके अंतर्गत होने वाले उपचार में स्वास्थ शरीर के साथ-साथ मन के निग्रह व आत्मा के उत्थान को भी ध्यान रखा जाता है. और, इसी कारण से योगासन को आयुर्वेद से जोड़ा गया है. महर्षि सूश्रूत नें स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या ऐसे व्यक्ति से की है जिसके शरीर त्रिदोष वात, पित, कफ संतुलित अवस्था में हों, प्राणभूत द्रव पदार्थ सामान्य अवस्था में हों और साथ ही आत्मा, मन, और इन्द्रिय शांत अवस्था में हों . यही आयुर्वेद का एकात्म दृष्टिकोण है. सम्पूर्ण रोग-प्रतिरोधक क्षमता [आरोग्य]को प्राप्त करने में शाकाहार की बड़ी भूमिका है, जिसे आयुर्वेद नें प्रधानता से स्वीकारा है. दूसरी ओर गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च में निहित इम्युनिटी बढ़ाने के गुणों से दुनिया अब अनजान नहीं, इसी के कारण से आज आयुर्वेदिक औषधियां के निर्यात में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आज लगभग ९० देशों में आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने वालों की अच्छी-खासी संख्या है. आयुर्वेद के द्वारा देश को प्राप्त इस गौरव के पीछे एनडीए सरकार की भूमिका को सदेव स्मरण किया जाता रहेगा. जब केंद्र में नरेंद्र मोदी नें सत्ता संभाली तो आयुर्वेद को पृथक आयुष मंत्रालय मिला. प्रधान मंत्री विदेश में जहां भी गए उन्होंनें नें भारतीय पारंपरिक ओषधियों को प्रोत्साहित करने के लिए करार किये. साथ ही भारतीय दूतावासों में आयुष सूचना केंद्र भी स्थापित किये.